

ड्रोन के खतरों से निपटने की क्षमता विकसित कर रही सेना : नरवणे

>>3

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 22

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

एक माह तक पास नहीं फटकेगा कोरोना वायरस



वाराणसी : म्यूटेट (परिवर्तित) होते कोरोना वायरस के कारण विज्ञानी सैनिटाइजर को भी अपडेट कर रहे हैं। आइआइटी हैदराबाद में नैनो टेक्नोलाजी पर आधारित किफायती, लेकिन लंबे समय तक प्रभावी सैनिटाइजर और अन्य स्वच्छता (हाइजीन) उत्पाद बनाए गए हैं। (पेज-14)

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▶ पृष्ठ 2

येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी ने संभाली

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पहली बार येलो लाइन पर मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी को सौंप दी है। एजेंसी द्वारा नियुक्त 70 चालकों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण डीएमआरसी ने यह कदम उठाया है। फिलहाल येलो लाइन पर तीन साल के लिए मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी गई है।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

नीरव मोदी की बहन ने भारत सरकार को भेजे 17.25 करोड़

नई दिल्ली : ईडी ने गुरुवार को बताया कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन स्थित बैंक अकाउंट में जमा 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। पूर्वी पीएनबी लोन घोटाले में सरकारी गवाह बन चुकी है। पूर्वी व उसके पति मयंक मेहता को मुंबई स्थित प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने मामले की सच्चाई सामने लाने व जांच में ईडी का सहयोग करने की शर्त पर क्षमादान की स्वीकृति दी है।

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

चुनाव बाद हिंसा पर बंगाल, केंद्र व निर्वाचन आयोग को नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीछे के कारणों की जांच कराए जाने और दोषियों को सजा देने की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा खासतौर पर उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति पर केंद्र को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दिया जाए।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

गर्मी ने निकाला पसीना, लू के लग रहे थपेड़े

नई दिल्ली : देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी व लू का दौर अभी दो दिन और परेशान करता रहेगा। रविवार से जरूर तापमान में थोड़ी कमी आने लगेगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी कहीं-कहीं कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन मानसून की स्थिति में अभी एक सप्ताह तक कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। यानी जहां है वहीं बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है।

भारतीय टीका लेने वाले जा सकेंगे नौ यूरोपीय देश

रंग लाई कोशिश ▶ एक दिन पहले ही भारत ने ईयू को दी थी चेतावनी

कोविशील्ड लगवाने वाले इन देशों में बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूरोपियन यूनियन की तरफ से डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट नियम को लेकर भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया था उसका सकारात्मक असर होता दिख रहा है। भारत के रुख को देखते हुए नौ यूरोपीय देशों ने भारत निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड को वीजा देने संबंधी दिशानिर्देश में शामिल कर लिया है। इसमें से सात यूरोपियन यूनियन (ईयू) के सदस्य हैं। एक देश एस्टोनिया ने भारत बायोटेक की तरफ से निर्मित कोवैक्सीन को भी वीजा देने संबंधी नियम में शामिल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले भारतीय या किसी दूसरे देश के नागरिकों को इन देशों में आने जाने की सहूलियत होगी। इन देशों के नाम हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी, सोलेवानिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन व स्टोनिया। स्विट्जरलैंड हालांकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है।

भारत ने एक दिन पहले ही परोक्ष तौर पर यूरोपीय देशों को चेतावनी दी थी कि उनके वीजा कार्यक्रम ग्रीन पास (डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट) के तहत भारतीय वैक्सीन को शामिल नहीं किया जाएगा तो उनके नागरिकों को भी यहां आने पर आवश्यक तौर पर क्वारंटाइन में रहना होगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि ईयू के देशों को अलग-अलग बताया गया कि अगर वो भारतीय वैक्सीन लेने वालों को अपने वीजा सर्टिफिकेट कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो भारत भी कोविड वैक्सीन लेने वाले उनके नागरिकों के लिए बिना क्वारंटाइन हुए आने की इजाजत देगा।

नए नियम में भारतीय वैक्सीन को नहीं किया था शामिलः इस हफ्ते की शुरुआत में ईयू की तरफ से जो नया नियम बनाया गया था उसमें भारतीय वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया था। बाद में भारत के विरोध पर ईयू ने तर्क दिया कि भारतीय वैक्सीन निर्माता ने इस संबंध में उसके समक्ष 28 जून तक कोई आवेदन ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में ईयू के सदस्य देश अपने अपने स्तर पर कोविशील्ड या दूसरी भारतीय वैक्सीन को अनुमित दे सकते हैं। यूरोपीय देशों के बीच आवागमन में डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क पहली जुलाई से लागू हुआ है।

इन्हें दी छूट : इस फ्रेमवर्क में फाइजर, माडर्ना, एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन को शामिल किया गया है। इन सभी वैक्सीन को यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी (ईएमए) से मंजूरी दी गई है। ये वैक्सीन लेने वालों को ईयू के भीतर आने-जाने की छूट होगी, जबकि भारत निर्मित वैक्सीन को ईएमए से मंजूरी नहीं मिली।

- एस्टोनिया ने कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी छूट के दायरे में रखा
- भारत ने कहा था, हमें छूट न दी तो यूरोप से आने वाले क्वारंटाइन होंगे



कोरोना महामारी से जंग में वैक्सीन सबसे अहम हथियार है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

भारत ने रखा था बराबरी का प्रस्ताव

यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड व कोवैक्सीन को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किए जाने से उपजी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 'गिव एंड टेक' फार्मूले का प्रस्ताव किया था। यानी यूरोपियन यूनियन भारत की वैक्सीन को वहां आने जाने के लिए प्रमाणित करती है तो भारत भी डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को वीजा देने में प्राथमिकता देगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले यूरोपीय नागरिकों को भारत में क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। भारत ने यह प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी देशों को अलग-अलग भी भेजा था, जिसकी प्रतिक्रिया में नौ देशों ने कोविशील्ड लेने वालों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।

एक और स्वदेशी वैक्सीन तैयार

जायडस कैडिला ने जायकोवी-डी के आपात इस्तेमाल की मांगी अनुमति

नई दिल्ली, एएनआइ : कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे और तीसरी लहर से आशंकित देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि देश की एक स्वदेशी वैक्सीन बाजार में जल्द आने को तैयार है। जायकोवी-डी नाम की यह वैक्सीन दिग्गज फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने तैयार की है। तीन डोज वाली डीएनए आधारित यह वैक्सीन 12 से 18 साल उम्र के बच्चों समेत सभी लोगों पर कारगर है। यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। कंपनी ने हर महीने एक करोड़ डोज का उत्पादन करने की उम्मीद जताई है।

जायडस कैडिला ने गुरुवार को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआइ) से अपनी जायकोवी-डी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। कंपनी ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। जायकोवी-डी डीएनए आधारित वैक्सीन है। इसमें कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड है जो टीका लगवाने वाले के शरीर में इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है, जबकि भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है, जिसने आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है।

इससे पहले, एक सरकारी सूत्र ने कहा था जायडस कैडिला ने सरकार से कहा है कि वह अगले सात-आठ दिनों में जायकोवी-डी वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकती है।

वहीं, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल भी पहले कह चुके हैं कि जायडस कैडिला ने अपने तीसरे चरण के अध्ययन के लिए 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों को नामांकित किया है।



जायडस कैडिला के प्रबंध निदेशक शार्विल। एएनआइ

उपलब्धि

- दिग्गज फार्मा कंपनी ने वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा किया
- इस वैक्सीन के तीन डोज लेने होंगे
- 12 से 18 साल के बच्चों को भी लगाया जा सकेगा यह टीका



66 फीसद से अधिक कारगर है वैक्सीन

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार जायडस कैडिला के प्रबंध निदेशक शार्विल पटेल ने बताया कि अंतरिम अध्ययन में उनकी वैक्सीन जायकोवी-डी 66.6 फीसद कारगर पाई गई है। उन्होंने हर महीने एक करोड़ डोज का उत्पादन करने की उम्मीद जताई है। पटेल ने कहा कि यद्यपि देश में अप्रैल-मई की अपेक्षा कोरोना के मामलों में काफी कमी है लेकिन संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हम देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराने पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी वैक्सीन को अनुमति मिलने से देश में पांच वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी। कंपनी की ओर से यह भी बताया कि तीसरे चरण में जिन 28,000 लोगों पर परीक्षण किया गया उनमें 12 से 18 साल के 1,000 बच्चे भी शामिल थे। इनका इम्यूनोजेनिसिटी (प्रतिरक्षाजनकता) डाटा चार से छह सप्ताह के भीतर सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। कंपनी ने बताया कि उसकी वैक्सीन का परीक्षण उस समय चल रहा था जब देश में दूसरी लहर चरम पर थी। ऐसी सूरत में उनकी वैक्सीन अन्य वैरिएंट के साथ डेल्टा वैरिएंट पर भी कारगर है।

यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन होगी पेज>>6

आरक्षण के लिए राज्य नहीं तय कर सकते सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें शीर्ष अदालत से पांच मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियों और दाखिलों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की घोषणा करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं रही है, जबकि केंद्र ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि राज्यों को अपने यहां निश्चित रूप से ऐसा करने का अधिकार है।

जस्टिस अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस. रवींद्र की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'हमने पांच मई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया है... पुनर्विचार याचिका का जो आधार बताया गया है, वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता जिसकी बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सके।' पीठ ने कहा, 'हमें पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई पर्याप्त आधार दिखाई नहीं देता। पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।' गुरुवार को अपलोड आदेश के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने मामले की खुली अदालत में सुनवाई के केंद्र के आवेदन को भी खारिज कर दिया।

इस मामले पर पांचों न्यायाधीशों ने 28 जून को 'चैंबर' में विचार किया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि जस्टिस भूषण चार जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद होने वाली रस्मों में शामिल होने के लिए बुधवार को ही शीर्ष अदालत से विदाई ले ली थी। पिछले हफ्ते उनकी मां का निधन हो गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 13 मई को एक बयान जारी कर कहा था कि केंद्र ने शीर्ष अदालत के पांच मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को पांच मई को बहुमत से रद कर दिया था और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा तय करने संबंधी 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इन्कार कर दिया था। पीठ ने 3:2 के बहुमत वाले निर्णय में कहा था कि संविधान का 102वां संशोधन केंद्र को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की घोषणा करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि केवल राष्ट्रपति ही सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। हालांकि, पीठ के पांचों जजों ने संविधान संशोधन को वैध करार दिया था और कहा था कि इसने संघीय राजनीति को प्रभावित नहीं किया और न ही संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन किया है।

मराठा आरक्षण मामला



सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई के अपने फैसले पर पुनर्विचार की केंद्र की याचिका खारिज की

ईडी ने जब्त की अजीत पवार के करीबी रिश्तेदार की चीनी मिल

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सातारा स्थित जरंडेश्वर चीनी मिल को जब्त कर लिया है। यह चीनी मिल राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी रिश्तेदार की है। यह कार्रवाई अजीत पवार के लिए बड़ा धक्का मानी जा रही है।

पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित जरंडेश्वर चीनी मिल पहले सहकारी प्रबंधन में थी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने आने के बाद इस प्रकार की कई सहकारी चीनी मिलों के बिकने की नौबत आ गई, जिन्हें कम दाम पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों ने ही खरीद लिया। इन्हीं में से एक जरंडेश्वर चीनी मिल भी है, जिसे अजीत पवार के करीबी रिश्तेदार राजेंद्र कुमार घाडगे ने खरीदा है। इस प्रकार राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सहकारी बैंकों से बड़े-बड़े कर्ज लेकर सहकारी चीनी मिलों को डुबाने और बाद में खुद ही इन चीनी मिलों को खरीद लेने के मामले की जांच के लिए अन्ना हजारे ने मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने गुरुवार को इसी मामले में कार्रवाई करते हुए जरंडेश्वर चीनी मिल को जब्त कर लिया है।

ईडी की इस कार्रवाई के बाद अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देर से ही सही, कार्रवाई शुरू तो हुई। हम अपेक्षा करते हैं कि अब अन्य चीनी मिलों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। हमारी शिकायत के बाद इस प्रकार की बड़ी अनियमितता बाहर आई है।

वहीं, दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक से भी ईडी एक अन्य मामले में पूछताछ कर चुकी है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एवं शिवसेना कोटे से परिवहन मंत्री अनिल परब की भी ईडी से जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। प्रताप सरनाईक तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कह चुके हैं कि यदि उन्होंने भाजपा से पुनः नजदीकी नहीं बढ़ाई तो शिवसेना के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

- कर्ज में डुबोकर औने-पौने दाम में खरीदी गई थी सहकारी चीनी मिल
- अन्ना हजारे ने अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई पर खुशी जताई



बड़ा धक्का : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अब रसोई गैस महंगी हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि से पहले ही हलकान है और अब रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। एक जुलाई, 2021 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25.50 रुपये बढ़ा दी गई है।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत अब 834.50 रुपये और कोलकाता में 835.50 रुपये होगी। फरवरी, 2021 के बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई यह छठी वृद्धि है। अगर एक मई, 2020 से तुलना करें तो दिल्ली में एलपीजी के 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 253.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, इसमें पिछले छह महीने में 140 रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष रसोई गैस पर सब्सिडी देने की व्यवस्था भी बदल दी गई जिसमें सिर्फ पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली गृहणियों के बैंक खातों में ही एलपीजी की सब्सिडी आती है। देश के अधिकांश हिस्सों में रसोई गैस पर सब्सिडी अमूमन खत्म हो चुकी है।

- एक जुलाई से 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े दाम



नई दिल्ली में गुरुवार को ग्राहकों के घर सिलेंडर पहुंचाने में जुटा श्रमिक। प्रेट्र

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को बताया वजह पेज>>7

कांग्रेस में संवाद की परंपरा खत्म होने पर शिंदे ने उठाए सवाल

- हाईकमान के करीबी शिंदे का बयान पार्टी के मौजूदा संकट को लेकर बढ़ती बेचैनी का संकेत
- पूर्व गृह मंत्री ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मनिरीक्षण की दी नसीहत



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पार्टी को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लंबे समय से राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रही कांग्रेस की दुविधा और अनिर्णय की स्थिति को देखकर अब पार्टी के भरोसेमंद पुराने दिग्गजों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। पार्टी की रीति-नीति और कामकाज की शैली के खिलाफ असंतोष के बावजूद हालात को सुधारने के लिए ठोस पहल का अभाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। कांग्रेस में संवाद, बहस और बैठकों के दौर की परंपरा खत्म होने का पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का ताजा बयान नेताओं के टूटते धैर्य का ही संकेत है। पार्टी के संचालन की मौजूदा रीति-नीति पर शिंदे का सवाल उठाना इसलिए भी मायने रखता है कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान के करीबियों में गिना जाता है।

राष्ट्रीय सियासत में कांग्रेस की लगातार कमजोर पड़ रही पकड़ को लेकर अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए शिंदे ने पुणे में कहा कि यह दुखद है कि आत्मचिंतन, चर्चा-बहस, बैठकें करने की कांग्रेस की परंपरा आज खत्म हो गई है। पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। शिंदे ने कहा कि हमारी नीतियों में त्रुटि-खामियां हो सकती हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए संवाद और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है।

पार्टी की मौजूदा दशा-दिशा पर शिंदे का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस हाईकमान पर सवाल है और उनकी यह मुखरता नेतृत्व की चिंता में इजाफा करेगा। खासकर यह देखते हुए कि काफी लंबे समय से शिंदे गांधी परिवार के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते रहे हैं और संप्रग दो सरकार में गृह मंत्री के अलावा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता जैसे अहम पद पर थे। इतना ही नहीं गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने की जब भी चर्चा उठती है तब शिंदे को हाईकमान से उनकी निकटता के चलते ही इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में भी गिना जाता रहा है। इन सब के बावजूद कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर शिंदे का सवाल उठाना यह साफ संकेत है कि पार्टी की गंभीर होती चुनौतियों पर नेतृत्व की दुविधा उनके जैसे नेताओं को भी अब रास नहीं आ रही है। कांग्रेस में असंतोष की मुखर आवाज उठाने वाले जी-23 समूह के बाद पार्टी के हालात को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने वाले शिंदे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और जाहिर तौर पर उनका यह बयान हाईकमान को कहीं ज्यादा असहज करेगा।

कैप्टन के लंच से उठी पंजाब में हिंदू अध्यक्ष की मांग

चंडीगढ़ : कांग्रेस हाईकमान की ओर से सिद्धू को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेतों के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को पार्टी के प्रमुख हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया। इस दौरान हुई चर्चा के जरिये हाईकमान को संदेश देने की कोशिश की गई है कि पंजाब में पार्टी अध्यक्ष हिंदू ही होना चाहिए। (पेज-4)

गुलशन हत्याकांड में रऊफ के भाई रशीद को भी उम्रकैद

मुंबई : करीब 24 साल पहले हुए गुलशन कुमार हत्याकांड में मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'कैसेट किंग' की हत्या संगीतकार नदीम सैफी और गैंगस्टर अबू सलेम ने करवाई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अब्दुल रऊफ मर्चेंट की आजीवन कारावास की सजा तो बरकरार रखी ही, निचली अदालत द्वारा बरी किए जा चुके उसके भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन टिप्स इंडस्ट्रीज के सहसंस्थापक रमेश तौरानी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस एसएस जाधव और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इसे एक नृशंस हत्याकांड करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अब्दुल रऊफ के बारे में जो कहा है, हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। (विस्तृत खबर पेज-5)

रखी बात

पीएम ने महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए डाक्टरों की सराहना की, कोरोना काल में इलाज के अनुभवों का दस्तावेज तैयार करने की दी सलाह

योग पर वैज्ञानिक शोध बढ़ाने की जरूरत : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संक्रमण के बाद के दुष्प्रभावों से निपटने में योग की बड़ी भूमिका सामने आई है। जिस तरह से डाक्टरों ने इसे अपनाया है, इससे लोगों में भी योग के प्रति रुझान बढ़ा है। योग के प्रति दुनिया के भरोसे को और बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने के लिए डाक्टरों की सराहना की और उन्हें अपने अनुभवों को संकलित करने की सलाह दी, ताकि भविष्य में ऐसी महामारी से निपटना आसान हो सके।

योग की बढ़ती स्वीकार्यता पर पीएम ने कहा कि इसके प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक तथ्य जुटाने की जरूरत है। कई संस्थाएं ऐसे तथ्य जुटाने में लगी हैं। मोदी ने डाक्टरों द्वारा योग के प्रभावों के अध्ययन की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे दुनिया में योग के प्रति भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ऐसे अध्ययनों को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं में छपवाने की अपील भी की। डाक्टरों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाने में डाक्टरों की भूमिका इसीलिए भी अहम रही क्योंकि देश में स्वास्थ्य का पर्याप्त आधारभूत ढांचा नहीं होने और वायरस के बदलते स्वरूप के बावजूद उन्होंने लोगों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों की सेवा में जुटे कई डाक्टरों की इस दौरान संक्रमण के कारण जान भी चली गई। पीएम ने सीमित संसाधनों के बावजूद अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्युदर कम रहने का श्रेय डाक्टरों को दिया। कोरोना जैसी नई बीमारी और कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं होने के बावजूद डाक्टरों ने अपने अनुभव के आधार पर लोगों को ठीक करने में पूरी ताकत लगा दी। पीएम ने कहा कि डाक्टर इलाज के इन अनुभवों का लिखित दस्तावेज तैयार करें, जिसमें विभिन्न दवाओं के असर की विस्तृत जानकारी हो। इससे दुनिया को मेडिकल से जुड़ी कई जटिलताओं को समझने में आसानी होगी।



राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रेट्र

ये भी बोले पीएम

- डाक्टर दिवस पर सभी डाक्टरों को मेरी शुभकामनाएं। दवाओं की दुनिया में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। हमने धरती को स्वस्थ बनाने में भी भूमिका निभाई है।
- पिछले साल हमने डाक्टरों पर हमले की कई घटनाएं देखी थीं। सरकार ऐसे हर मामले में उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- 2014 में देश में सिर्फ छह एम्स थे। सात साल में 15 नए एम्स में काम शुरू हुआ है। मेडिकल कालेजों की संख्या और अंडर ग्रेजुएट की सीट डेढ़ गुना की गई है।

7026 मेगावाट पहुंच गई गुरुवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग। इससे पहले वर्ष 2018 व वर्ष 2019 में भी अधिकतम मांग सात हजार मेगावाट के ऊपर रही थी।

अपनी यमुना की मछली नहीं खा पा रहे दिल्लीवासी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

- यमुना नदी का पानी दूषित होने से यहां की मछली करीब बीस साल से बिकने के लिए मंडी में नहीं पहुंच पाई
- पहले इस नदी में 50 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां हुआ करती थीं, अब केवल कमनकार प्रजाति ही यमुना में रह गई है

देश के हर कोने की मछली का स्वाद राजधानी के लोग ले रहे हैं, लेकिन अपने ही शहर के बीच से होकर बहने वाली यमुना की मछलियों के स्वाद से वंचित हैं। तमाम नालों के दूषित पानी ने यमुना नदी को इतना जहरीला बना दिया है कि इसमें मछलियां पनप ही नहीं पा रहीं। किसी जमाने में रोहू, कतला, चीतल, सिंघाड़ा समेत 50 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां इस नदी में होती थीं, लेकिन अब महज कमनकार प्रजाति मछली ही इसमें रह गई हैं। इसके भी अधिक, अब यमुना में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि जो मछलियां यमुना में मौजूद हैं वे भी अब खाने लायक नहीं रह गई हैं। जो मछुआरे यमुना से मछली पकड़कर रेहड़ी लगाकर बेचा करते थे, अब उनका रोजगार भी छिन गया है।

यमुना से मछली पकड़ने वाले ज्यादातर मछुआरों का यह काम पुश्तैनी है। बस फर्क इतना है कि उनके पूर्वज यह काम बिना लाइसेंस के करते थे। अब की पीढ़ी लाइसेंस लेकर मछली पकड़ती है। हालांकि, ज्यादातर मछुआरों का कहना है कि यमुना में मछलियां न के बराबर हैं और बीते कुछ वर्षों से उनका पुश्तैनी कामकाज चौपट हो चुका है। ज्यादातर मछुआरे पहले से ही बेरोजगार ही हैं। अब दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से ओखला बैराज सहित यमुना के कुछ अन्य हिस्सों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगाए जाने के बाद यह संकट और गहरा गया है। यह स्थिति तब उभरी है जब यमुना की सफाई में हर साल बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। एक आरटीआइ के मुताबिक अकेले 2018 से 2021 के बीच करीब दो सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए।

यमुना की मछलियां मंडी में भले ही नहीं बिकती हों, लेकिन मदनपुर खादर, खड्डा कालोनी, मीठापुर, झंगौला गांवों के मछुआरे रेहड़ी लगाकर आसपास के लोगों को मछलियां बेचकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु से समुद्री मछली दिल्ली आती हैं। उप्र, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, पंजाब, मप्र, हरियाणा, तेलंगाना, बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र के मत्स्यपालक गाजीपुर मछली मंडी में मछली भेजते हैं। यहां पर मल्ली, रोहू, सोल, पंगास, माहसीर, कतला, तिलापिया, सिंघाड़ा, चीतल समेत सौ से ज्यादा प्रकार की मछलियां मंडी में बिकने आती हैं।

ऐसा पानी उपयुक्त

- बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड का स्तर तीन मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो
- डिजाल्व डिजाल्व आक्सीजन का स्तर पांच मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होना चाहिए



खड्डा कालोनी के पास यमुना नदी में जा रहा नाले का पानी। जागरण

यमुना दूषित होने की वजह ओखला बैराज में मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। बाकी हिस्सों में फिलहाल मछलियों के प्रजनन के चलते उनको पकड़ने पर रोक लागू है।
– डा. राकेश सिंह, निदेशक, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन विभाग

जब जामा मस्जिद पर मछली मंडी थी तब जरूर यमुना से मछली वहां बिकने आती थी। गाजीपुर मछली मंडी को बने करीब बीस साल हो गए हैं। तब से यहां यमुना की मछली कभी नहीं आई। इस नदी की मछली खाने लायक नहीं होती।
– नासिर अली अल्वी, चेयरमैन, गाजीपुर मछली मंडी

मेरे मेरे परिवार को यमुना नदी से मछली पकड़ते हुए 70 वर्ष हो गए हैं। यमुना में घटते जल स्तर और बढ़ते प्रदूषण के चलते यह काम खत्म हो गया है। यह मुनाफे का काम नहीं, लेकिन मछली पकड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता। –गुरविंदर सिंह, मछुआरा, झंगौला गांव

प्रदूषित मछली खाने से कैंसर का खतरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : यमुना नदी के दूषित पानी में पनपी मछली को खाने पर कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इस नदी के पानी में कई तरह की हानिकारक धातु घुली हुई हैं। अगर यहां से कोई मछली निकाली जाती है तो उसके अंदर हानिकारक धातुएं भी होंगी। ऐसे में मछली खाने पर इन धातुओं की वजह से धीरे-धीरे शरीर में कैंसर सेल पैदा हो सकती है।

धर्मशीला अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डा. अंशुमान कुमार ने बताया कि यमुना के दूषित पानी में आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, सीसा जैसी हानिकारक धातु होती हैं। ये धातुएं कैंसर कारक होती हैं। जब मछली ऐसे पानी में पली होंगी और उसका सेवन लोग करेंगे तो ये धातुएं उनके शरीर में जाएंगी। इससे उन्हें खून, आंत, पेशाब की थैली, अस्थि मज्जा (बोन मैरो), स्किन, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। लेकिन इसका पता काफी वक्त बाद पता चलता है। ऐसी मछली खाने से त्वरित रूप से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है। उन्होंने बताया कि यमुना की मछली गर्भवतियों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इससे उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। बच्चे के होंठ और तालु जन्म से कटे हो सकते हैं।

न्यूज गैलरी

डाक्टरों व रेस्टोरेंट मालिक में मारपीट, चार घायल

नई दिल्ली : हौजखास थाना क्षेत्र के गौतम नगर इलाके में बुधवार को दो डाक्टरों व दुकानदार में मारपीट हो गई। इसमें चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और उनका मेडिकल कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। दक्षिणी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के अनुसार, बुधवार को कुछ डाक्टर गौतम नगर स्थित भगत सिंह वर्मा पराठा वाली दुकान पर पराठा खाने गए थे। आरोप है कि डाक्टरों ने दुकान पर ही दुकानदार भगत सिंह के साथ शराब पी। इस दौरान किसी बात पर दुकानदार व डाक्टरों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें दो डाक्टर, भगत सिंह व उनके पुत्र अभिषेक घायल हो गए। (जासं)

मेडिकल कालेज के लिए केंद्र का दरवाजा खटखटाएगा जामिया

नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मेडिकल कालेज खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित जामिया मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाएगा। जामिया की कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार रात संपन्न हुई। इसमें इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मेडिकल कालेज के निर्माण का पूरा ब्योरा एवं 350 बेड के अस्पताल निर्माण की योजना संबंधी रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार से साझा करते हुए मेडिकल कालेज के निर्माण की गुहार लगाई जाएगी। कार्यकारी परिषद में जामिया परिसर में 50 बेड के कोविड सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। कोविड सेंटर में सिर्फ जामिया के पदाधिकारियों व उनके स्वजनों का इलाज होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया लंबे अरसे से मेडिकल कालेज खोलने की मांग कर रहा है। (जासं)

संयुक्त शोध करेंगे जेएनयू और डीआइपीएएस

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शिक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ फिजियोलाजी एंड एलाइड साइंसेस (डीआइपीएएस) के साथ करार किया है। कुलपति प्रो एम जगदीश कुमार ने कहा कि डीआरडीओ के साथ करार जेएनयू के अटल इनक्यूबेशन सेंटर में संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, संकाय और शोधार्थियों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर केंद्रित होगा। जेएनयू के पास जीवन विज्ञान और जैव चिकित्सा क्षेत्रों में बुनियादी व मौलिक अनुसंधान में विशेषज्ञता है। कुलपति ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड फिजियोलाजी, जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स, मेटाबालिकमिक्स, मेडिकल इंफार्मेटिक्स, हेल्थ इकोनामिक्स, केमोइनफारमैटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग और डेटा रिपोजिटरी सहित चिकित्सा अनुसंधान में अन्य उन्नत डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान किए जाएंगे। (जासं)

बस खरीद में अनियमितता का आरोप लगा भाजपा ने दिया धरना

नई दिल्ली : भाजपा लो फ्लोर बसों की खरीद की प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगा रही है। मामले की जांच के लिए भाजपा विधायकों ने दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, उपराज्यपाल व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने जांच के लिए समिति बना दी है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल बस खरीद की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को भाजपा विधायकों व नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को उनके पद से हटाने की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था बदहाल है। एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी है। इसके लिए सीधे तौर पर परिहवन मंत्री जिम्मेदार हैं। सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। (राब्यू)

मार्च 2022 तक शुरू होगी हेल्थ कार्ड योजना : केजरीवाल

मुख्यमंत्री ने एचआइएमएस प्रोजेक्ट की समीक्षा की, अधिकारियों को प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का निर्देश दिया

कोरोना संक्रमण के कारण प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुई देरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली



स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआइएमएस) प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस प्रणाली के साथ ही हेल्थ हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी और हेल्थ कार्ड के लिए पूरी दिल्ली में नए सिरे से सर्वे शुरू किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली में सबसे आधुनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बना रहे हैं। कोरोना के कारण प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च, 2022 तक यह प्रणाली शुरू हो जाएगी।

दिल्ली सरकार एचआइएमएस को दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके तहत मरीजों की देखभाल संबंधित सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैक एंड सेवा और प्रक्रियाओं आदि को इस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। इसके साथ ही ई-हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यह पूरा सिस्टम डिजिटल और क्लाउड पर आधारित होगा। इससे दिल्ली के लोगों को एक छत के नीचे सभी जानकारी प्राप्त करने और आपातकालीन मामलों में मदद मिल सकेगी। एचआइएमएस लागू होने के बाद दिल्ली देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा, जहां क्लाउड आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली होगी।

ई-हेल्थ कार्ड के लिए प्रस्तावित गतिविधियां : वोटर आइडी और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर दिल्ली के सभी निवासियों को क्यूआर कोड आधारित ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे मरीजों की संख्या के साथ ही उनकी बुनियादी क्लीनिकल जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही पात्र लोगों की स्वास्थ्य योजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए मैपिंग की जाएगी। इसके साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकेगा।

केंद्रीयकृत स्वास्थ्य हेल्पलाइन के लिए होगा काल सेंटर : इस स्कीम को लागू करने के लिए दो स्तर पर केंद्रीयकृत काल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्तर पर आने वाली शिकायतों व समस्याओं का ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) को लाग-इन कर केस का आकलन करते हुए उसका समाधान कराएंगे। साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं, दूसरे स्तर पर दिल्ली सरकार के डाक्टर और विशेषज्ञ फोन काल व संदेश को प्राप्त करते हुए मरीज को मिलने का समय देंगे। यदि केस इमरजेंसी है, तो उनकी काल को तत्काल स्वीकार करेंगे। यदि जरूरत पड़ती है, तो वे संबंधित रोग के विशेषज्ञ डाक्टर से संपर्क करेंगे। इसके बाद मरीज को जानकारी देते हुए सीआरएम पर इसका अपडेट देंगे।

कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए चल रहीं तैयारियां : मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- केजरीवाल ने इंदिरा गांधी अतिविशिष्ट अस्पताल में डायलिसिस यूनिट व पीडियाट्रिक आइसीयू वार्ड का किया उद्घाटन
- स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी को डाक्टर्स डे की शुभकामनाएं दीं

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुईं गलतियों से सबक लेकर दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। लहर कभी भी आए, लेकिन हमारी तैयारी इससे लड़ने के लिए पूरी रहनी चाहिए। ये बातें गुरुवार को द्वारका सेक्टर-9 स्थित इंदिरा गांधी अतिविशिष्ट अस्पताल में 20 बेड की डायलिसिस यूनिट व 23 बेड के पीडियाट्रिक आइसीयू वार्ड के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहीं।

उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऐसा कोई परिवार नहीं था, जिसपर महामारी का प्रभाव न पड़ा हो। दूसरी लहर में कई लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में निजी संस्थाओं व कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने जिस तरह से मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वह सराहनीय है। महामारी से उबरने के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी को डाक्टर्स डे की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इंडियन सोसायटी आफ जीसस क्राइस्ट संस्था का धन्यवाद किया, जिसने अस्पताल को 10 लीटर की क्षमता युक्त 500 आक्सीजन कंसंट्रेटर व 1200 मानीटर प्रदान किए हैं।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि दूसरों की सेवा में ही स्वयं की सेवा छिपी हुई है, क्योंकि इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। तीसरी लहर यदि दिल्ली में दस्तक देती है तो उससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी अतिविशिष्ट अस्पताल सक्षम है।

अस्पताल में 1,243 बेड तैयार हैं। कार्यक्रम में अस्पताल के निदेशक डा. बृजेश कुमार, क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून, विधायक अखिलेश त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे।

कोरोना से अनाथ हुए 67 बच्चों के लिए सीएम आज शुरू करेंगे विशेष योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार खास योजना शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की वजह से 67 बच्चे अनाथ हुए हैं। कोरोना की वजह से 651 बच्चों की मां और 1311 बच्चों के पिता का निधन हो गया। ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी। दिल्ली छोड़ चुके लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। गौतम ने आगे कहा कि माता या पिता में किसी एक को खोने वाले बच्चों को पचास हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए की राशि के साथ एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही इस संबंध में अहम सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य किया गया है जिसमें उन लोगों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि शामिल होनी चाहिए, जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवाई है।

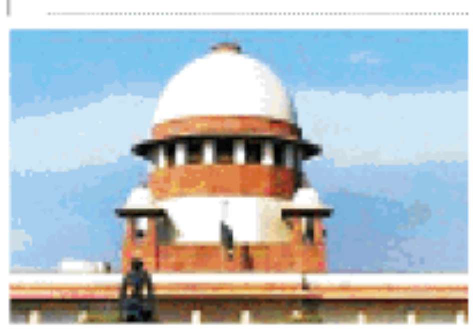
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को गवाही की प्रति देने का आदेश

- दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील शीर्ष अदालत ने की खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में एक गवाह के बयान की प्रति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को उपलब्ध कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुलिस की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक रूप से यह एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से इसमें कुछ खास नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस को एक गवाह का बयान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को मुहैया कराने को कहा था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांत के अनुसार आरोपित के पास गवाह के बयान की प्रति होनी चाहिए।

अदालत ने पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अमन लेखी की इन दलीलों को खारिज कर दिया कि यदि हाई कोर्ट के फैसले को रद नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक रूप से यह विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से इसमें कुछ खास नहीं। फाइल

यह आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश के साथ कथित तौर पर मारपीट से जुड़ा है। केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य आप विधायकों को अक्टूबर, 2018 में जमानत दी गई थी। हाई कोर्ट ने इससे पहले दो अन्य विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को जमानत दी थी।

आम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ स्पुतनिक-वी टीका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में कोविशील्ड व कोवैक्सीन के अलावा अब आम लोगों के लिए स्पुतनिक-वी टीका भी उपलब्ध हो गया है। अभी निजी क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ अपोलो, बत्रा सहित तीन अस्पतालों में ही यह टीका उपलब्ध है। बत्रा अस्पताल में मंगलवार व अपोलो अस्पताल में बुधवार से स्पुतनिक-वी टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक करीब 1300 लोगों को इस टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। अपोलो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह टीका लेने के लिए लोग कोविन एप पर पंजीकरण कराने के बाद अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। अप्वाइंटमेंट के जरिये ही अभी यह टीका लगाया जाएगा। बगैर आनलाइन अप्वाइंटमेंट के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने पर फिलहाल यह टीका नहीं लगाया जाएगा।

अगले कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ और निजी अस्पतालों में भी यह टीका उपलब्ध होने की उम्मीद है। निजी अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत 1145 रुपये है। पहली डोज लगने के 21 दिन के अंतर पर दूसरी डोज दी जाएगी। यह टीका एडिनोवायरस से बना है, लेकिन इसकी दोनों डोज एक-दूसरे से अलग हैं।

आइजीआइ एयरपोर्ट पर घरेलू विमान यात्रियों की तादाद तीन गुना से अधिक बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मई के मध्य में 18 हजार यात्रियों की आवाजाही थी, जो जून के अंत तक करीब 62 हजार तक पहुंच गई

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है। लाकडाउन के दौरान मई के मध्य में रोजाना एयरपोर्ट पर 18 हजार यात्रियों की आवाजाही थी, जो जून के अंत तक करीब 62 हजार पहुंच गई यानी डेढ़ महीने में यात्रियों की आवाजाही में तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आइजीआइ एयरपोर्ट का प्रबंधन संभालने वाली संस्था डायल को उम्मीद है कि आने वाले समय में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद और भी तेज गति से बढ़ेगी।

डायल के मुताबिक विमान यात्रियों में सर्वाधिक तादाद ऐसे यात्रियों की है जो अपने स्वजन व मित्रों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। कुल यात्रियों में करीब इनकी आधी तादाद है। वहीं करीब एक चौथाई यात्री ऐसे हैं जो छुट्टियां मनाने दिल्ली से बाहर गए या यहां आए। इसके अलावा कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने वालों की तादाद करीब 19 फीसद है। विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की बात करें तो इनकी तादाद में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

लाकडाउन के दौरान मई के मध्य में जहां इनकी तादाद रोजाना करीब साढ़े चार हजार थी जो अब बढ़कर साढ़े सात हजार पहुंच चुकी है। मई व जून महीने में घरेलू यात्रियों की बात करें तो मुंबई, पटना, पुणे, हैदराबाद, लेह, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिल्ली से सर्वाधिक टिकट बुक किए गए।



आइजीआइ एयरपोर्ट पर आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। फाइल

भरोसा जगाने के हो रहे प्रयास

डायल के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान विमान यात्री हवाई यात्रा को सुरक्षित समझें, इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए। एयरपोर्ट पर सफाई हो या यात्रियों की कोरोना जांच, हर स्तर पर उत्कृष्ट सेवाएं दी गईं। टर्मिनल की साफ-सफाई के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वहीं कोरोना जांच के लिए रैपिड जांच की व्यवस्था थी ताकि यात्रियों को जांच के नतीजे जल्द से जल्द मिल जाएं। टर्मिनल पर इस्तेमाल की जाने वाली हर वस्तुओं को सैनिटाइज किया जाता था। शारीरिक दूरी को लेकर यहां पूरी तरह सावधानियां बरती गईं।

येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी ने संभाली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- निजी कंपनी ने 153 ट्रेन चालक की नियुक्त, 70 चालकों का प्रशिक्षण पूरा
- अन्य मेट्रो कारिडोर पर परिचालन की जिम्मेदारी भी निजी एजेंसी को देने की तैयारी

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पहली बार येलो लाइन पर मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी को सौंप दी है। एजेंसी द्वारा नियुक्त 70 चालकों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण डीएमआरसी ने यह कदम उठाया है। फिलहाल येलो लाइन पर तीन साल के लिए मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी लाइनों पर परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी है।

डीएमआरसी परिचालन पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए लंबे समय से आउटसोर्सिंग की तैयारियों में जुटा हुआ था। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया था। इसके बावजूद येलो लाइन परिचालन के लिए निजी एजेंसी की नियुक्ति कर दी गई। उक्त निजी एजेंसी ने अब तक 153 मेट्रो ट्रेन आपरेटरों (चालक) की नियुक्ति की है। डीएमआरसी व निजी एजेंसी के बीच हुए समझौते के अनुसार चालकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो की होगी। शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी में 70 चालकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसके अलावा 83 चालकों का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर से येलो लाइन की कुल लंबाई 49.31 किलोमीटर है। डीएमआरसी का कहना है कि निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त चालक विभाग की निगरानी में ही मेट्रो का परिचालन करेंगे। निजी एजेंसी का दायित्व सिर्फ चालक उपलब्ध कराना है। ट्रेनों की रखरखाव की जिम्मेदारी डीएमआरसी के पास ही रहेगी।

मेट्रो स्टेशनों की साफ सफाई व टोकन बिक्री की जिम्मेदारी पहले से निजी एजेंसियों के पास रही है। पहली बार दिल्ली मेट्रो के किसी लाइन परिचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई है। इससे डीएमआरसी को स्थायी तौर पर ट्रेन चालकों की नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो की 10 लाइनें हैं, जिसका कुल नेटवर्क 348 किलोमीटर है और 253 मेट्रो स्टेशन हैं। इन सभी 10 लाइनों पर परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी।

कोरोना काल में बढ़ा मेट्रो का घाटा, केंद्र सरकार ने चुकाया लोन

कोरोना के दौर में मेट्रो का घाटा बढ़ गया है। क्योंकि लाकडाउन में काफी दिनों तक मेट्रो का परिचालन बंद रहा था। अब भी मेट्रो का परिचालन करीब 10 फीसद क्षमता के साथ ही हो रहा है। इस वजह से यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेट्रो का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में मेट्रो परिचालन, फीडर बसों व संपत्तियों के किराये से डीएमआरसी को महज 895.88 करोड़ राजस्व मिला। जबकि इसके पिछले साल डीएमआरसी की कमाई 3897.29 करोड़ हुई थी। इसके मुकाबले इस बार 3001.40 करोड़ की आमदनी कम हुई है। हालांकि, मेट्रो को केंद्र सरकार से करीब 1242.28 करोड़ की सहायता मिली। केंद्र सरकार ने जापान की एजेंसी का लोन चुकाने के लिए 808.70 करोड़ व लोन का ब्याज चुकाने के लिए 433.85 करोड़ भुगतान किया। फिर भी डीएमआरसी को 1784 करोड़ का नुकसान हुआ है।

ग्रामीण इलाके की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ेंगे आइआइटी छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आइआइटी दिल्ली) ने छात्रों के लिए ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम (जीआरआइपी) शुरू किया है। इसके तहत छात्र ग्रामीण, अर्ध नगरीय इलाकों की समस्याओं का हल तलाशेंगे। जीआरआइपी का औपचारिक उद्घाटन करते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो के विजय राघवन ने कहा कि इससे ग्रामीण समस्याओं का समाधान निकलेगा।

आइआइटी दिल्ली ने बताया कि जीआरआइपी के तहत दो चरणों में समस्याओं का हल निकाला जाएगा। पहले चरण के तहत छात्रों का समूह ग्रामीण, अर्ध नगरीय इलाकों का हफ्ते या महीने में एक बार भ्रमण करेगा। गांवों में स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। समस्याओं की पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। डिजाइन विभाग के अध्यक्ष प्रो पीवीएम राव ने बताया कि यह प्रोग्राम छात्रों की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा।

आइआइटी ने बताया कि दूसरे चरण में छात्रों द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। इसमें विज्ञानियों की भी मदद ली जाएगी। छात्रों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए पूरे सेमेस्टर साल भर की लंबी परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। आइआइटी निदेशक प्रो वी रामगोपाल राव ने बताया कि कई छात्रों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसकी मदद से छात्र जिस जगह रहते हैं, वहां के समुदाय की समस्याओं का भी आगे बढ़कर समाधान करेंगे। यह उन छात्रों के लिए बेहतरीन पहल है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जीआरपीआइपी छात्रों को बौद्धिक और वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा।

निजी स्कूलों को पिछले साल की तुलना में 15 फीसद कम फीस वसूलने के आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाते हुए दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश लागू कर दिया है। निजी स्कूलों को अब फीस में 15 फीसद की कटौती करनी होगी। यह कटौती 2020-21 में प्रतिमाह ली गई कुल फीस के आधार पर की जाएगी। यह आदेश उन्हीं स्कूलों पर लागू होगा, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि किसी स्कूल ने वित्त 2020-21 में मासिक फीस 3000 रुपये माह ली है, तो 2021-22 सत्र के लिए निजी स्कूल 15 फीसद कटौती के साथ 2550 रुपये प्रतिमाह ही चार्ज कर सकेंगे। यदि स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस ली जा चुकी है, तो स्कूलों को आने वाले माह में इसे समायोजित करना होगा। साथ ही स्कूलों को मासिक आधार पर ही फीस वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

8 बजे सुबह से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे पंजाब में सरकारी दफ्तर। प्रदेश में बिजली संकट के कारण यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी अधिकारियों व लोगों से बिजली खपत कम करने की अपील की है।

डिजिटल इंडिया यानी भ्रष्टाचार पर चोट

कार्यक्रम के छह साल ▸ डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक के लिए सुविधा का बड़ा माध्यम

पीएम बोले, इस कार्यक्रम में सबको अवसर, सबको सुविधा और सबकी भागीदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों के लिए सुविधा और उनके सशक्तीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसने सिर्फ गरीबों की नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी। डिजिटल इंडिया में सबको अवसर, सबको सुविधा और सबकी भागीदारी है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के छह साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट है। डिजिटल इंडिया समय, श्रम और धन की बचत है। डिजिटल इंडिया मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस है और इससे सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच है। इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की बदौलत कोरोना के इस डेढ़ साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब सात लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में सिर्फ भीम यूपीआइ से ही हर महीने करीब पांच लाख करोड़ रुपये का लेनदेन होता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन, वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड खरीद के लगभग 85 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। ई-नाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन कर चुके हैं।



डिजिटल इंडिया अभियान की छठी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। एएनआइ

डिजिटल इंडिया से मिलने वाले अन्य लाभ

डिजि-लाकर : 10वीं, 12वीं, कालेज, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजि-लाकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। अभी कोरोना काल में कई शहरों के कालेज एडमिशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट्स का वैरिफिकेशन डिजि-लाकर की मदद से ही कर रहे हैं।

सेवा प्रक्रिया आसान हुई : ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों की प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान हो गईं। गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास कामन सर्विस सेंटर से हो रहा है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड : अब दूसरे राज्य में जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनवाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।

गरीबों को सिस्टम से जोड़ना : रेहड़ी-ठेला-पटरी वाले डिजिटल इंडिया के कारण स्वनिधि योजना से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को घर की कानूनी सुरक्षा के दस्तावेज मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधा : डिजिटल इंडिया से घर बैठे मरीजों का इलाज संभव हो गया है। कोरोना काल में तैयार किए गए आरोग्य सेतु व कोविन एप दुनिया में चर्चा का विषय हैं। इससे कोरोना को रोकने में बहुत मदद मिली है।

वर्क फ्राम होम : आज कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होमस्टे से अपना काम कर रहा है जो डिजिटल कनेक्ट से ही संभव हो पाया है।

पीएम-वानी से गरीब बच्चों को मिलेंगे आनलाइन शिक्षा के अवसर : प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-वानी योजना से देशभर में ऐसे एक्सेस प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां कम से कम कीमत में ब्राडबैंड- वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों और युवा साथियों को आनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

भारतीय डाक्टर के साथ अफगान राजदूत के अनुभव में दो देशों के संबंधों की है सुगंध : पीएम

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ राष्ट्रीय डाक्टर दिवस पर अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने हिंदी में ट्वीट कर जीता देशवासियों का दिल

▸ राजस्थान घूमने की इच्छा पर मोदी ने भी ट्वीट कर फरीद को राजस्थान सहित गुजरात के भी हरिपुरा गांव जाने की दी सलाह

भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता की एक बानगी गुरुवार को राष्ट्रीय डाक्टर दिवस पर देखने को मिली। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई का हिंदी में एक ट्वीट देशवासियों के दिल को छू गया। इसमें फरीद ने एक भारतीय डाक्टर की दरियादिली की जमकर तारीफ की। इस पर उनके भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें अपने शहर आने का न्योता दिया। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की सहयोगी बल कौर ढिल्लो ने भी उन्हें राजस्थान स्थित अपने गांव हरिपुरा आने का निमंत्रण दिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको राजस्थान सहित गुजरात के भी हरिपुरा गांव जाने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय डाक्टर के साथ अफगान राजदूत के अनुभव में दो देशों के संबंधों की सुगंध है।

दरअसल, राष्ट्रीय डाक्टर दिवस पर अफगानिस्तान के भारत में राजदूत फरीद मामुंदजई ने ट्वीट कर एक भारतीय डाक्टर की तारीफ की। उन्होंने लिखा-कुछ दिन पहले मैं इलाज के लिए एक डाक्टर के पास गया था। यह जानने पर कि मैं भारत में अफगान राजदूत हूं उन्होंने मुझसे कोई शुल्क नहीं लिया। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यह सेवा तो अफगानिस्तान के लिए बहुत कम है। वह एक भाई से फीस नहीं लेंगे। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। यह भारत है।

उन्होंने लिखा कि यहां प्यार, सम्मान, मूल्य और करुणा है। आपके कारण मेरे दोस्त, अफगानी थोड़ा कम रोते हैं, थोड़ा और मुस्कुराते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं।

लोगों के आमंत्रण पर फरीद ने राजस्थान यात्रा की इच्छा जताई है। इस पर बलकौर ढिल्लो ने उन्हें राजस्थान स्थित अपने गांव हरिपुरा आने का निमंत्रण दिया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने फरीद को संबोधित करते हुए कहा कि आप बलकौर ढिल्लों के हरिपुरा भी जाइए और गुजरात के हरिपुरा भी। वह भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। मेरे देश के एक डाक्टर के साथ का आपने जो अनुभव शेयर किया है, वह भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की खुशबू की एक महक है। इसके बाद फरीद ने फिर एक ट्वीट कर अपने ही अंदाज में जवाब दिया।

उन्होंने लिखा-अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। आप उन्हें हमेशा नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं कि वे हमेशा मौजूद रहते हैं। भारतीयों और अफगानों के संबंधों की कहानी। समय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यह इस पुरानी और गहरी दोस्ती का एक और उदाहरण है।

अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे पर केवल संसद बना सकती है कानून : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सदन के अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार देने संबंधी याचिकाओं के समय पर निस्तारण के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, हम कानून कैसे बना सकते हैं? यह संसद का मामला है।

सुप्रीम कोर्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य राणाजीत मुखर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने अध्यक्षों द्वारा अयोग्यता याचिकाओं के समय पर निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश बनाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया था। सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक जेबराज ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के तहत अयोग्य करार देने संबंधी याचिकाओं पर फैसला देने के लिए दिशा निर्देश बनाने की खातिर याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि एक निर्धारित समय सीमा तय की जाए, क्योंकि अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले नहीं ले रहे हैं और 10वीं अनुसूची के तहत समय रहते कदम नहीं उठा रहे हैं।



▸ कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी

इस पर जस्टिस रमना ने कहा, मैंने कर्नाटक विधायक मामले में पहले ही अपनी राय दे दी है। उस मामले में भी यह मुद्दा उठा था और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसी तरह की दलीलें रखी थीं। लेकिन, हमने संसद पर यह फैसला छोड़ दिया था। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने फैसला पढ़ा है? इस पर जेबराज ने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा है। पीठ ने कहा, आप फैसला पढ़िए और फिर वापस आइए। हम दो हफ्तों के बाद मामले पर सुनवाई करेंगे।

शीर्ष अदालत ने विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए 13 नवंबर, 2019 को कहा था कि अध्यक्ष के पास यह बताने की शक्ति नहीं होती कि कोई विधायक कब तक अयोग्य करार रहेगा या उसे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। यह अध्यक्ष के फैसले से जुड़ा मामला है, जिसके तहत विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया और उनके मौजूदा विधानसभा तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई।

आनलाइन पढ़ाई में ढिलाई पर संसदीय समिति हुई सख्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ उत्तर प्रदेश, बंगाल सहित आधा दर्जन राज्यों के शिक्षा सचिवों को किया तलब



समिति की बैठक आज, स्मार्ट फोन की जगह सेटेलाइट टीवी के जरिये पढ़ाने का सुझाव। फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल-कालेज बंद हैं और बच्चों के पास आनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में सभी बच्चों तक इसकी पहुंच न होने को लेकर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि स्मार्ट फोन व इंटरनेट जैसी सुविधा सिर्फ 30 फीसद बच्चों के पास है। ज्यादातर राज्यों में आनलाइन पढ़ाई इसके जरिये ही कराई जा रही है। ऐसे में करीब 70 फीसद बच्चे इससे वंचित हैं। समिति ने इस मामले में राज्यों को जवाबदेह माना है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बंगाल सहित करीब आधा दर्जन राज्यों के शिक्षा सचिवों को तलब किया है।

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति ने इस संबंध में अहम बैठक शुक्रवार को रखी है। इसमें प्रसार भारती और इसरो के अधिकारियों को भी बुलाया है। समिति का मानना है कि कोरोना काल में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य कुछ और बेहतर कर सकते हैं। इस मामले में समिति ने गुजरात और ओडिशा में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सेटेलाइट चैनल का उदाहरण दिया है। साथ ही सभी राज्यों से इसी तर्ज पर प्रयास करने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार, समिति इससे पहले सभी राज्यों को ऐसा करने का सुझाव दे भी चुकी है। हालांकि राज्यों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माना जा रहा है कि आनलाइन पढ़ाई में ढिलाई पर राज्यों से सवाल-जवाब भी किया जा सकता है। समिति का कहना है कि सालाना दो से ढाई करोड़ के खर्च में ही इन सेटेलाइट चैनलों को शुरू किया जा सकता है।

समिति ने जिन प्रमुख राज्यों के शिक्षा सचिवों को तलब किया है, उनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। समिति से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में सेटेलाइट एजुकेशन चैनल को संचालित करने वाली एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। वे इस संबंध में प्रजेंटेशन देंगे। बैठक में समिति आनलाइन शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय और राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी लेगी, जिसमें वन क्लास-वन चैनल का प्रस्ताव भी शामिल है।

ड्रोन के खतरों से निपटने की क्षमता विकसित कर रही सेना : नरवणे

▸ पाक के साथ संघर्ष विराम के बाद से एलओसी पर नहीं हुई घुसपैठ



सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के हमारे अभियान जारी रहेंगे। जागरण आर्काइव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि ड्रोन की आसानी से उपलब्धता ने सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना इनके खतरों से प्रभावी रूप से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है। फिर चाहे ये किसी देश की सरकार द्वारा प्रायोजित तत्वों से हों या खुद किसी देश द्वारा उत्पन्न हों।

वर्चुअल माध्यम से एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से भली भांति परिचित हैं और उन्होंने कुछ सुरक्षा उपाय अपनाए भी हैं। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थिति के बारे में सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ नहीं हुई है। इस कारण कश्मीर में आतंकियों की संख्या में कमी आई है और आतंकी घटनाएं भी घटी हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे तत्व हमेशा मौजूद रहेंगे जो शांति और विकास की प्रक्रिया बाधित करने की कोशिश करेंगे, हमें उनसे निपटना होगा। जम्मू-कश्मीर में आतंक रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है और शांति बनाए रखने के हमारे अभियान जारी रहेंगे।'

पैंगोंग झील इलाके में सेनाओं के पीछे हटने के बाद से एलएसी पर हालात सामान्य : जनरल नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर भारत-चीन वार्ता ने विश्वास कायम करने में मदद की है और पैंगोंग झील व कैलास रेंज से फरवरी में सेनाओं के पीछे हटने के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालात सामान्य रहे हैं। उन्होंने बाकी मसलों के जल्द समाधान का भरोसा जताया, लेकिन साथ ही कहा कि पिछले साल उत्तरी सीमा का घटनाक्रम इस बात की दृढ़ता से याद दिलाता है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए सेना को लगातार तैयार रहने और युद्ध की आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही हैं इनमें कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य स्तरीय वार्ताएं शामिल हैं।

प्रवेश परीक्षा पर केंद्रीय विवि से मांगा प्लान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर फिर हरकत में आया शिक्षा मंत्रालय

▸ यूजीसी को भी इस मसले पर विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय की सौंपी गई जिम्मेदारी

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर पिछले कुछ हफ्तों के चुप्पी के बाद शिक्षा मंत्रालय फिर हरकत में आया है। मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों से व्यापक प्लान मांगा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की योजना से जुड़ा एक प्रजेंटेशन मंत्रालय को दिया है।

शिक्षा मंत्रालय ने यह तेजी तब दिखाई है, जब सीबीएसई सहित सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों का 12वीं का परिणाम 31 जुलाई तक घोषित हो जाएगा। ऐसे में इससे पहले स्नातक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करनी है। साथ ही इसे लेकर सभी विश्वविद्यालयों की ओर से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इस साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का एलान कर चुका है। हालांकि, अभी तक उन्हें इसको लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मानना है कि दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसे कराने या न कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाए, ताकि इसके आयोजित न होने की स्थिति में वह समय रहते अपनी तैयारी कर सके। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की इस सक्रियता से विश्वविद्यालयों ने राहत की सांस ली है।

वहीं शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से इस मामले में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालयों की ओर से दाखिले को लेकर आने वाली योजनाओं में किसी बेहतर योजना को अपनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा से छात्रों का भटकाव कम होगा। साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा।

मोदी ने पुडुचेरी के विधायकों से चर्चा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : पीएम नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा की। पुडुचेरी में आइएनआरसी की अगुआई वाली राजग सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले ए. नमसिवयम और भाजपा की केंद्र शासित प्रदेश शाखा के अध्यक्ष वी सामिनाथन प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

पहली बार दक्षिण भारत के इस केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री एवं एआइएनआरसी संस्थापक एन. रंगासामी के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से दो सदस्य नामसिवयम और एके साई जे सरवन कुमार शामिल हैं। मोदी ने विधायकों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, 'पुडुचेरी के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पुडुचेरी के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की।'

नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन से भारत सरकार को भेजे 17.25 करोड़ रुपये

▸ पीएनबी घोटाले की जांच में मदद की शर्त पर सरकारी गवाह बनाई गई है पूर्वी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बताया कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन स्थित बैंक अकाउंट में जमा 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। पूर्वी 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) लोन घोटाले में सरकारी गवाह बन चुकी है।

पूर्वी मोदी उर्फ पूर्वी मेहता (47) व उसके पति मयंक मेहता को जनवरी में मुंबई स्थित प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने और जांच में ईडी का सहयोग करने की शर्त पर क्षमादान की स्वीकृति दी है।

पूर्वी और उसके पति ब्रिटिश नागरिक हैं और वे जांच में कभी शामिल नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, '24 जून को पूर्वी ने ईडी को सूचित किया कि लंदन में स्थित एक बैंक में उसके नाम पर अकाउंट है। उसे नीरव मोदी के कहने पर खोला गया है। उसमें जमा धन पूर्वी का नहीं है।'

ईडी ने बताया, 'पूर्वी ने ब्रिटेन स्थित अपने बैंक अकाउंट में रखे 23,16,889.03 डालर (करीब 17.25 करोड़ रुपये) भारत सरकार (प्रवर्तन निदेशालय) के अकाउंट में भेज दिए हैं। यह राशि अपराध से अर्जित संपत्ति का हिस्सा है।' एजेंसी ने कहा कि पूर्वी ने ईडी को भरोसा दिया है कि वह न्यूयार्क व लंदन में स्थित फ्लैट तथा स्विस बैंक में जमा नकदी समेत 579 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने में मदद करेगी।

इससे पहले ईडी ने पूर्वी के खिलाफ वर्ष 2018 में इंटरपोल के जरिये गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया था तथा उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत दो आरोप पत्र भी दाखिल किए थे। अदालत में क्षमादान की याचिका दाखिल करते हुए पूर्वी ने कहा था कि घोटाले में ईडी ने उसकी सीमित भूमिका बताई है और वह मामले की जांच में एजेंसी की हर तरह से मदद के लिए तैयार है।

बता दें कि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपित नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। उसकी भारत प्रत्यर्पण संबंधी याचिका भी खारिज हो चुकी है।

आह्वान

अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जनता से संवाद बढ़ाने पर गृह मंत्री का जोर

पुलिस की छवि बेहतर बनाने में जुट जाएं आइपीएस : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पुलिस विभाग की छवि बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। वे ऐसे कार्य करें जिससे जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर बनकर उभरे। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है।

आइपीएस के 72 वें बैच के अधिकारियों को वीडियो लिंक के जरिये संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पुलिस पर लगने वाले कार्रवाई न करने या अतिरेक कार्रवाई करने के आरोपों से अलग हटकर सही और जरूरी कार्रवाई करने वाली छवि विकसित की जाए। सही और जरूरी कार्रवाई का मतलब स्वाभाविक कार्रवाई होती है, जो हर किसी की समझ में आ जाती है। पुलिस कानून जानती है, इसलिए वह उसके दायरे में रहते हुए सही लगने वाला कार्य कर सकती है। इसलिए अपनी छवि को बेहतर बनाने का कार्य खुद पुलिसकर्मी ही कर सकते हैं।

गृह मंत्री ने कहा, संवाद और संवेदनशीलता, ऐसे मूल बिंदु हैं जिनको व्यवहार में लाकर पुलिस अपनी छवि को बेहतर बना सकती है। इसलिए सभी पुलिसकर्मियों को जनता से अपना संवाद बढ़ाना चाहिए। उनके बीच पैठ स्थापित करनी चाहिए। इससे अपराध भी रुकेंगे और अपराधी भी बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जनसंपर्क के बगैर किसी अपराध को करने वाले को ढूंढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को चाहिए कि वे तहसील और ग्राम स्तर पर जाकर लोगों से मिलें, उनका विश्वास प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी ग्रामीण इलाकों में जाकर रात गुजारें। लेकिन आइपीएस समेत अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी प्रचार से दूर रहें, इससे वे बेहतर प्रशासन देने में सफल हो पाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।



नई दिल्ली में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आइपीएस के 72वें बैच के अधिकारियों से संवाद किया। एएनआइ

इंटरनेट मीडिया का हिस्सा न बनें अधिकारी

अमित शाह ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इंटरनेट मीडिया से जरूरी जानकारी तो लें लेकिन उसका हिस्सा न बनें। इससे वे बेवजह की बहस में पड़े बगैर बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। पुलिस कांस्टेबलों के कल्याण वाले कार्यों पर जोर देते हुए शाह ने कहा कि पुलिस अधिकारी उनके लिए जीवन भर कार्य कर सकते हैं। कहा कि कांस्टेबल पुलिस बल की 85 प्रतिशत ताकत हैं। वे पुलिस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जमीन पर वे कानून के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। अगर हम उनके कल्याण के कार्यों पर ध्यान देंगे तो बाकी का 15 प्रतिशत पुलिस विभाग बेहतर तरीके से देश और समाज की सेवा कर सकेगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी



3 बार विधानसभा चुनाव हारने वाले या जमानत गंवाने वाले प्रत्याशियों को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काट सकती है। इस फार्मूले से चार जिलाध्यक्षों सहित 15 ब्लाक अध्यक्षों की छुट्टी तय मानी जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 जुलाई, 2021

चुनाव बाद हिंसा पर बंगाल, केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस

उठाई आवाज ▸ सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब, कोर्ट से हिंसा के कारणों की जांच करा दोषियों को सजा देने की मांग

कानून-व्यवस्था की बिगड़ती दशा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीछे के कारणों की जांच कराए जाने और दोषियों को सजा देने की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा खासतौर पर उठाया गया है। पीड़ितों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि बंगाल में कानून-व्यवस्था की खराब होती स्थिति पर केंद्र सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दिया जाए। साथ ही बंगाल में आंतरिक गड़बड़ी को शांत करने के लिए केंद्र को वहां सशस्त्र अर्ध सैनिक बल लगाने का निर्देश दिया जाए।

ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।

गुरुवार को जस्टिस विनीत सरन और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने याचिका पर वकील हरिशंकर जैन को सुनने के याचिका में प्रतिवादी बनाई गई केंद्र


मांगा जवाब : सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो।

सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी प्रतिवादी बनाया गया है लेकिन उन्हें नोटिस जारी नहीं हुआ है।

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा व हिंदुओं पर अत्याचार का मामला उठाने वाली यह जनहित याचिका वकील रंजना अग्निहोत्री और जितेंद्र सिंह ने दाखिल की है। कहा गया कि यह याचिका विशेष परिस्थितियों में दाखिल की गई है। बंगाल के हजारों निवासियों को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं ने भाजपा का समर्थन करने के कारण सताया, मारा और आतंकित किया है। याचिका के जरिये बंगाल के उन हजारों लोगों की बात उठाई जा रही है, जो ज्यादातर हिंदू हैं और जिन्हें मुसलमानों ने भाजपा का समर्थन करने के कारण निशाना बनाया। वे हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं ताकि वर्षों तक उनकी पसंद की पार्टी ही सत्ता में रहे। कहा गया है कि बंगाल में दो मई को चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लूटमार शुरू कर दी। कम से कम 15 भाजपा समर्थकों की हत्या हुई और सैकड़ों घायल हुए। महिलाओं का अपहरण और दुष्कर्म हुआ लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन ने पीड़ितों को कोई सुरक्षा नहीं दी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार, प्रशासन और पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते रहे जिसके कारण महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ हुआ। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई जिसके चलते महिलाओं और बच्चों का जीवन खतरे में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट के तुरंत दखल देने की जरूरत है। कोर्ट निर्देश दे ताकि बंगाल में सरकार संविधान के मुताबिक चले और अगर हिंसा लगातार जारी रहे तो भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 के तहत उचित कार्रवाई करे।

'निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहा निर्वाचन आयोग' : याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ी। उसने मुसलमानों से एक बने रहने और बेहतर भविष्य के लिए उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। पांच अप्रैल, 2021 को भाजपा ने टीएमसी की इस सांप्रदायिक अपील के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। लेकिन आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के प्रविधान लागू करने में नाकाम रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अभिराम सिंह मामले में दिए फैसले में इस प्रविधान की व्याख्या में कह चुकी है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में धार्मिक अपील नहीं कर सकता। कहा गया कि बंगाल में करीब 30 फीसद मुस्लिम आबादी है। वहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बिना किसी जांच के मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया है। करीब 100 निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों के मत ही उम्मीदवार का फैसला करते हैं।

शाह से मिले सुवेंदु, हिंसा और फर्जी वैक्सीन मामले पर की चर्चा

मुलाकात

- सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी कानूनी मामलों को लेकर किया विमर्श
- तृणमूल सांसद दिब्येंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके बीच लगभग 35 मिनट तक बैठक चली। शुक्रवार से बंगाल में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र से पहले यह बैठक राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजट सत्र में भाजपा हिंसा के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। चुनाव परिणाम के बाद यह बंगाल विधानसभा का पहला सत्र है।

बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद सुवेंदु अधिकारी की अमित शाह के साथ यह दूसरी मुलाकात है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राज्य में चुनाव बाद हिंसा तथा फर्जी वैक्सीन घोटाले को लेकर चर्चा हुई। सुवेंदु अधिकारी


भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। एएनआइ

ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन से भी मुलाकात की। उनके साथ कूचबिहार के सांसद निशीथ प्रमाणिक भी थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य के फर्जी टीकाकरण मामले पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार ने टीकाकरण के लिए अपना खुद का बेनवैक्स पोर्टल लांच किया है। मैंने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे बताया कि वैक्सीन घोटाले पर राज्य सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट भेज दी है।

एएनआइ के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी ने कानूनी मामलों में विमर्श के लिए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मुलाकात की। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि बंगाल की सियासत का रण अब अदालत भी पहुंच चुका है। चुनाव बाद हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने भी इसकी जांच कर रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी है। भाजपा हिंसा के मामले को लगातार उठा रही है। वहीं, ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी को मिली जीत के परिणाम को अदालत में चुनौती दी है।

सुवेंदु के भाई पहुंचे पीएम आवास: दूसरी ओर, तमलुक के तृणमूल सांसद तथा सुवेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि दिब्येंदु ने बंगाल में कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। दिब्येंदु मंगलवार रात 11:30 बजे लोककल्याण मार्ग गए और वहां लगभग 40 मिनट रहे। देर रात प्रधानमंत्री आवास में उनके जाने को लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। सुवेंदु और उनके छोटे भाई सौम्येंदु पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिब्येंदु भी शीघ्र ही भाजपा में शामिल होंगे।

ममता के आरोपों पर हर्षवर्धन का पलटवार, बोले- महामारी पर ओछी राजनीति से बचें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- मुख्यमंत्री ने केंद्र पर बंगाल को छोटे राज्यों से भी कम वैक्सीन देने का लगाया था आरोप
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर गैरजिम्मेदाराना बयान से बचने की दी नसीहत

कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर बंगाल में सियासत जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि बंगाल को छोटे राज्यों से भी कम वैक्सीन दी गई है। ममता के इस बयान के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने गुरुवार को बिना नाम लिए उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक हस्तियां कोरोना वैक्सीन को लेकर गैरजिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को महामारी में ओछी राजनीति से बचना चाहिए।

डा. हर्षवर्धन ने एक के बाद एक अपने कई ट्वीट में राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन आपूर्ति की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी राजनेताओं से महामारी पर ओछी राजनीति से बचने की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 75 फीसद वैक्सीन को मुफ्त किए जाने के बाद टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी है। 11.50 करोड़ डोज अकेले जून में दी गई हैं। जुलाई की वैक्सीन सप्लाई के लिए राज्यों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस जानकारी को राज्यों के साथ 15 दिन के निश्चित समय में साझा किया जाता है, वह भी प्रतिदिन की सप्लाई के साथ। जुलाई में सप्लाई के लिए कुल 12 करोड़ खुराक तैयार हैं। प्राइवेट अस्पतालों के लिए सप्लाई इससे कहीं अधिक होगी। अगर राज्यों को कहीं दिक्कत होती है, तो उससे यह पता चलता है कि उन्हें अपने टीकाकरण अभियान के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है।

फर्जी टीकाकरण पर टीएमसी ने राज्यपाल को भी घेरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार और राजभवन के बीच जारी टकराव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्यपाल जगदीप धनखड़ को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। जैन हवाला कांड से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जुड़े रहने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों के बाद अब टीएमसी ने गुरुवार को उन पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जी टीकाकरण शिविर मामले से भी उनका कनेक्शन जोड़ दिया है। टीएमसी के प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कोलकाता में फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए फर्जी आइएएस अधिकारी देबांजन देब के साथ राजभवन के संबंध का जिक्र करते हुए राज्यपाल को घेरा है। उन्होंने देबांजन के अंगरक्षक के साथ राज्यपाल की दो तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि वह नियमित रूप से राजभवन जाता था। राय ने यह भी दावा किया कि इस सुरक्षा गार्ड के जरिये राजभवन में उपहार भी किसी खास व्यक्ति को गया था। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, तृणमूल के आरोपों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम जानते हैं कि वे (तृणमूल नेता) राज्यपाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे बिना किसी सुबूत के उनके खिलाफ जो कुछ भी कहते हैं, वह अपनी ही विश्वसनीयता को नष्ट कर रहे हैं।

टकराव के बीच राज्यपाल आज विस को करेंगे संबोधित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बजट सत्र की शुरुआत में ममता सरकार के अभिभाषण को हूबहू पढ़ने से मना कर चुके हैं धनखड़
- सत्र के दौरान हिंसा के मुद्दे पर भाजपा भी राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में

बंगाल सरकार और राजभवन के टकराव के बीच राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुक्रवार को बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की अगुआई में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को पहले ही हूबहू पढ़ने से मना कर चुके हैं। ऐसे में अभिभाषण को लेकर टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

अभिभाषण में लिखी ममता सरकार की तारीफ : अभिभाषण में राज्यपाल अपनी तरफ से क्या कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। बजट सत्र के लिए राज्य सरकार ने जो अभिभाषण तैयार करके राजभवन भेजा है उसमें ममता सरकार की विकास योजनाओं व उपलब्धियों सहित राज्य की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त बताया गया है जबकि राज्यपाल इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।

सात को पेश होगा बजट : दूसरी ओर, इस सत्र के दौरान हिंसा व फर्जी टीकाकरण कैंप के मुद्दे पर भाजपा भी ममता सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा का यह सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। सात जुलाई को राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र में विधान परिषद के गठन के लिए भी बिल पेश किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते कुछ विधायकों को अधिवेशन कक्ष की दर्शक दीर्घा और रिपोर्टर्स गैलरी में भी बैठाने की व्यवस्था की जा रही है।

1969 में भी राज्यपाल ने नहीं पढ़ा था लिखा हुआ अभिभाषण

वर्ष 1969 में भी तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने टकराव के कारण संयुक्त फ्रंट सरकार की ओर से दिए गए अभिभाषण को हुबहू पढ़ने से इन्कार कर दिया था। इसकी वजह थी कि राज्यपाल धर्मवीर ने 21 नवंबर 1967 को तत्कालीन संयुक्त फ्रंट मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया था। जब दोबारा 1969 में संयुक्त फ्रंट सत्ता में आया तो धर्मवीर को सरकार ने अभिभाषण में यह पढ़ने को कहा कि उन्होंने संयुक्त फ्रंट की सरकार को अन्यायपूर्वक बर्खास्त कर दिया था। काफी दबाव के बावजूद राज्यपाल ने इसे नहीं पढ़ा जिसे लेकर बाद में काफी हंगामा हुआ।

बंगाल विस के डिप्टी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- बंगाल विस में भाजपा के मुख्य सचेतक ने किया एलान, कारण नहीं बताया

बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में इस पद पर बीरभूम जिले की रामपुरहाट सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक आशीष बंद्योपाध्याय का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। आशीष बंद्योपाध्याय पहले बंगाल के कृषि मंत्री थे। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न देकर डिप्टी स्पीकर बनाने का फैसला किया है।

बंगाल विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा ने कहा कि पार्टी डिप्टी स्पीकर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि, उन्होंने कारण नहीं बताया। दरअसल, भाजपा हाल ही में पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटने वाले मुकुल राय को बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति का चेयरमैन बनाने का कड़ा विरोध कर रही है। माना जा रहा है कि भाजपा इसी को लेकर डिप्टी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।

मुकुल को मिलेगी 65 नंबर वाली महत्वपूर्ण सीट

भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल रॉय को बंगाल विधानसभा में विरोधी दल की सीट पर ही बैठना होगा, क्योंकि अब भी वह भाजपा के विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार उन्हें माकपा के पूर्व विधायक सुजन चक्रवर्ती की 65 नंबर सीट आवंटित की जा सकती है। इस सीट का काफी महत्व है। विरोधी दलों के वरिष्ठ विधायकों को ही यह सीट आवंटित होती आई है। सुजन को माकपा विधायक दल का नेता भी चुना गया था। इस बार माकपा समेत वामदलों का कोई विधायक नहीं है। इसलिए उनकी तरफ से इस सीट का कोई दावेदार भी नहीं है। विधानसभा सूत्रों का कहना है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए विधानसभा में सीटें आवंटित की जा रही हैं।

जन्मदिन के बहाने अखिलेश ने साधा लक्ष्य-2022

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने ढोल-मजीरे के साथ सुंदर कांड का पाठ तो गेट पर ढोल की धुन पर नाचते कार्यकर्ता...। दफ्तर के अंदर व बाहर जश्न का माहौल...और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई देते नेता। मौका था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन का। इस बार का जन्मदिन इसलिए भी खास दिखा क्योंकि वर्ष 2022 का चुनाव मुहाने पर है। अखिलेश ने भी छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर न सिर्फ उनका उत्साह बढ़ाया बल्कि लक्ष्य-2022 पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और वह 2022 के चुनाव में बदलाव के लिए मतदान करेगी।

योगी ने दी फोन पर बधाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फोन कर जन्मदिवस की बधाई दी। योगी ने ट्वीट कर बधाई देने के साथ ही प्रभु श्रीराम से अखिलेश के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना भी की।

कैप्टन के लंच से उठी हिंदू अध्यक्ष की मांग

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़


उपेक्षा होने का लगाया आरोप, हाई कमान दे रहा है सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के संकेत

कांग्रेस हाईकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी देने के संकेतों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को पार्टी के प्रमुख हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया। इस दौरान हुई चर्चा के जरिये हाईकमान को संदेश देने की कोशिश की गई है कि पंजाब में पार्टी अध्यक्ष हिंदू ही होना चाहिए।

बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक के बाद ऐसी सूचनाएं आई थीं कि हाईकमान सिद्धू को पंजाब अध्यक्ष बना सकता है। गुरुवार को कैप्टन ने पार्टी के हिंदू नेताओं को दोपहर के भोजन पर बुलाया। इसमें छह मंत्री, कई विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें शामिल ज्यादातर नेताओं ने कहा कि पंजाब में सिखों के बाद हिंदू सबसे बड़ा वोट बैंक हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। 15 सीटें हिंदू बहुल हैं। कभी यहां हिंदू उम्मीदवार ही चुनाव में उतारे जाते थे, लेकिन वहां जट्ट सिख विधायक हैं। इन नेताओं ने बठिंडा, गुरदासपुर, फिरोजपुर और कोटकपूरा सीट का प्रमुख तौर पर जिक्र किया। बठिंडा से विधायक और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की मौजूदगी में नेताओं ने कहा कि 1992 में बठिंडा से सुरिंदर कपूर (कांग्रेस), 1997 में चिरंजी लाल गर्ग (शिअद), 2002 में सुरिंदर सिंगला (कांग्रेस), 2007 में हरमिंदर जस्सी (शिअद), 2012 में सरूप चंद सिंगला (शिअद) और 2017 में मनप्रीत बादल (कांग्रेस) ने जीत दर्ज की। यानी इन छह चुनाव में से केवल दो बार जट्ट सिख उम्मीदवार जीते, जबकि 1957 से 2017 तक इस सीट पर 14 विधानसभा चुनावों में 11 बार हिंदू उम्मीदवार जीते। इसी तरह गुरदासपुर सीट पर कांग्रेस पहले रमन बहल को आगे करती रही है तो कोटकपूरा में उपेंद्र शर्मा जैसे नेता पार्टी के उम्मीदवार रहे। दो दिन पहले कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके वरिष्ठ नेता अश्वनी सेखड़ी भी लंच में मौजूद रहे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार पंजाब अधीनस्थ सेवाएं बोर्ड के चेयरमैन रमन बहल ने भी कहा कि गुरदासपुर में उन्हें शून्य कर दिया गया है। अनीश सिदाना ने कहा कि हिंदू और ओबीसी वर्ग कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक रहे हैं परंतु सरकार में पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है।

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ नहीं पहुंचे। उनकी गैरहाजिरी चर्चा का विषय रही। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि जाखड़ ने कभी भी पार्टी नेताओं की कोई बैठक ही नहीं बुलाई।

हर हफ्ते चार मंत्री करेंगे जम्मू-कश्मीर का दौरा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों का जायजा लेने और आम जनता और स्थानीय प्रशासन की राय जानने के लिए चार मंत्रियों का एक दल हर सप्ताह केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेगा। दल में शामिल दो मंत्री कश्मीर संभाग और दो जम्मू संभाग का दौरा करेंगे।

यह जानकारी गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुशासन की प्रतिकृति पर शुरू हुए दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में दी। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत जल्द जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू होने जा रहे हैं। हमने यह प्रयोग जनवरी में किया और करीब 35 मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं को शुरू कराया।

अब लद्दाख से भी उठी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग

- कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने गृह राज्य मंत्री से की मुलाकात
- जी किशन रेड्डी ने लद्दाख के विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई


नई दिल्ली में गुरुवार को गृह मंत्रालय पहुंचे लद्दाख के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की मांग के बाद अब लद्दाख से भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मुलाकात के दौरान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने यह मांग उठाई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में वहां से सिविल सोसाइटी समूह समेत कई राजनीतिक नेता शामिल हैं। ध्यान देने की बात है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।

जी किशन रेड्डी ने अपनी ओर से कोई आश्वासन नहीं देकर उनकी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। रेड्डी ने लद्दाख के विकास के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वे जल्द ही कारगिल और लेह का दौरा करेंगे और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को जानेंगे। कांग्रेस पार्टी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता असगर अली करबलाई ने कहा कि हमने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग की। हमारे सदस्यों ने खुले दिल से बात की और केंद्रीय मंत्री ने भी खुले दिल से हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के विकास को लेकर गंभीर है।

उत्तर प्रदेश

नई हवा या पुरानी लहर, बताएंगे पंचायत चुनाव

जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के नतीजों पर टिकी है भाजपा और सपा की नजर, अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की जुगत में भाजपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक-एक सीट के लिए भाजपा और सपा में खींचतान सिर्फ पंचायतों पर झंडा बुलंद करने के लिए नहीं है। इन चुनावों के अंतिम नतीजे ही इशारा करेंगे कि गांवों में सपा की 'नई हवा' वाकई चल पड़ी है या फिर भाजपा की 'पुरानी लहर' का असर अभी बरकरार है। कोरोना की भीषण आपदा और कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बावजूद 'आल इज वेल' का संदेश देने के लिए भाजपा अधिक से अधिक सीटें जीतने की जुगत में है।

जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही है। नामांकन वापसी तक 75 में से 22 सीटों की स्थिति साफ हो गई है। 21 सीटों पर भाजपा तो एक पर सपा के प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बाकी 53 सीटों के लिए चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया तीन जुलाई यानी शनिवार को होनी है। अधिकतर सीटों पर भाजपा और सपा के ही प्रत्याशियों में मुकाबला है। आमने-सामने की टक्कर ने समाजवादी पार्टी के उस दावे को और सहारा दे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सपा मजबूत हो रही है। हालांकि, अब तक जिस तरह से भाजपा ने बढ़त बनाई है, उससे तो भगवा खेमे में ही खुशी की लहर है। चूंकि सपा सत्ता के बाहर है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेल चुकी है, इसलिए वह जितनी सीटें पा जाए, उतना ही मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, जबकि भाजपा के लिए विजय रथ को इस चुनाव में भी आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया है, ताकि भाजपा की लहर बरकरार रहने का संदेश जाए और सपा की नई हवा की काट हो सके। भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि कोरोना की पीड़ा को कुरेदकर विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सत्ताधारी दल 50 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष अपने जितवा लेती है तो वह बड़ा संदेश देने में कामयाब होगी। पार्टी ने उसी के मुताबिक तैयारी भी की है। इसके बाद ब्लाक प्रमुख के चुनावों में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है।

उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव बिना सिंबल के होते हैं। राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशी को घोषित करते हैं। हार झेलने वाले दल इसकी आड़ में बेशक चेहरा छुपाने का प्रयास करें, लेकिन स्थिति साफ हो ही जाती है कि किस दल का पलड़ा भारी रहा। पार्टी की कमजोरी का संदेश जनता में न जाए, शायद इसीलिए बसपा ने इस चुनाव से किनारा कर लिया है। इस लिहाज से लगभग 70 फीसद ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहना कतई गलत न होगा।

बेनतीजा रही कांग्रेस की कसरत

कांग्रेस के रणनीतिकार भी मानते रहे हैं कि प्रदेश की सत्ता पाने के लिए गांवों में पार्टी को मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में सांसद राहुल गांधी ने गांवों में खाट सभाएं कीं, लेकिन सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर भी कामयाबी न मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संगठन की कमान संभाली तो उनका भी जोर गांवों पर खूब रहा। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा दी गई। इस सबके बावजूद पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बहिष्कार से लोन का इन्कार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर की अवाम का ही नुकसान होगा। इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के अपने फैसले को सही ठहराया। बीते सप्ताह हुई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए सज्जाद ने कहा कि इसमें भाग लेना जरूरी था। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के हक में है। अगर यहां से नेता नहीं जाते तो कहा जाता कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे बात नहीं कर सकते, उनके पास कोई आधार नहीं है। बैठक को किसी की हार-जीत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड और चुनाव का आपस में कोई मेल नहीं है। हमें यहां हालात बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। वैसे मेरा मानना है केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा देना चाहिए। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा हक है।

1 जुलाई से जम्मू-कश्मीर में बनिहाल-बारामुला रेल सेवा आंशिक तौर पर बहाल कर दी गई। फिलहाल बनिहाल से बड़गाम के बीच ही ट्रेन चलेगी और कुल क्षमता के 50 फीसद यात्रियों के साथ दिन में दो फेरे ही लगाएगी।

गुलशन हत्याकांड में रऊफ के भाई रशीद को भी हाई कोर्ट से उम्रकैद

फैसला ▶ निचली अदालत ने अब्दुल रऊफ को दी थी आजीवन कारावास की सजा

रऊफ की सजा व टिप्स इंडस्ट्रीज के सहसंस्थापक रमेश तौरानी को बरी करने के फैसले को रखा बरकरार

राज्य ब्यूरो, मुंबई

करीब 24 साल पहले हुए गुलशन कुमार हत्याकांड में मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'कैसेट किंग' की हत्या संगीतकार नदीम सैफी और गैंगस्टर अबू सलेम ने करवाई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अब्दुल रऊफ मर्चेंट की आजीवन कारावास की सजा तो बरकरार रखी ही, निचली अदालत द्वारा बरी किए जा चुके उसके भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन टिप्स इंडस्ट्रीज के सहसंस्थापक रमेश तौरानी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इसे एक नृशंस हत्याकांड करार

▶ हाई कोर्ट ने कहा, नदीम और अबू सलेम ने करवाई थी गुलशन कुमार की हत्या


मिला न्याय : गुलशन कुमार। फाइल फोटो

दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अब्दुल रऊफ के बारे में जो कहा है, हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। उसने बिना किसी कारण के गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाईं और उनकी हत्या कर दी। रऊफ की गुलशन कुमार से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इसके बावजूद उसने नदीम सैफी एवं अबू सलेम के कहने पर यह काम किया, जो गुलशन कुमार के साथ अपनी दुश्मनी निभाना चाहते थे। बता दें कि नदीम सैफी और अबू सलेम, दोनों इस मामले में भगोड़े घोषित किए गए थे। सलेम को बाद में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था, वह अभी कई अन्य मामलों में जेल में है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की सराहना भी की। कोर्ट ने कहा कि हमें घटना के उन प्रत्यक्षदर्शियों की सराहना करनी होगी जो न सिर्फ गुलशन कुमार के ड्राइवर के साथ उन्हें घायलावस्था में अस्पताल ले जाने में साथ रहे, बल्कि अदालत में बेहिचक सच्चाई बयान करने के लिए खड़े भी रहे। मालूम हो कि टी-सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार की 24 साल पहले 12 अगस्त, 1997 को अंधेरी पश्चिम में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामले को व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता का नाम देते हुए टिप्स के सह-संस्थापक रमेश तौरानी को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया था। सत्र न्यायालय ने 29 अप्रैल, 2002 को सुनाए अपने फैसले में इस मामले में आरोपित 19 में से 18 लोगों को बरी कर दिया था। उनमें रमेश तौरानी और अब्दुल रऊफ का भाई अब्दुल रशीद भी शामिल थे। यह फैसला आने के बाद अब्दुल रऊफ ने अपनी सजा के खिलाफ, तो राज्य सरकार ने रमेश तौरानी को बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसले के करीब 19 वर्ष बाद हाई कोर्ट ने इन्हीं याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में रमेश तौरानी का हाथ होने का कोई कारण नजर नहीं आता। लेकिन हाई कोर्ट ने अब्दुल रऊफ मर्चेंट के साथ उसके भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने अब्दुल रऊफ के प्रति कोई रियायत न बरते जाने के निर्देश दिए हैं क्योंकि वह गुलशन कुमार की हत्या के बाद से फरार था। उसे 2001 में गिरफ्तार किया जा सका था। सजा मिलने के बाद जब उसे 2009 में फरलो (कैदियों को मिलने वाली थोड़े दिन की छुट्टी) पर रिहा किया गया था, तब वह निर्धारित अवधि के बाद वापस जेल नहीं पहुंचा था। 2016 में उसे फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। कोर्ट ने उसके भाई अब्दुल रशीद को भी शीघ्र अतिशीघ्र सत्र न्यायालय अथवा मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाने में समर्पण करने के निर्देश दिए हैं। यदि अब्दुल रशीद समर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर सकता है।

गर्मी ने निकाला पसीना, लू के लग रहे थपेड़े

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी व लू का दौर अभी दो दिन और परेशान करता रहेगा। रविवार से जरूर तापमान में थोड़ी कमी आने लगेगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी कहीं-कहीं कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन मानसून की स्थिति में अभी एक सप्ताह तक कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। यानी जहां है वहीं बना रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी-उत्तरी राजस्थान में भी अलग-अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति देखी जा रही है। अभी दो दिन और निचले स्तरों पर पाकिस्तान से उत्तर-पश्चिम भारत की ओर शुष्क पश्चिमी व दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी के तेवर तल्ख ही रहने की संभावना है।

राष्ट्रीय पूर्वानुमान केंद्र का कहना है कि अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थितियों में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। इसके आगे बढ़ने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां बनती नहीं दिख रहीं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डा. एम महापात्रा के मुताबिक दो दिन बाद लू से कुछ राहत मिल सकती है और बढ़ा हुआ तापमान भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। कुछ हिस्सों में गर्जन वाले बादल बनने और हल्की बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन वह मानसून की बारिश नहीं होगी। मानसून के आगमन में अभी समय लगेगा। उन्होंने बताया कि मानसून ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों को कवर किया है, लेकिन 19 जून से कोई प्रगति नहीं देखी गई है। मध्य-अक्षांश पछुआ हवाएं, प्रतिकूल मैडेन-जूलियन आसीलेशन (एमजेओ) और कम तापमान की अनुपस्थिति-बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर दबाव प्रणाली कुछ कारण हैं।

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से आ रही गर्म हवा का असर दो दिन और रहेगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी।

दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा नौ साल का रिकार्ड : दिल्ली में अधिकतम तापमान ने नौ साल का रिकार्ड तोड़ दिया। दिन के साथ-साथ रातें और सुबह भी गर्म होने लगी हैं।


नई दिल्ली में गुरुवार को गर्मी के सितम से बचने के लिए मुंह ढककर गुजरती महिला। प्रेट्र

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर	तापमान
श्रीनगर	33.8
जम्मू	42.9
धर्मशाला	31.4
शिमला	27.8
देहरादून	37.6
अमृतसर	41.0
पटियाला	42.3
भटिंडा	44.0
चंडीगढ़	40.6
गुरुग्राम	44.7
लखनऊ	39.4
अलवर	44.0

(डिग्री सेल्सियस में)



गांव में घुसा मगरमच्छ...

कर्नाटक के कारवार कस्बे में गुरुवार को कोगिलबाना गांव में लोग उस वक्त हैरान रह गए, जब उन्हें गली में एक मगरमच्छ विचरण करता दिखा। समीप की काली नदी से गांव में घुसे इस मगरमच्छ से डरे ग्रामीणों ने फौरन वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित पकड़ वापस नदी में छोड़ दिया। गनीमत रही कि मगरमच्छ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अधिकारियों के मुताबिक नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं। प्रेट्र

लश्कर ने पूरे देश में आतंकी हमलों की साजिश रची

दरभंगा ब्लास्ट

▶ जांच और आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी

▶ एनआइए ने इमरान व नासिर के घरों की ली तलाशी

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा दरभंगा जंक्शन ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए दो आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि लश्कर ए तैयबा पूरे देश में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। एनआइए के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि घटनास्थल के निरीक्षण, जांच टीम से मिली जानकारी और आरोपितों से पूछताछ में यह सामने आया है कि लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर देशभर में आतंकी हमलों से बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान के मंसूबे बना रहे थे।

एनआइए ने इस मामले में हैदराबाद से लश्कर ए तैयबा के इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और उसके भाई मु. नासिर खान को बुधवार को गिरफ्तार किया था। बता दें, पिछले महीने दरभंगा रेलवे स्टेशन में एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था जिसकी जांच एनआइए कर रही है।

एनआइए ने न्यू मेलापल्ली में दोनों आतंकियों के घरों की तलाशी ली और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बरामद सामग्री आइईडी बनाने से संबंधित है। बता दें, 17 जून को मामले की जांच हाथ में लेने के बाद एनआइए ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले इमरान और नासिर पर शिकंजा कसना शुरू किया था।

एनआइए के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर दोनों आरोपितों ने आइईडी बनाकर एक पार्सल में पैक की और ट्रेन में रख दी। इनका मकसद चलती हुई ट्रेन में विस्फोट के साथ आग लगाना था। एनआइए का कहना है कि नासिर खान 2012 में पाकिस्तान जा चुका है और वहां लश्कर के आतंकियों से आइईडी बनाना सीखा। प्रवक्ता के अनुसार, पूरी साजिश का पता लगाने के लिए आरोपितों से विस्तृत पूछताछ और जांच जारी है।

उधर, पटना से जागरण संवाददाता के अनुसार, एनआइए कोर्ट में दोनों आरोपितों की पेशी पर गुरुवार को पूरे दिन एयरपोर्ट से लेकर अदालत परिसर तक माहौल गर्म रहा। एनआइए ने गुरुवार को आरोपितों की पेशी पटना स्थित कोर्ट में करने की जानकारी दी थी। शुक्रवार को आंतकियों को कोर्ट में पेशी के आसार हैं।

तीन वर्षों में 300 से अधिक परिवारों का मतांतरण

रामानुज मिश्र, अंबेडकरनगर

अंबेडकरनगर के माली थाने में गांव-गांव चंगाई सभा लगाकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इनके निशाने पर खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोग एवं कम पढ़ी-लिखी आबादी है। मालीपुर थाने के एक दर्जन से अधिक गांवों में तीन साल के अंदर करीब तीन सौ परिवारों का मतांतरण कराया गया है। इनमें से कुछ परिवारों के सदस्यों ने ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दर्जनों गांवों में फैला है नेटवर्क : अल्लीपुर कोड़रा गांव की दलित बस्ती के 50 से अधिक परिवार इसकी जद में हैं। यहां के प्रधान कमलेश वर्मा ने बताया कि कई परिवार चंगाई सभा में शामिल होते हैं, लेकिन लिखापढ़ी में अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। कालेपुर महुअल के राजितराम ने बताया कि उनके घर के पास ही सभा लगती है। यहां 60-70 लोगों की भीड़ जुटती है और हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। विरोध करने पर मारने की धमकी देते हैं। इसी तरह ऊसरपुर, धमरुआ, नेमपुर, हुसैनपुर, विपहन, नूरपुर कला, चितौना कला, श्यामपुर, इटौरी, कुढ़ा मोहम्मदपुर आदि गांवों में मिशनरियों का जाल बिछा है।

एसओ मालीपुर के खिलाफ चल रही जांच : मतांतरण में एक थानाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है। स्थानीय भाजपा नेता अरविंद पांडेय ने आइजी से मालीपुर थाने के एसओ विवेक वर्मा की भूमिका की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे। करीब 10 दिन पहले आइजी ने अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय को जांच सौंप जल्द इसकी रिपोर्ट मांगी थी।

तीन पर हो चुकी है कार्रवाई : स्थानीय भाजपा नेता अरविंद पांडेय की शिकायत पर बीते सोमवार को पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। चालान के बाद कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मतांतरण का उदाहरण : परशुराम प्रजापति का एक ही बेटा है। उसे एमए-बीएड तक की पढ़ाई कराई। शादी के बाद उसका व्यवहार गड़बड़ाने लगा। करीब दो साल पहले प्रदीप की तबीयत खराब रहने लगी। इस बीच पड़ोस के गांव बसिया में लगने वाली चंगाई सभा में जाने वाला जगपत उनके घर आने-जाने लगा। उसने प्रदीप को ईसा मसीह के जादू से ठीक होने का विश्वास दिलाया।

प्रदीप भी हर रविवार सभा में जाने लगा। यहां प्रदीप से कहा गया कि उसके घर वाले हिंदू हैं, इसीलिए वह बीमार है। मतांतरण करते ही उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। घर वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन जगपत आदि ने उसे घर-गाड़ी आदि का प्रलोभन देकर मतांतरण करा दिया। साल भर पहले प्रदीप ने पिता का हाथ तोड़ दिया और मां को भी पीटा। मालीपुर थाने में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मतांतरित युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश

जासं, नई दिल्ली : इस्लाम अपनाने के बाद रेनू गंगवार से आइशा अल्वी बनी युवती को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त व जामिया नगर एसएचओ को निर्देश दिया कि पांच जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक याची को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी युवती ने याचिका में आरोप लगाया था कि उसके इस्लाम मत स्वीकार करने की वजह से उसे व उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

फरीदाबाद के एक परिवार का मतांतरण करा चुका है उमर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : उत्तर प्रदेश में मतांतरण के मामले ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। पता चला है कि मुख्य आरोपित उमर गौतम यहां एनआइटी के एक परिवार का मतांतरण करा चुका है। उमर गौतम औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में भी सक्रिय रहा है और करीब सात साल पहले यहां के एनआइटी क्षेत्र के एक नंबर में रहने वाले एक परिवार का मतांतरण करा चुका है।

मतांतरण का विरोध करने पर पिता-पुत्र को किया लहूलुहान

जासं, शिवली (कानपुर देहात) : कानपुर देहात के शिवली के मकरंदापुर मलिक गांव में पिता-पुत्र को पड़ोसियों ने लाठी-डंडे व धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। घायलों का आरोप है कि आरोपितों ने पहले खुद मतांतरण किया और अब गांव के लोगों को भी बरगला रहे हैं। इसी बात का विरोध करने पर हमला किया गया। पुलिस ने पांच आरोपितों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मकरंदापुर मलिक निवासी सुमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उसके गांव का राजू सिंह करीब एक साल पहले युश्मान खां बन गया है।

न्यूज गैलरी

सजा पूरी कर आज तिहाड़ से रिहा होंगे ओपी चौटाला

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला शुक्रवार को सुबह साढ़े नौ बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही उनकी रिहाई हो जाएगी। (राब्यू)

अति कुपोषित बच्ची को मां ने जिंदा दफनाया

हरदोई : उप्र के हरदोई में लोनार क्षेत्र के मुंगलापुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मानसिक मंदित महिला ने अपनी अति कुपोषित बच्ची को जिंदा दफना दिया। बच्ची का सिर खुला रहा। गांव वालों की सूचना पर पहुंची चाइल्ड लाइन टीम ने बच्ची को पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती कराया है। सकरौली निवासी भगवानदीन ने करीब 10 वर्ष पहले बिहार से राजकुमारी को लाकर उससे शादी कर ली थी। उसके तीन बच्चे धर्मवीर, नंदनी और सबसे छोटी तीन वर्ष की मधु है। चाइल्ड लाइन के समन्वयक अनूप तिवारी ने बताया कि राजकुमारी मानसिक मंदित है। पोषण केंद्र पर उसने बताया कि नदी पार उसके पति का खेत है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। (जासं)

केक काटकर 'मृतक' ने मनाया पुनर्जन्मदिन

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : उप्र आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के खलीलाबाद गांव में जन्म लेने वाले लालबिहारी ने इस बार भी अनोखा आयोजन किया। कागजों में जिंदा होने के बाद अपना 27वां पुनर्जन्मदिन मनाया और केक काटकर लोगों के बीच खुशियां मनाईं। सिविल लाइन स्थित एक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एलान किया कि अगले वर्ष पत्नी के साथ दोबारा शादी रचाकर सरकार को संदेश देंगे। तर्क दिया कि 1994 में अगर कागजों में मुझे जिंदा किया गया तो उस हिसाब से मेरी उम्र मात्र 28 वर्ष होगी और मैं शादी का हकदार भी हूं। सरकारी दस्तावेज में 18 वर्ष तक मृत रहने वाले लालबिहारी ने अपने नाम के आगे मृतक जोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि मृतक संघ, ट्रस्ट बनाकर जनता की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 30 जुलाई, 1976 को जीते जी मृत घोषित कर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर अपमानित किया गया।

आंदोलनकारियों के बीच दो घंटे फंसे रहे पंजाब भाजपा अध्यक्ष

जासं, गढ़शंकर (होशियारपुर)

▶ कार्यक्रम में शामिल होने गए थे अश्वनी शर्मा, दो घंटे बाद पुलिस ने निकाला

▶ पुलिस अधिकारियों की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे प्रदर्शनकारी

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पंजाब में भाजपा नेताओं के घेराव का कोई मौका नहीं चूक रहे। गुरुवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा को करीब दो घंटे तक रोके रखा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बाद में पहुंची पुलिस ने बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकाला।

जानकारी के मुताबिक अश्वनी शर्मा बीनेवाल गांव में स्वामी कृष्णानंद कुटिया वालों से मिलने पहुंचे थे। पता चलते ही किसान संगठनों के लोग पहुंच गए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। दो घंटे के बाद पुलिस अधिकारियों ने अश्वनी शर्मा की गाड़ियों को वहां से निकाल कर जैजों-दोआबा के रास्ते पठानकोट रवाना किया।

पूर्व सांसद घुबाया के खिलाफ की नारेबाजी

उधर, फाजिल्का के मंडी लाधूका के पास किसानों ने कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद शेर सिंह घुबाया का घेराव किया। इस दौरान पूर्व सांसद व किसानों के बीच काफी बहस हुई। घुबाया ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार शुरुआत से ही किसानों के साथ है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। वह मंडी में न तो वोट मांगने गए और न कोई बैठक करने। वह तो अपने रिश्तेदार के साथ मिलने जा रहे थे।

माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : उप्र की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। अब माफिया की अवैध तरीके से अर्जित चल व अचल संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक बीते साल गाजीपुर जिले के दक्षिणटोला थाने में विकास कंस्ट्रक्शन और उसके पार्टनर आतिफ के खिलाफ धोखाधड़ी व सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस को जांच में पता चला था कि विकास कंस्ट्रक्शन नामक फर्म मुख्तार अंसारी की बीवी अफासा अंसारी, उसके साले सरजील उर्फ आतिफ रजा तथा अनवर शहजाद, रविंद्र नारायण, जाकिर हुसैन के नाम है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में छग के एडीजी के 15 ठिकानों पर छापेमारी

नईदुनिया, रायपुर

▶ उनके ड्राइवर, सीए व कंप्यूटर आपरेटर के घर पर भी पड़े छापे

▶ खदानों में निवेश के साथ ओडिशा से भी जुड़ रहे तार

आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) गुरजिंदर पाल (जीपी) सिंह के 15 ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। एसीबी की टीम ने 1994 बैच के आइपीएस सिंह के ड्राइवर, सीए और कंप्यूटर आपरेटर के घर पर भी छापे मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं, सिंह के खिलाफ आयकर विभाग भी बेनामी एक्ट के तहत अलग से कार्रवाई कर रहा है।

एसीबी के आलाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राजनांदगांव और भिलाई समेत ओडिशा में भी सुबह छह बजे एक साथ छापे मारे गए, जहां सिंह की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में बेनामी संपत्तियां अर्जित करने के प्रमाण मिले हैं। एडीजी ने वहां केंदुजर जिले के बड़बिल शहर में खदान में निवेश किया है। टीम ने अब तक जमीन, मकान, खदान में निवेश के साथ एक दर्जन गाड़ियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। सिंह के रायपुर स्थित निवास पर 20 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रहे थे। उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही थी। वीआइपी रोड स्थित शगुन फार्म हाउस और प्रीतपाल सिंह के घर पर भी जांच चल रही थी। प्रीतपाल सिंह शगुन फार्म के मालिक हैं और सिंह के दोस्त हैं।

दोनों एजेंसियों के प्रमुख रह चुके हैं सिंह : जीपी सिंह प्रदेश के पहले आइपीएस हैं, जिस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। जीपी सिंह खुद भी एसीबी व ईओडब्ल्यू के चीफ रह चुके हैं। विवाद के बावजूद सिंह बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जैसे तीन बड़े रेंज के आइजी रह चुके हैं।

बेनामी एक्ट के तहत आयकर विभाग ने शुरू की जांच : एसीबी के आलाधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आए प्रामाणित तथ्यों के आधार पर केस दर्ज किया गया। छापे की प्रक्रिया अब भी जारी है, जिसके शुक्रवार देर रात तक चलने की संभावना है। सिंह के खिलाफ आयकर विभाग भी बेनामी एक्ट के तहत अलग से कार्रवाई कर रहा है।

सिंह का विवादों से है पुराना नाता : 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी जीपी सिंह एक बार बस्तर एसपी रहते चर्चा में आए थे। उन्होंने रेंज आइजी एमडब्ल्यू अंसारी के सरकारी बंगले पर छापा मारा था। इस दौरान उन्होंने अंसारी के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के कमरे की तलाशी ली थी। उन पर मैडल के चक्कर में ग्रामीणों को नक्सली बता कर आत्मसमर्पण कराने का भी आरोप लग चुका है। एसीबी का चीफ रहते हुए आइपीएस मुकेश गुप्ता (88 बैच) के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले की भी डायरी जीपी के ही कार्यकाल में खुली थी। तब सरकार ने उन्हें एसीबी प्रमुख से हटा दिया था। आइजी के रूप में जीपी को बिलासपुर पहला रेंज मिला था। उनके साथ राहुल शर्मा को बिलासपुर का एसपी बनाया गया था। पोस्टिंग के दो महीने बाद ही राहुल शर्मा ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। इस दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने एरोगेंट बास का जिक्र किया था।

बिकरू कांड का एक साल

बदनामी का दाग, बेटी और नौकरी देने से कतराते लोग

बिकरू के दुर्दांत अपराधी विकास की करनी की सजा भुगत रहे ग्रामीण, तमाम ग्रामीणों के सामने परिवार चलाने को लेकर भी हैं मुश्किलें

जागरण संवाददाता, कानपुर

कानपुर के बिकरू कांड को लेकर एक साल बाद भी गांव की बदनामी के दाग साफ नहीं हो सके हैं। यहां के लोगों को रिश्ते तय करने और आजीविका चलाने के लिए नौकरी पाने में मुश्किलें हो रहीं हैं। गांव का नाम सुनते ही लोग मुंह फेर लेते हैं।

बिकरू कांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की करनी की सजा ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है। गांव वालों के मुताबिक, कहीं काम मांगने जाओ या फिर बेटी-बेटा का रिश्ता करने की बात पर लोग अनदेखी करते हैं। काम नहीं मिलता है। गांव की कलावती, शिवदेवी, खुदाबक्श, राम किशन, कल्लू, मोहन लाल आदि ने बताया कि कई बार नौकरी और बच्चों के रिश्ते के लिए गांव का नाम तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन जुड़ाव सामने आते ही लोग इन्कार कर देते हैं। किसान मन्नू ने बताया कि खेत जोताई के लिए दूसरे गांव के लोग ट्रैक्टर भी नहीं भेजते हैं। विकास के रहते ट्रैक्टर देने से कोई इन्कार भी नहीं कर पाता था। एक महिला ने अपना दुखड़ा सुनाया कि उनके परिवार को भी बिकरू कांड की बदनामी मिली है। बेटी का रिश्ता भी टूटा और पति की नौकरी भी चली गई। बदनामी का यह दाग पता नहीं कब तक टीस देता रहेगा।

▶ सात पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा हुई थी

▶ अब तक सिर्फ एक शहीद के स्वजन को नौकरी मिल सकी

यह है बिकरू कांड

पिछले साल दो जुलाई की रात विकास दुबे और उसके सहयोगियों ने बिकरू गांव में सीओ सहित आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी।

शहीद बबलू के भाई को छोड़ किसी की नहीं मिली नौकरी : बिकरू कांड में शहीद हुए तत्कालीन सीओ और बाकी सात पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ एक शहीद के स्वजन को नौकरी मिल सकी है। तीन परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए तीन वर्ष की मोहलत ले ली थी, लेकिन बाकी चार परिवार अब तक इंतजार कर रहे हैं। एक सिपाही राहुल की पत्नी तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अव्वल आ चुकी हैं। शहीद सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा की बड़ी बेटी वैष्णवी ने विशेष कार्याधिकारी के पद के लिए आठ जनवरी, 2021 को प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय लखनऊ में दाखिल किया था। अगले ही महीने यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसी तरह सिपाही सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला की ओर से उपनिरीक्षक पद के लिए पांच जनवरी, 2021 को प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। दारोगा अनूप कुमार सिंह की पत्नी नीतू सिंह की शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 जून को ही हुई है। सिपाही राहुल कुमार की पत्नी दिव्या भारती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 11 फरवरी 2021 को लखनऊ में हुई थी, जिसमें वह अव्वल रहीं थीं। दिव्या ने बताया कि पति की मौत के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई हैं, लेकिन फिर भी अपनों के लिए जी-जान से मेहनत कर रही हैं, जिससे पति के सपने को साकार कर सकें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहीद सिपाही बबलू कुमार के भाई उमेश की पिछले माह 19 जून को ही कांस्टेबल पद पर नौकरी लगी है। इन दिनों पुलिस लाइन में प्रशिक्षण चल रहा है। शहीद दारोगा महेश यादव, नेबू लाल व सिपाही जितेंद्र के परिवारों ने उपनिरीक्षक पद पर आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय मांगा है। उनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आइजी कानपुर परिक्षेत्र मोहित अग्रवाल ने बताया कि शहीदों के आश्रितों को नौकरी दिलवाने की प्रक्रिया चल रही है। तीन ने समय मांगा है। बाकी सभी को जल्द ही मिल जाएगी।

न्यूज गैलरी

स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाले विज्ञानियों को मिले भारत रत्न

रांची : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाले विज्ञानियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। (राब्यू)

कर्नाटक में दिवंगत हुए कोविड वारियर्स का बनेगा स्मारक

बेंगलुरु : कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में 'शहादत' देने वाले डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सम्मान में बेंगलुरु में पहला कोविड वारियर स्मारक बनाया जाएगा। (प्रेट्र)

अनाथ हुए छात्रों की फीस माफ करेगा आइसीएआइ

धनबाद : कोरोना महामारी में अपने माता-पिता व अभिभावकों को खो चुके छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखता हुए द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) ने उनकी फीस माफ करने की घोषणा की है। (जासं)

गंगाजल से कोरोना उपचार, आइसीएमआर व केंद्र को नोटिस

जागरण संवाददाता प्रयागराज

गंगा जल से तैयार नोजल स्प्रे के क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति के लिए दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन कार्उसिल फार मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) एवं भारत सरकार की नैतिकता समिति (इथिक्स कमेटी) को नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता व गंगा पर हाई कोर्ट के एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अरुण कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है।

अधिवक्ता गुप्ता का कहना है कि मार्च, 2020 में मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था जिसे भरत झुनझुनवाला के साथ मिलकर आइसीएमआर के सामने रखा गया। इसका वर्चुअल प्रजेंटेशन भी हुआ, लेकिन आइसीएमआर ने क्लीनिकल डाटा की मांग कर इसे नकार दिया। इसके बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डा विजय नाथ मिश्र से डाटा तैयार करने का आग्रह किया। उनके नेतृत्व में पांच डाक्टरों की टीम ने प्रारंभिक सर्वे में पाया है कि नियमित गंगा स्नान और गंगाजल के सेवन से कोरोना संक्रमण का असर तनिक भी नहीं है। इस शोध को इंटरनेशनल रिव्यू कमेटी के सामने रखा गया, उनके रिव्यू के बाद यह इंटरनेशनल जर्नल आफ माइक्रो बायोलाजी में प्रकाशित हुआ। याचिका में कहा है कि डाक्टरों की टीम ने 617 लोगों पर रिसर्च किया। इसमें से 317 लोगों को गंगा जल दिया गया जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव रही। फिर गंगोत्री से लिए गए गंगाजल से नोजल स्प्रे तैयार किया गया। फिर पूरा डाटा इथिक्स कमेटी को भेज कर क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी, किंतु कोई निर्णय नही लिया गया।

वायरो फेज थिरेपी से कोरोना को खत्म करने का दावा : बीएचयू के डाक्टरों का दावा है कि वायरो फेज थिरेपी से कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन है वे वायरस को निष्क्रिय करती हैं, जब कि गंगा जल से प्रस्तावित नोजल स्प्रे वायरस को खत्म करता है। बीएचयू के डाक्टरों की टीम ने आइसीएमआर व आयुष मंत्रालय को क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति के लिए शोध प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनकी ओर से कोई रुचि नहीं ली गई और पहले इसे जानवरों पर प्रयोग की बात कही गई। याचिका में मांग की गई है कि आयुष मंत्रालय व आइसीएमआर को डा. वीएन मिश्र की टीम को क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति देने का समादेश जारी किया जाय तथा पुणे के वायरोलाजी लैब मे गंगा जल से तैयार स्प्रे का टेस्ट कराया जाय।

एनएमसीजी को सौंपे है सभी शोध पत्र : याची अरुण कुमार गुप्ता ने 28अप्रैल 2020 को सभी शोधपत्र नेशनल क्लीन गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भेजा है। महानिदेशक आइसीएमआर को भी देकर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की मांग की है। याची गंगा प्रदूषण मामले में जनहित याचिका मे एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) हैं। ऐसी ही रिपोर्ट भरत झुनझुनवाला ने भी भेजी है।

जनहित याचिका

- इलाहाबाद हाई कार्ट ने मांगा सभी पक्षों से छह सप्ताह में जवाब
- गंगा जल से तैयार नोजल स्प्रे के क्लीनिकल ट्रायल की मांग



उपकारी गंगा जल। फाइल फोटो

राष्ट्रपति को भी भेजा है शोध प्रस्ताव

अधिवक्ता अरुण के मुताबिक शोध प्रस्ताव राष्ट्रपति को भी भेजा गया है जिसमें दावा किया गया है कि गंगा जल का क्लीनिकल ट्रायल कर कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। याची का कहना है कि 1896 मे ब्रिटिश वैक्टीरियोलाजिस्ट अनेस्ट हाकिंस ने गंगा जल पर शोध किया था। उनकी रिपोर्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल मे छपी थी। गंगोत्री के जल मे सेल्फ प्यूरीफाइंग क्वालिटी पाई गई थी। अन्य कई देशो की पत्रिका मे भी शोध पत्र छपे हैं।

वैक्सीन से लकवा से राहत का दावा, डाक्टर बोले-शोध जरूरी

नईदुनिया, कवर्धा

- छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के घनश्याम ने वीडियो जारी कर किया दावा

छत्तीसगढ में कवर्धा जिले के ग्राम मारियाटोला निवासी घनश्याम वर्मा ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद उनको लकवे (पैरालिसिस) की समस्या में काफी फायदा मिला है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि लकवा के कारण दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब काम करने लगा है। वह फिर दाएं हाथ से खाना खाने लगे हैं और थोड़ा वजन भी उठाने लगे हैं। उनके दावे पर सीएमएचओ डाक्टर एसके मंडल ने कहा कि यह शोध का विषय है।

घनश्याम वर्मा ने इस बावत एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनको तीन वर्ष पहले लकवा मार गया था, जिससे उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। कई डाक्टरों से इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उन्होंने पिछले दिनों कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद शरीर में कई तरह के बदलाव महसूस किए। अब वह फिर दाएं हाथ से खाना खाने लगे हैं और थोड़ा वजन भी उठाने लगे हैं।

इस बारे में जब सीएमएचओ डाक्टर एसके मंडल ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। कोई वैक्सीन हो, उसके रिएक्शन होते हैं। यदि वैक्सीन से पैरालिसिस ठीक होने का दावा किया जा रहा है तो यह शोध का विषय है। उन्होंने कहा कि साइकोलाजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। हालांकि इस तरह के अनुभवों का भी गौर से अध्ययन किया जा रहा है।



लकवे से परेशान। फाइल फोटो

3 साल पहले लकवा मारने के कारण नहीं काम कर रहा था दायां हाथ, अब मिली राहत

टीकाकरण में स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन कर्मियों को प्राथमिकता

जिंदगी का टीका ▶ केंद्र ने वैक्सीन लगाने में गरीबों को छोड़ने और अमीरों को तरजीह देने के आरोप को नकारा

टीकाकरण कार्यक्रम महामारी विज्ञान के सबूतों पर है आधारित

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसका टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चों (फ्रंटलाइन) पर कार्यरत कर्मियों के साथ सबसे संवेदनशील वर्गों की रक्षा कर देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। इसके साथ ही सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कथित तौर पर टीकाकरण रणनीति में बुजुर्गों और असुरक्षित/संवेदनशील वर्गों को छोड़ने और अमीरों को तरजीह देने का आरोप लगाया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान से जुड़े सबूतों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों और दुनिया की सबसे बेहतरीन परिपाटी के आधार पर तैयार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण के हर पहलू की व्यवस्थित योजना बनाई गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभावी एवं कुशल योगदान से इसे लागू किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि सरकार की कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता शुरुआत से ही अटूट और सक्रिय है।

बयान में कहा गया कि मीडिया में कुछ खबरें आई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि देश की टीकाकरण रणनीति में बुजुर्गों और असुरक्षित आबादी को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसमें आगे दावा किया गया है कि नीति अमीरों को विशेषाधिकार देती है।

मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान के सबूतों पर आधारित है, यह पेशेवरों, स्वास्थ्य एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों की रक्षा कर देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने को प्राथमिकता देता हैं, इसके साथ ही आबादी के सबसे असुरक्षित समूह की रक्षा करता है।

बयान में कहा गया कि इस रणनीति के सकारात्मक नतीजे आए हैं। अबतक पंजीकृत 87.4 फीसद स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसी प्रकार पंजीकृत अग्रिम मोर्चे के करीब 90.8 फीसद कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। इस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर में इस समूह की रक्षा की गई जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, निगरानी और संक्रमण के कार्यों को रोकने में शामिल रहे।

मंत्रालय ने कहा कि अबतक 45 साल से अधिक उम्र के करीब 45.1 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 60 साल से अधिक उम्र के बड़े 49.35 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है।

बयान में कहा गया कि 21 जून को लागू संशोधित टीकाकरण नीति में टीका उत्पादकों और नए टीके विकसित करने वाले को प्रोत्साहित करने का प्रविधान है। घरेलू उत्पादकों को सीधे निजी अस्पतालों को टीका मुहैया कराने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इसकी सीमा मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत रखी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि आय सीमा से परे सभी नागरिक भारत सरकार की योजना के तहत मुफ्त टीके के लिए योग्य हैं। जिनकी क्षमता भुगतान की है उन्हें निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्र के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि जल्द से जल्द सभी को टीका लगवाया जा सके।



नई दिल्ली में पुलिस की ओर से बच्चों की कोरोना जांच के लिए खिलौनों से युक्त वैन लांच की गई है। इसमें बैठकर बच्चे बिना डरे जांच करवा सकते हैं। गुरुवार को इस वैन में एक बच्ची का स्वैब सैंपल लेता स्वास्थ्यकर्मी। एएफपी

राज्यों के पास टीके की 1.24 करोड़ से ज्यादा डोज : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरवार को बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी कोरोनारोधी टीके की 1.24 करोड़ से ज्यादा खुराकें उपलब्ध हैं। अगले तीन दिनों में उन्हें 94,66,420 और डोज उपलब्ध करा दी जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 32.92 करोड़ डोज की आपूर्ति कर चुकी है। इनमें बर्बाद हुई 31,67,50,891 डोज भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास अब भी 1,24,50,909 से ज्यादा खुराकें हैं।

गुरुवार सुबह आठ बजे कोरोना की स्थिति

नए मामले	48,786
कुल मामले	3,04,11,634
मौतें	1,005
कुल मौतें	3,99,559
कुल सक्रिय मामले	5,23,257
ठीक होने की दर	96.97 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.54 फीसद
मृत्यु दर	1.31 फीसद
जांचें (बुधवार)	19,21,450
कुल जांचें	41,20,21,494

टीकाकरण की राज्यवार स्थिति

राज्य	संख्या (लाख में)
उत्तर प्रदेश	3.42
मध्य प्रदेश	9.65
राजस्थान	0.54
बिहार	2.00
झारखंड	0.32
पंजाब	0.18
हरियाणा	1.86
उत्तराखंड	0.42
बंगाल	1.14
महाराष्ट्र	2.74
दिल्ली	1.57

वैक्सीन कार्ड दिखाओ, राशन पाओ

जासं, मैनपुरी

यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। आपके पास कार्ड है, तो आपको राशन की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पेट्रोल व डीजल भी तुरंत मिलेगा, साथ ही गैस सिलेंडर भी बिना इंतजार के मिलेगा। वैक्सीन लगवाने को जागरूक करने के लिए उप्र के मैनपुरी में जिला पूर्ति अधिकारी ने नई पहल की है। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।

कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जिले में उत्सुकता का अभाव नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन में मैनपुरी जिले का प्रदेश में 65वां स्थान आया है। अब 12 विभाग जागरूकता के साथ प्रोत्साहन देने को जुटे हैं। जिला पूर्ति विभाग भी खास पहल के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) यूआर खान ने राशन कोटेदार, गैस एजेंसी संचालक और पेट्रोल पंप संचालकों को खास पहल के साथ योगदान निभाने को कहा है। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

स्पूतनिक लाइट टीके के आपात इस्तेमाल को नहीं मिली मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के औषधि नियामक ने रूस के कोविड रोधी टीके स्पूतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है। यह टीका सिंगल डोज का है।

विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की बैठक में सुझाई गई सिफारिशों के अनुसार स्पूतनिक लाइट भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे स्पूतनिक वी बना है। जिसके सुरक्षित होने को लेकर भारतीय आबादी में पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, इसलिए इसी तरह का अलग से एक और परीक्षण करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त दिखते हैं। इन सिफारिशों को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने भी मंजूर किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड की गई एसईसी की सिफारिशों में कहा गया कि डाक्टर रेड्डीज लैबोरैटरीज ने डीसीजीआइ को एक प्रस्ताव सौंपा था और रूस में पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के आंकड़ों के आधार पर स्पूतनिक लाइट के लिए बाजार संबंधी अनुमति मांगी थी। भारत में तीसरे चरण का परीक्षण करने के लिए समिति के समक्ष एक प्रोटोकाल प्रस्तुत किया था।

सीडीएससीओ की एसइसी ने आवेदन पर विचार करने के बाद उल्लेख किया कि स्पूतनिक लाइट भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे स्पूतनिक वी बना है।

समिति ने यह भी उल्लेख किया कि रूस में तीसरे चरण का परीक्षण जारी है और स्पूतनिक लाइट के प्रभाव संबंधी आंकड़े अभी आने बाकी हैं।

योगी के कोविड मैनेजमेंट की आस्ट्रेलिया में तारीफ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी के कोविड मैनेजमेंट का डंका आस्ट्रेलिया में भी बज रहा है। बेहतर कोरोना प्रबंधन के दम पर वायरस को काबू करने में मिली सफलता की आस्ट्रेलिया के संसद सदस्य क्रैग कैली ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों के कारण डेल्टा वैरिएंट को यूपी रोकने में सफल रहा।

क्रैग कैली ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूपी के संक्रमण की तुलना की। उन्होंने सही वक्त पर आइवरमेक्टिन दवा का प्रयोग करने के यूपी के फैसले की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी में आइवरमेक्टिव दवा मरीजों को खिलाए जाने का ही नतीजा है कि 17 लाख संक्रमितों में से 22,601 रोगियों की मौत हुई। यूपी में अब प्रतिदिन डेढ़ सौ से कम रोगी मिल रहे हैं। उधर यूके की आबादी करीब साढ़े छह करोड़ है, लेकिन यहां पर आइवरमेक्टिन दवा का प्रयोग नहीं किया गया।

दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन होगी

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

डा. पाल कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे निकट भविष्य में वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन करेंगे। उनका अधिकांश अध्ययन पूरा हो गया है। हमें उम्मीद है कि वे बहुत जल्द अपने नतीजे पेश करेंगे। हम इस टीके के लिए काफी आशान्वित हैं क्योंकि यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन होगी। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से के रूप में केंद्र के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

भारत ने कोरोना के खिलाफ कोवैक्सिन (भारत बायोटेक), कोविशील्ड (सीरम इंस्टीट्यूट) और रूसी स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। इसके अलावा मार्डना वैक्सीन के आयात को हाल ही में मंजूरी दी गई है।

जायकोवी-डी तीन डोज वाला टीका है। पहला टीका लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। कंपनी ने कहा है कि वह दो-डोज वाली वैक्सीन पर भी काम कर रही है। इसका डाटा भी पेश कर दिया गया है। इस वैक्सीन के स्टेबिलटी डाटा से पता चला है कि जायकोवी-डी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए दो से आठ डिग्री सेल्सियस तक भंडारण करना होगा वहीं अल्पावधि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर भी इसे स्टोर किया जा सकता है।

सीरम को बच्चों पर कोवोवैक्स के परीक्षण की अनुमति नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञ पैनल ने बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआइआइ) को दो से 17 साल की उम्र के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की।

फिर मिलने लगे बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित

ऋषि दीक्षित, कानपुर

अब फिर बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं। ये बेहद घातक साबित हो रहे हैं। संक्रमण का पता नहीं चलने से वह जहां-तहां घूमते रहते हैं और जाने-अनजाने अपने साथियों, स्वजन और सहयोगियों को संक्रमित कर रहे हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से उनमें कोरोना के लक्षण नहीं उभरते हैं और किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती, लेकिन ऐसे व्यक्ति कोरोना वायरस के कैरियर (वाहक) का काम करते हुए घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थल पर दूसरों तक संक्रमण पहुंचा रहे हैं।

मधुमेह और दूसरी बीमारियों से पीड़ितों को ज्यादा खतरा : बिना लक्षण वाले संक्रमित के बोलने या खांसने पर ड्रापलेट के साथ कोरोना का वायरस निकलता है। इससे मधुमेह, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर, कैंसर और इम्यूनो डिसआर्डर से पीड़ित उनके संपर्क में आकर संक्रमण की चपेट में आते हैं, जो उनके लिए घातक होता है।

केस-एक : कानपुर निवासी 26 वर्षीय युवक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बाहर आना-जाना रहता है। विदेश यात्रा पर जाना था तो कोरोना जांच कराई, जिसमें कोरोना संक्रमित निकला। उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बुजुर्ग दादी और मां को संक्रमित कर दिया।

केस-दो : कानपुर के पनकी का 46 वर्षीय व्यक्ति मार्केटिंग कंपनी में है। काम के सिलसिले में दूसरे शहर आना-जाना रहता है। कब संक्रमित हो गए, पता ही नहीं चला। हवाई यात्रा के सिलसिले में कोरोना की जांच कराई तो संक्रमण का पता चला। उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पत्नी संक्रमण की चपेट में आ गई।

लक्षण न उभरने की वजह

- अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता
- वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर
- वायरस के गले-सांस नली में रुकना।
- पहले संक्रमित होने से एंटीबाडी बनना।

बचाव के लिए यह जरूरी

- बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं
- भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें
- हाथों को बार-बार मुंह-नाक में न लगाएं
- लिफ्ट, वाहनों के हैंडिल छुएं तो हाथ सैनिटाइज जरूर करें
- घर आने पर हाथ-पैर व मुंह साबुन से अच्छी तरह धोएं

बिना लक्षण वाले संक्रमित सामने आने की तीन वजहें हैं। कुछ इम्यूनो कंप्रोमाइज (जिन्हें जल्दी-जल्दी सर्दी जुकाम होता है) मरीज होते हैं, जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए हों। ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और जो वैक्सीन लगवा चुके हों, यह तीनों दोबारा कोरोना वायरस होने पर कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उनमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन करें। मास्क जरूर लगाएं।

-डा. सौरभ अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग एवं नोडल अफसर, कोविड-19, जीएसवीएम मेडिकल कालेज

झारखंड में बाहर से आने वाले सभी की होगी कोरोना जांच

राज्य ब्यूरो, रांची : कई राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट मिलने के बाद अब झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करने के सख्त निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या तथा उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। इसके लिए प्रारूप भी तय कर दिया गया है, जिसके तहत सभी जिलों को रिपोर्ट देनी है।

अपर मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की संख्या, कोरोना जांच के लिए सैंपल संग्रह की संख्या, पाजिटिव व निगेटिव सैंपल तथा लंबित सैंपल की संख्या देने को कहा है।

कोरोना महामारी से उबारने के लिए बैंकों ने कसी कमर

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ

कोरोना महामारी से प्रभावित उत्तर प्रदेश को उबारने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है। ऋण वितरण को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान में सभी बैंकों को लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत सभी बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) में पौने तीन लाख करोड़ ऋण के रूप में देने होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने इस पर मुहर लगा दी है।

'राम' पर फोकस करेंगे बैंक : बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी बैंकों के सामने ऋण वितरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों की प्राथमिकता रहेगी। इसके तहत सभी बैंकों को राम (रिटेल, एग्रीकल्चर व एमएसएमई) क्षेत्र पर अधिक फोकस करना होगा। कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी बैंकों को बराबर ध्यान देना होगा।

कुछ बड़े बैंक और उनके लक्ष्य (करोड़ में)

भारतीय स्टेट बैंक	47,710
बैंक आफ बड़ौदा	21,129
बैंक आफ इंडिया	9,005
केनरा बैंक	21,977
सेंट्रल बैंक	9,798
इंडियन बैंक	186,98
पंजाब नेशनल बैंक	41,591
यूनियन बैंक	15,597
एक्सिस बैंक	4,715
एचडीएफसी बैंक	12,286

एसएलबीसी की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में सभी बैंकों को कुल 2.79 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है। यह बूस्टर के रूप में काम करेगा।

कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में एसआइटी ने बढ़ाई धारा, अब जांच में आएगी तेजी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआइटी ने फर्म व लैब संचालकों और बिचौलियों से पूछताछ के बाद धारा 467 (कुटरचना कर फर्जी दस्तावेज बनाना) बढ़ा दी है। इसकी जानकारी एसआइटी ने बकायदा नैनीताल हाइकोर्ट में दाखिल की है। एफआइआर के दौरान लगी धाराओं में अधिकतम सजा सात साल है, लेकिन धारा 467 में दस साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है। एसआइटी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पड़ताल में नामजद संस्थानों के अलावा एक अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सुबूत भी मिल चुके हैं। कई अन्य अधिकारियों की भूमिका को टटोला जा रहा है। बिचौलियों की कड़ी से कड़ी जुड़ने पर फर्म और लैब संचालकों पर कार्रवाई को लेकर काफी कुछ साफ हो जाएगा।

कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआइटी अभी तक सीएमओ डा. शंभू कुमार झा, मेलाधिकारी स्वास्थ्य डा. अर्जुन सेंगर और नोडल अधिकारी डा. एनके त्यागी के बयान दर्ज कर चुकी है। कोरोना टेस्टिंग का ठेका लेने वाली फर्म मैक्स कारपोरेट सर्विसेज दिल्ली, टेस्टिंग करने वाली नलवा लैबोरेट्रीज लैब हिसार हरियाणा और डा. लाल चंदानी लैब्स नई दिल्ली के संचालकों से बारी-बारी पूछताछ की जा चुकी है। लैब और फर्म के बीच में डील कराने वालों से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में अभी तक दस व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। नलवा लैब की डील कराने वाले अजय निवासी हिसार हरियाणा की अपील पर हाइकोर्ट में दाखिल जवाब में एसआइटी ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। धारा बढ़ने के बाद अब एसआइटी नामजदगी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसलिए आरोपितों की गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं, एसआइटी के सीओ राकेश रावत ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।



जांच में हुई है फर्जीवाड़ा। फाइल फोटो

काश! पड़ोसी जैसा पोस्टर हमारे घर भी लग जाए

श्रीशंकर शुक्ला, रायपुर

- वार्ड में 70 फीसद से ज्यादा टीकाकरण हुआ

कोरोना संक्रमण के दौरान पाजिटिव मरीज मिलने पर लोगों के घरों के बाहर बीमारी से संबंधित पोस्टर लगाए गए थे। जिनके घर के बाहर पोस्टर लग जाता था, उनसे सभी परहेज करने लगते थे। अब दौर टीकाकरण का चल रहा है। इसे लेकर काफी लोग हिचक रहे हैं। ऐसे में रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के पार्षद आकाश तिवारी ने पड़ोसियों को प्रेरणा स्रोत बना दिया है। घरों के बाहर पोस्टर लगवा रहे हैं जिस पर लिखा है-हमने वैक्सीन लगवा ली है, अब हमारा परिवार सुरक्षित है। इस पोस्टर का पड़ोसियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं और युवा परिवार के मुखिया पर टीकाकरण कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। बगल वाले के घर का पोस्टर देखकर पड़ोसी टीकाकरण करवा रहे हैं। इससे वार्ड में टीकाकरण की दर में तेजी आई है। पार्षद का दावा है कि सर्वाधिक 70 फीसद लोगों का इस वार्ड में टीकाकरण हो गया है।

पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के पार्षद वोटर लिस्ट लेकर अपने वार्ड के लोगों के बीच सर्वे कर रहे हैं। वह वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर घर के सभी सदस्य का टीकाकरण हुआ या नहीं इसकी जानकारी ले रहे हैं। यदि घर के प्रत्येक सदस्य को टीकाकरण हो गया है तो उसके घर के बाहर मैं सुरक्षित, मेरा परिवार और मेरा वार्ड सुरक्षित का स्टीकर लगा रहे हैं। वार्ड में कुल 11 हजार मतदाता और 25 हजार की आबादी है।

रीबॉक को करीब सवा अरब डॉलर में बेच रही एडिडास

फ्रैंकफर्ट : जर्मनी की अग्रणी स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी एडिडास ने रीबॉक ब्रांड को बेचने के लिए संभावित खरीदारों का चयन कर लिया है। कंपनी ने इसे वर्ष 2006 में 3.8 अरब डॉलर में खरीदा था। इसकी बिक्री से करीब 1.2 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि एडिडास ने अपनी अमेरिकी स्पर्धी वोल्वराइन के अलावा एडवेंट, सीवीसी, सर्बरूज तथा सायकामोर से अगस्त में अंतिम बोली दाखिल करने को कहा है। (रायटर)

टेलीकॉम सेक्टर पर बहुत अधिक दबाव है। कंपनी टैरिफ बढ़ाने से नहीं हिचकेगी, लेकिन यह अकेले नहीं होगा। — सुनील मित्तल, चेयरमैन, भारती एयरटेल



सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
52,318.60	15,680.00	₹46,310	₹68,654	₹74.55	$75.29
164.11	41.50	₹526	₹1,231	₹0.23	

कई विदेशी कंपनियां भारत में बनाएंगी लैपटॉप, पीसी और सर्वर

जाब्यू, नई दिल्ली : मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब देश में ही लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर जैसे उत्पाद काफी अधिक संख्या में बनने लगेंगे। डेल से लेकर आइसीटी विस्ट्रॉन जैसी कंपनियां भारत में ही लैपटॉप बनाएंगी। आइटी मंत्रालय ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली 14 कंपनियों को आइटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। अभी आइटी हार्डवेयर से जुड़े अधिकतर उत्पादों का आयात किया जाता है। इनमें अधिकतर हिस्सेदारी चीन की है। पीएलआइ स्कीम के तहत कंपनियों को चार फीसद प्रोत्साहन मिलेगा जो हर वर्ष उत्पादन में बढ़ोतरी के आधार पर होगा। इन कंपनियों को अगले चार वर्षों में 7,325 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। अगले चार वर्षों में ये कंपनियां 1.61 लाख करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का उत्पादन करेंगी। पीएलआइ स्कीम से 2,517 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।

अनलॉक का दिखने लगा असर, जून में आर्थिक गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार

ऑटो बिक्री में तेज उछाल, बिजली, पेट्रोल की खपत बढ़ी, निर्यात में दिखी तेजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर में नरमी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक का असर दिखने लगा है। जून में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत दे रही है। पिछले महीने में ऑटोमोबाइल्स एवं पेट्रोल-डीजल की बिक्री में उछाल देखा गया और बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी हुई। जून के प्रथम पखवाड़े के आंकड़ों के आधार पर पूरे महीने के निर्यात में भी बढ़ोतरी की संभावना है। आर्थिक तेजी को देखते हुए जून का जीएसटी संग्रह भी एक लाख करोड़ रुपये के पार रहने की पूरी उम्मीद है। जून का जीएसटी कलेक्शन आंकड़ा गुरुवार को जारी किया जाना था, लेकिन वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब यह पांच जुलाई को जारी होगा। ऑटो कंपनियां आने वाले महीनों में



ऑटो सेक्टर को बिक्री में ऐसी बढ़ोतरी की सख्त जरूरत थी ● फाइल फोटो

भी गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं।

ऑटोमोबाइल्स बिक्री : देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने जून में कुल 1,47,368 यूनिट की बिक्री जो मई से 217 फीसद अधिक है। इस वर्ष मई में कंपनी ने 46,555 यूनिट की बिक्री की थी। पिछले वर्ष जून में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 57,428 यूनिट की थी। कंपनी के मुताबिक लॉकडाउन में ढील मिलने से जून में छोटे और कॉम्पैक्ट सेग्मेंट की मांग बेहतर रही। टाटा मोटर्स के पैसेंजर वाहनों की बिक्री में इस वर्ष जून में मई के मुकाबले 59 फीसद और पिछले वर्ष जून के मुकाबले 111 फीसद की बढ़ोतरी रही। जून में कंपनी ने 24,110 यूनिट पैसेंजर वाहनों की बिक्री की। ह्युंडई ने जून में कुल 54,474 यूनिट की बिक्री की जो कि पिछले वर्ष जून के मुकाबले 103.1 फीसद अधिक है। ग्रामीण इलाकों की गतिविधियां तेज होन से महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून में ट्रैक्टर की घरेलू बिक्री 46,875 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष जून की तुलना में 31 फीसद अधिक है।

बिजली खपत : बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में बिजली की खपत पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले लगभग 10 फीसद बढ़ी। जून में 115.39 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 105.08 अरब यूनिट थी। इस वर्ष मई में 110.17 अरब यूनिट बिजली की खपत रही। हालांकि इस वर्ष जून की बिजली खपत वर्ष 2019 में समान महीने के मुकाबले कम है। जून, 2019 में 117.98 अरब यूनिट की खपत हुई थी। रिफाइनरी से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने पेट्रोल की बिक्री मई के मुकाबले 29.35 फीसद और डीजल की 18.5 फीसद अधिक रही।

निर्यात : वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक जून के प्रथम पखवाड़े में 14.06 अरब डॉलर का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 46.43 फीसद और जून, 2019 की समान अवधि के मुकाबले 34.3 फीसद अधिक है।

बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी : शक्तिकांत दास

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने बैंकों की समग्र और व्यक्तिगत पूंजी को कोरोना संकट जैसे मुश्किल दौर में भी पर्याप्त बताया है। आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि उनमें ग्रॉस एनपीए में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी का सामना आसानी से करने की पूरी क्षमता है। बैंक ने अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा कि अगले वर्ष मार्च तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 9.8 फीसद तक पहुंच सकता है।

हालांकि पिछली एफएसआर में आरबीआइ ने बैंकों का ग्रॉस एनपीए सालाना आधार पर 7.5 फीसद से बढ़कर सितंबर में 13.5 फीसद पर पहुंच जाने की आशंका जताई थी। लेकिन नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष मार्च में भी ग्रॉस एनपीए 7.5 फीसद ही रहा। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए अगले वर्ष मार्च अंत तक बढ़कर 12.52 फीसद और निजी बैंकों का 6.46 फीसद तक रह सकता है। दास ने बढ़ते साइबर हमलों को इकोनॉमी की राह में बड़ी बाधा बताई है।

दुनियाभर की कंपनियों को सेटेलाइट सेवा देगी एयरटेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अंतरिक्ष में सेटेलाइट स्थापित कर उसके जरिये मोबाइल सेवा मुहैया कराने के लिए भारती ग्रुप की सहायक शाखा वनवेब ने अंतरिक्ष में 36 छोटे सेटेलाइटों को सफलतापूर्वक स्थापित करने की घोषणा की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी सेटेलाइट मोबाइल सेवा जियो और वोडाफोन जैसी घरेलू टेलीकॉम कंपनियों समेत दुनियाभर की अन्य कंपनियों के लिए भी होगी। वनवेब वर्ष 2022 के अंत तक पूरी दुनिया में अपनी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने को 648 सेटेलाइट स्थापित करेगी। गुरुवार को प्रक्षेपित 36 सेटेलाइट के साथ कंपनी के कुल 254 सेटेलाइट स्थापित हो चुके हैं।

भारती इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बताया कि वनवेब की सेटेलाइट मोबाइल सेवा हिमालय के क्षेत्र में या समुद्री तट के आसपास या देश के दूरदराज के इलाकों में निर्बाध मोबाइल व इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकेगी। मोबाइल



भारत में सेटेलाइट आधारित मोबाइल सेवा अगले वर्ष से उपलब्ध होगी ● फाइल फोटो

कंपनियों के लिए इसकी स्थापना लागत काफी कम होती है। कंपनी की इस सेवा में देश की सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस बलों ने भी रुचि दिखाई है। भारत में कंपनी की सेवा अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी। इसके लिए कंपनी उत्तर भारत व दक्षिण भारत में दो ग्राउंड स्टेशन बना रही है। वनवेब की सेवा ब्रिटेन, कनाडा व पूर्वोत्तर यूरोप समेत दुनियाभर के कई हिस्सों में उपलब्ध हो गई है। भारती एयरटेल ने पिछले दिनों वनवेब में 50 करोड़ डॉलर के नए निवेश की घोषणा की थी। इस कंपनी में ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी है।

पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। फसल बीमा योजना को देश के 75 आकांक्षी जिलों में मजबूती से विस्तार देने के लिए इससे जुड़े संस्थानों को लगाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को फसल बीमा योजना सप्ताह की घोषणा करते हुए कहा, किसानों को खेती में होने वाले नुकसान की आशंका से बचाने के लिए यह योजना एक रक्षा कवच है।

किसानों के बीच फसल बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तोमर ने इस मौके राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे इसके लिए अपने 75 ब्लॉक और तहसीलों में अभियान चलाकर किसानों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। वर्ष 2016

17,000 करोड़ के प्रीमियम पर 95,000 करोड़ का मिला मुआवजा

में शुरू हुई इस योजना के तहत चार वर्षों में किसानों को कुल 17,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के एवज में 95,000 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया है। अब तक रिकॉर्ड 8.3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। विभिन्न आपदाओं में खेती को होने वाले नुकसान की भरपाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को बताना जरूरी है।

फसल बीमा योजना में किसानों का पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष तक इसकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा किसान पंजीकरण करा रहे हैं। तोमर ने कहा कि किसानों के लिए योजना को और लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 11 माह में पहली बार संकुचन

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 11 माह के दौरान पहली बार जून में संकुचन देखा गया है। मासिक सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर रोकने को लगाए गए लॉकडाउन का असर कारोबारी गतिविधियों पर दिखा है। आइएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) जून में घटकर 48.1 रह गया, जो मई में 50.8 था। इस सूचकांक पर 50 से ऊपर का अंक परिलक्षित होने का मतलब मैन्यूफैक्चरिंग में विस्तार और उससे कम रहने पर संकुचन माना जाता है।

फैक्ट्री ऑर्डर तथा निर्यात और खरीद की मात्रा में गिरावट आई है। पिछले माह कारोबारी आशावाद भी गिरा है और नई नौकरियों के सृजन में कमी आई है। सर्वे में बताया गया है कि संक्रमण के चलते विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से विदेशी बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग में भी कमी देखी गई है।

मिट्टी की जरूरत के हिसाब से बनेगा फर्टिलाइजर

नैनो तरल यूरिया से इफको की पहल, दूसरी कंपनियां भी कर रहीं तैयारी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह ● नई दिल्ली

खेत की मिट्टी के संतुलन के हिसाब से फर्टिलाइजर उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश के सभी किसानों के खेतों का सॉयल हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए यह ज्यादा आसान हो गया है। सॉयल यानी मिट्टी के असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए जरूरी फर्टिलाइजर और पोषक तत्वों का ही खेती में उपयोग किया जाएगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सहकारी क्षेत्र की कंपनी इफको ने तरल यूरिया के उत्पादन के माध्यम से बड़ी पहल कर दी है। अन्य फर्टिलाइजर कंपनियां भी तैयारी में जुट गई हैं।

क्लाइमेटिक जोन यानी भौगोलिक क्षेत्र विशेष और फसलों की जरूरतों के मद्देनजर फर्टिलाइजर की आवश्यकता पर जोर दिया



किसान मिट्टी की गुणवत्ता की जांच किए बगैर खाद का प्रयोग करते हैं जो फसलों और मिट्टी के लिए नुकसानदेह है ● फाइल फोटो

जा रहा है। कृषि विज्ञानियों के अनुसार घटते प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ती आबादी की जरूरतों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एक बड़ी व गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी ही एकमात्र साधन है, जिसके प्रयोग की सख्त जरूरत है। सिंचाई के सीमित साधनों, अच्छी प्रजाति के बीज और फर्टिलाइजर के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

खेती की लागत में फर्टिलाइजर की औसत हिस्सेदारी 20 फीसद से अधिक हो गई है, जिसे घटाना जरूरी है। इसके लिए हाल ही में इफको ने नैनो तरल यूरिया का उत्पादन कर लागत में कटौती की मिसाल पेश की है। इस बारे में कंपनी के रिसर्च एंड डवलपमेंट जीएम डॉक्टर रमेश रालिया का कहना है कि नैनो यूरिया से लागत में भी कटौती हुई है और खेती में इसके उपयोग से उत्पादकता में भारी वृद्धि का अनुमान है। बोरी भर यूरिया की जगह एक बोतल में नैनो यूरिया का उपयोग किया जा सकता है।

मिट्टी व जल विज्ञानी जगतवीर सिंह का कहना है कि नैनो तरल यूरिया के घोल का छिड़काव करने से इसका सीधा असर फसलों पर होता है। लेकिन बाकी फर्टिलाइजर का उपयोग मिट्टी में करना होता है। ऐसे में मिट्टी की जरूरतों के मद्देनजर इसमें अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण जरूरी है। मिट्टी में तीन मुख्य और लगभग एक दर्जन से अधिक सूक्ष्म तत्व होते हैं। फसलों की उत्पादकता और पौष्टिकता के लिए इन तत्वों के बीच जरूरी संतुलन होना जरूरी होता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत बिगड़ गई है।

सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर 'एक जिला एक खाद' तैयार करने का फैसला कर लिया गया है। इस तरह के फर्टिलाइजर में स्थान विशेष यानी वहां की मिट्टी के साथ सीजन की फसलों की जरूरत का खास ध्यान रखा जाएगा। हर फसल के लिए अलग तरह की खाद चाहिए। खाद में संबंधित क्षेत्र विशेष की मिट्टी के हिसाब से उसमें सूक्ष्म पोषक व अन्य आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाएगा।

भारत में 36,000 करोड़ का निवेश करेगी वेदांता

जाब्यू, नई दिल्ली : खनन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने अगले तीन वर्षों के दौरान भारत में पांच अरब डॉलर यानी 36,000 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश का एलान किया है। इसके जरिये कंपनी देश में कच्चे तेल व एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता में 50 फीसद वृद्धि करेगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश के 1,000 गांवों का समग्र विकास करने को अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये निवेश की भी घोषणा की है।

अग्रवाल ने बताया कि दो अरब डॉलर का निवेश तेल व गैस सेक्टर में किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पांच लाख बैरल रोजाना क्रूड उत्पादन करके वह ओएनजीसी की बराबरी कर सकता है। अभी भारत विदेशी बाजार से 70-75 डॉलर प्रति बैरल की लागत से कच्चा तेल खरीदता है। कंपनी 20-25 डॉलर प्रति बैरल दर पर कच्चा तेल आपूर्ति कर रही है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

अनिल देशमुख के सहयोगियों की हिरासत छह तक बढ़ाई

मुंबई : प्रिवेंशन आफ मनी लाड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने गुरुवार को मनी लाड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के दो सहयोगियों की हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी। मामला 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है। देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे व निजी सहायक रहे कुंदन शिंदे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। (प्रेट्र)

डीआरजी से मुठभेड़ में तीन लाख का इनामी नक्सली ढेर

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एलंगनार के जंगल में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन लाख का इनामी प्लाटून नंबर 26 का डिप्टी कमांडर जोगा मारा गया। उससे एक 303 रायफल, एक पिस्टल, एक वायरलेस सेट बरामद किया है। एसएसपी दीपक झा ने बताया मुठभेड़ के बाद सर्च आपरेशन जारी है। (नईदुनिया)

पूर्व डिप्टी सीएम के पीआरओ के खिलाफ चार्जशीट पेश

जम्मू : एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद के तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) एवं पूर्व फारेस्ट गार्ड केवल कृष्ण शर्मा, पत्नी, बेटे व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि केवल ने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व नजदीकी दोस्तों के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को है। (जासं)

राजस्थान में खान आवंटन में लागू होगी आरक्षण व्यवस्था

जयपुर : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब खान आवंटन के लिए भी आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी। खनन ब्लॉक के आवंटन सहित इससे जुड़ी सभी गतिविधियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। खनन पट्टों के आवंटन में इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। आवंटन की प्रक्रिया तय करने के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कमेटी गठित की है। (जासं)

अमानवीयता : पुत्र और भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को बेड़ियों से जकड़ा

संवाद सूत्र, उदयपुर

- राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला का मामला
- तीन महीने बाद पुलिस ने कराया मुक्त, पांच गिरफ्तार

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को बेड़ियों में जकड़कर रखने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे और चचेरे भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर महिला को मुक्त कर लिया है। महिला तीन माह तक बंधक रही है।

जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के जाम्बुखेड़ा गांव में भैरूलाल मीणा ने अपनी पत्नी जीवा बाई (40) को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था। इसकी जानकारी अरनोद थाने के बीट कांस्टेबल नेमीचंद को मिली। उन्होंने पहले इस बारे में पड़ताल की और बाद में वह थानाधिकारी रविंद्र सिंह और साथी कांस्टेबल शिवसिंह को लेकर भैरूलाल मीणा के घर पहुंचे। वहां कच्ची टापरी में एक महिला को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। पुलिस महिला को थाने ले गई और आरोपितों में शामिल भैरूलाल के चचेरे भाई अजमल मीणा को ताले की चाबी लाने को कहा। इसके एक घंटे बाद महिला को बेड़ियों से मुक्त किया गया।

पीड़िता को तीस किलो की जंजीरों से बांधकर रखा गया था। उसके पांव लोहे की जंजीरों की वजह से सूज गए थे। उसका मेडिकल कराया गया है तथा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। - रविंद्र सिंह, थानाधिकारी, अरनोद



जंजीर से बंधी जीवा बाई। जागरण

इसलिए बनाया बंधक

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पीहर में अकेली रह रही मां की देखभाल के लिए वह उनके पास जाती थी। इसको लेकर उसका पति उस पर संदेह करने लगा। उसके चरित्र पर शंका करते हुए वह उससे मारपीट करने लगा। इसमें उसका बेटा भी उसका साथ देता। तीन महीने पहले जब वह अपनी मां के घर से लौटी तो पति भैरूलाल ने बेटे राजू तथा चचेरे देवर अजमल मीणा और उसके दो अन्य भाई नारायण और परतू ने उसे लोहे की जंजीर से बांध दिया। पांव में जंजीर डालकर ताले लगा दिए, जिनकी चाबी अजमल अपने साथ ले गया।

केयरटेकर ने बच्चे को थप्पड़ मारकर खींचे बाल

जागरण संवाददाता, पटियाला

- निकर में बाथरूम करने पर बच्चे की बाजू तक मरोड़ दी
- सभी सदस्य करते हैं नौकरी, बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई थी केयरटेकर
- बच्चे व सामान की सुरक्षा के लिए परिवार ने लगाए हुए थे बेडरूम तक में कैमरे

नौकरीपेशा परिवार में पौने दो साल के बच्चे को संभालने वाला कोई न होने के कारण घर में एक केयरटेकर रखी गई। घर की देखभाल के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगे थे, लेकिन बच्चे व सामान की सुरक्षा के लिए दंपती ने बेडरूम में भी कैमरे लगा दिए। इस कैमरे की फुटेज देखते ही परिवार के होश उड़ गए। फुटेज में केयरटेकर महिला बच्चे को थप्पड़ मार रही थी। उसके बाल खींच रही थी। यही नहीं निकर में बाथरूम करने पर केयरटेकर ने बच्चे की बाजू तक मरोड़ दी। फुटेज देखते ही परिवार ने इसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सभी लोगों को अपने बच्चों का खास ध्यान रखने की अपील की। वहीं, उन्होंने फोन पर माडल टाउन पुलिस चौकी को शिकायत कर दी है। परिवार इस समय छुट्टियां मनाने शहर के बाहर गया है।

माडल टाउन निवासी बच्चे की मां संदीप सिद्धू ने बताया कि वह एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनके पति सरकारी मुलाजिम हैं। वहीं सास भी स्कूल प्रिंसिपल है, जबकि ससुर रेलवे में नौकरी करते हैं। ननद पढ़ाई कर रही है। ऐसे में पूरा परिवार ही घर से बाहर रहता है। पिछले साल लाकडाउन से पहले बच्चे को एक क्रेच में भेजा था। जहां पर उसकी देखभाल की जाती थी, लेकिन लाकडाउन के कारण क्रेच बंद हो गया। इस क्रेच में बढ़ूंगर में रहने वाली करीब 40 वर्षीय तलाकशुदा महिला काम करती थी। उसे एक माह पहले बेटे की देखभाल के लिए लगा दिया गया। घर पर सभी काम पर चले जाते थे तो ननद घर रहती थी, जिनकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। ऐसे में घर पर देखभाल के लिए कोई न रहने पर उन्होंने बेडरूम तक में कैमरा लगा दिए थे। फुटेज देखने पर उन्हें सच्चाई पता चली।

केयरटेकर ने किरायेदार से पूछा था कैमरे के बारे में : संदीप ने बताया कि जब उन्होंने बेडरूम में कैमरा लगाया तो केयरटेकर को शक हुआ था, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया गया। घर के एक हिस्से में किरायेदार के रूप में एक लड़की रहती है, जिससे इस कैमरे के बारे में केयरटेकर ने पूछा। लड़की ने इसे टालते हुए खिलौना बताया, जिस वजह से महिला बेफिक्र हो गई और उसकी हरकत कैमरे में कैद हुई।

मनसुख हिरेन की हत्या के लिए हुई 45 लाख रुपये की फंडिंग!

एंटीलिया कांड

- एनआइए ने अदालत में किया महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा
- कोर्ट ने दो आरोपितों की एनआइए हिरासत पांच जुलाई तक बढ़ाई

फैजान खान, मिड डे (मुंबई)

मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर (एंटीलिया) के पास से विस्फोटक लदी कार बरामद होने और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड में आए दिन नई बातें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुरुवार को अदालत को बताया कि उसे संदेह है कि मनसुख हिरेन की हत्या के लिए 45 लाख रुपये की फंडिंग की गई। एनआइए ने दावा किया कि उसे लेनदेन के एक अहम लिंक का पता चला है। आरोपित लाल रंग की टवेरा कार में मनसुख की हत्या के बाद नेपाल फरार हो गए थे। एजेंसी ने बताया कि उसे एक सीसीटीवी प्राप्त हुआ है, जिसमें हत्यारोपित चार मार्च को ठाणे के घोड़बंदर रोड पर मनसुख के साथ देखे गए।

विशेष अदालत में आरोपित सतीश मुटकरी व मनीष सोनी को पेश करते हुए एनआइए ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। एजेंसी ने कहा कि उसे 45 लाख रुपये के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। आशंका है कि एंटीलिया कांड के बाद उन रुपये का उपयोग मनसुख की हत्या के लिए किया गया, क्योंकि वह बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का आदेश नहीं मान रहा था। एनआइए ने कहा कि हत्याकांड में 45 लाख रुपये की फंडिंग तो बहुत छोटी रकम है, संदेह है कि इससे करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। इस मामले में कुछ और लोग संलिप्त हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल किए जाने की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने सतीश व मनीष की एनआइए हिरासत पांच जुलाई तक बढ़ा दी।

अदालत में बहस के दौरान लोक अभियोजक ने कहा कि मनसुख हत्याकांड के आरोपित के हवाले से 35 हजार रुपये बरामद हुए हैं। कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह राशि बड़ी नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को बताया वजह

प्रथम पृष्ठ से आगे

सरकारी तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को कारण बता रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो संकेत हैं उससे साफ है कि तेल उत्पादक देशों का संगठन (ओपेक) कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों को थामने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। गुरुवार देर शाम भी ओपेक की बैठक हुई। भारत अभी भी अपनी जरूरत की तकरीबन 50 फीसद रसोई गैस आयात करता है। कच्चे तेल से पेट्रोल व डीजल तैयार करने में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन रसोई गैस में नहीं हो सका है। पिछले कुछ वर्षों में गरीब परिवारों को उज्ज्वला स्कीम के तहत रसोई गैस कनेक्शन देने से रसोई गैस की मांग बढ़ी है। इसकी पूर्ति के लिए इंडियन आयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ने वर्ष 2020-21 में 11.6 फीसद ज्यादा एलपीजी आयात (6.28 करोड़ टन) की। इस पर ज्यादा खर्च भी एक कारण है कि कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं।

जमीन घोटाले में एसडीएम समेत 13 पर मनी लांड्रिंग का केस

ताराचंद गुप्ता, प्रयागराज

- ईडी ने शुरू की जांच, फंस सकते हैं बड़े अफसर, पूर्वोत्तर रेलवे की 41 बीघा जमीन बेचने का मामला

झूंसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे की 41 बीघा जमीन नियम विरुद्ध प्रापर्टी डीलर को देने और फिर उसकी प्लाटिंग कर बेचे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। फूलपुर के तत्कालीन एसडीएम राजकुमार द्विवेदी समेत 13 लोग आरोपित बनाए गए हैं। करीब 50 करोड़ रुपये कीमती जमीन के इस घोटाले में रेलवे और प्रशासन के बड़े अफसरों के भी फंसने की आशंका है। ईडी की जांच से खलबली है।

झूंसी थाने में 10 अगस्त, 2017 को फूलपुर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार देवेंद्र ने प्रापर्टी डीलर कुतुबउद्दीन व उसके भाई सल्लाउद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों अभियुक्त फूलपुर के चंदौहा गांव निवासी हैं। आरोप है कि झूंसी के कटका गांव और आसपास स्थित रेलवे व सड़क की भूमि गलत तरीके से नाम करा दी गई। मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई थी। इसमें एसडीएम, लेखपाल व प्रापर्टी डीलर समेत 13 लोगों का नाम प्रकाश में आया और सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई।

इन लोगों पर दर्ज हुआ है केस : तत्कालीन एसडीएम राजकुमार द्विवेदी, नायब तहसीलदार निखिल शुक्ला, लेखपाल धर्मपाल यादव, न्यायिक तहसीलदार आशुतोष सिंह, सेवानिवृत्त सीआरओ भाई लाल सरोज व सुरेश चंद्र, धर्मवीर यादव, मो. वसीद, मो. शाजिद खां, संजय जायसवाल, फजील जाफरी, प्रापर्टी डीलर सलाउद्दीन, कुतुबउद्दीन।

खाली कराई जा चुकी है जमीन : प्रशासन ने जमीन बिल्डर के कब्जे से मुक्त कराते हुए रजिस्ट्री निरस्त करा दी है। फिलहाल जमीन अभी रेलवे व संबंधित विभाग के पास है। राजस्व अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ था।

रिहाई मांग रहे कैदियों की याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु यानी नाबालिग होने के आधार पर रिहाई मांग रहे आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 कैदियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पा चुके याचिकाकर्ता अब तक 14 से 22 साल तक की सजा भुगत चुके हैं। याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से उन्हें नाबालिग घोषित किए जाने के आदेश को आधार बनाया गया है। अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने गुरुवार को रिहाई मांग रहे कैदियों की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक जवाब मांगा। कोर्ट ने रिट याचिका के अलावा तत्काल अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग पर भी प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मल्होत्रा ने कहा कि यह मामला एक प्रकार से गैर कानूनी हिरासत रहा है।

दैनिक जागरण
जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो वही सबसे शक्तिशाली है

कांग्रेस की कार्यशैली

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि कांग्रेस में अब संवाद और बहस की परंपरा खत्म हो चुकी है, उससे असहमत होना कठिन है। आत्मचिंतन के लिए शिविरों और बैठकों को आवश्यक बताते हुए शिंदे ने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस अपनी संस्कृति खोती जा रही है। उनकी मानें तो आज यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस कहां जा रही है। यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेसी नेता ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हों। इसके पहले गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल समेत 23 नेता एक चिट्ठी के जरिये वैसी बातें कह चुके हैं, जैसी शिंदे ने कहीं। चूंकि इन 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद भी कांग्रेस के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इसके आसार नहीं कि शिंदे की बातें असर करेंगी। कांग्रेस अपने तौर-तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं, इसका प्रमाण पंजाब कांग्रेस के संकट को सुलझाने के उसके रवैये से भी मिलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके विपरीत उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते ही प्रियंका गांधी और फिर उनके जरिये राहुल गांधी से भी मुलाकत कर लेते हैं।

पता नहीं अमरिंदर और नवजोत के बीच की तनातनी कैसे खत्म होगी, लेकिन यह देखना दयनीय है कि उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गठित की गई समिति किसी काम नहीं आई। काम आई प्रियंका गांधी की पहल। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव के नाते नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने का समय निकाला, लेकिन राहुल गांधी का बीच में पड़ना तो यही बताता है कि वह बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी को अपने ढंग से चला रहे हैं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से ही पार्टी के सारे बड़े फैसले वही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने न तो कोई तंत्र बना रखा है और न ही संपर्क-संवाद की कोई व्यवस्था। वह जिससे चाहते हैं, उससे मिलते हैं और जिससे नहीं चाहते, वह इधर-उधर परिक्रमा करते रहता है। इससे ही आजिज आकर हिमंता बिस्वा सरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे कई नेता या तो दूसरे दलों में चले गए या फिर शिंदे की तरह निष्क्रिय हो गए। एक अर्से से कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हो गया है। ये तीनों जो चाहते हैं, वही होता है। जिनकी इन तक पहुंच नहीं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस तरह कंपनी तो चलाई जा सकती है, पार्टी नहीं।

पौधों को बचाएं

वाराणसी में पौधों के नाम से सड़कों और पार्कों को एक नई पहचान देने की अच्छी पहल हुई है। इसके तहत जिस सड़क या पार्क को चुना जाएगा, उसमें खास किस्म के पौधे ही रोपे जाएंगे। इससे इन्हें तो विशिष्ट पहचान मिलेगी ही, नई पीढ़ी को भी पौधों की नई किस्मों की जानकारी हो सकेगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) इसकी शुरुआत आवासीय कालोनियों से करने जा रहा है। माडल के रूप में बड़ालालपुर आवासीय योजना की सड़कों को गुलमोहर रोड, कचनार रोड और अमलतास रोड जैसे नाम दिए जाएंगे। 20 जगह हर्बल और नवग्रह वाटिका भी बनेगी। यहां नवग्रहों से जुड़े पौधे ग्रहों की उपयुक्त दिशा में रोपे जाएंगे। वीडीए की यह पहल प्रदेश में एक जुलाई से 30 करोड़ पौधे रोपने के वृहद अभियान का ही हिस्सा है। वैसे प्रदेश के हर शहर में स्थानीय विभूतियों के नाम पर सड़कों या पार्कों का नामकरण किया गया है, लेकिन पौधों के नाम पर सड़क थोड़ी नई बात है। बिजनौर पुलिस ने भी पिछले दिनों महापुरुषों के नाम पर थानों, पुलिस चौकियों और चेक पोस्टों के नामकरण की ऐसी ही पहल की थी। इस प्रयास से लोग न सिर्फ अपने महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उनकी गौरवगाथा से प्रेरणा भी पा रहे हैं। कुछ वर्षों से सामाजिक संस्थाएं भी दिवंगत स्वजन की याद में पौधे रोपने और उसकी देखभाल का जिम्मा देती आई हैं। इससे पौधे तो सुरक्षित रहते ही हैं, अपने प्रिय स्वजन की यादें भी ताजा बनी रहती हैं। हालांकि पौधारोपण अभियान में अथवा जिलों में नए अफसरों के आगमन पर भी उनके नाम से पौधे रोपे जाते हैं। यह विडंबना ही है कि इनकी भी ठीक से देखरेख नहीं हो पाती। अच्छा हो कि जो पौधा रोपा जाए, उसकी देखभाल भी सुनिश्चित हो। वनाच्छादन तभी बढ़ेगा, जबकि बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश की जाएगी। याद रखें, अभियान में 30 करोड़ और एक दिन में 25 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य भले ही हम हासिल कर लें, लेकिन इसकी सफलता तो जीवित बचे पौधों से ही आंकी जाएगी।

> अभियान में 30 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य भले ही हासिल कर लिया जाए, लेकिन इसकी सफलता तो जीवित बचे पौधों से ही आंकी जाएगी

बंगाल को बचाने के उपाय



कैप्टन आर विक्रम सिंह

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की भयावह घटनाओं को सुनकर 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, लोमहर्षक हत्याओं, दुष्कर्मों की याद ताजा हो रही है

विधानसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की स्थिति चिंताजनक रूप से अस्थिर है। राज्य के सियासी हालात कैसे हैं, इसका पता इससे चलता है कि आतंकित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सिर मुड़ाकर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वे खुलेआम इसे लेकर माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ऐसा लगता है कि आतंक का राज प्रतिपक्ष को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। स्थिति यह है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ भी हाथापाई की कोशिश की जाती है, जबकि यह टीम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य का दौरा करने गई थी। तृणमूल कांग्रेस किसी की परवाह नहीं कर रही है। वह दलबदल कानून से प्रभावित मुकुल राय को परंपराओं को तोड़ते हुए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने पर आमादा है। यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति, सत्ता-चरित्र, नेताओं के व्यक्तित्व को उजागर करने वाला है। सिविल सोसायटी की तथ्य खोजी समिति का निष्कर्ष है कि चुनाव बाद सुनियोजित हिंसा के चलते बंगाल के लोगों को पलायन कर असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी है। इस समिति ने लोगों के घर जलाने, उनकी हत्याएं करने और महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों का भी उल्लेख किया है।

बंगाल की चुनाव बाद हिंसा की भयावह घटनाओं को सुनकर 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, लोमहर्षक हत्याओं, दुष्कर्मों की याद ताजा हो रही है। आपको याद होगा कि इसी बंगाल में 1946 में जिन्ना के आह्वान से हुए भीषण नरसंहार ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान बनने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आखिर बंगाल की राजनीतिक-सांप्रदायिक हिंसा का संदेश क्या है? जमीनी सतह पर खुली हिंसा, सांप्रदायिक पक्षधरता का मुकाबला कैसे हो? लंका युद्ध में मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से जब युद्धभूमि में भगवान राम और लक्ष्मण जी मरणासन्न से हो गए तो विभीषण विक्षिप्त होकर जामवंत के सामने विलाप करते हैं कि-अरे, अब लंका का राज तो गया, जिसकी आशा में यहां आया था। अब लंकेश मेरा न जाने क्या हाल करेगा? इस संकट के समय जामवंत जी के सम्मुख विभीषण का जो मूल चरित्र था, वह प्रकट हो गया। पता चल गया कि वह कितना बड़ा रामभक्त था। वही स्थिति आज बंगाल के टीएमसी से विद्रोह कर भाजपा में आए और पलायन को आतुर हो रहे भाजपा नेताओं की हो रही है। चलिए, अच्छा भी है कि वक्त रहते उनका स्वार्थी चरित्र प्रकट हो गया। अब समझ में आता है कि बख्तियार खिलजी ने कैसे इतनी आसानी से बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हरा दिया था।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम से गुहार लगाते हिंसा पीड़ित। एएनआइ

भयादोहन के जरिये शासन करने की जो रणनीति कम्युनिस्टों की थी उसी को टीएमसी ने भी अपना लिया है। यही नीति उसे प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में ले आई है। निःसंदेह केंद्र के सामने विषम स्थिति है। देश की जनता बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, सांप्रदायिक पक्षधरता, पलायन के समाचार सुन-सुनकर बौखला रही है। वह केंद्र सरकार को इसके लिए कोस रही है कि वह कुछ नहीं कर रही है। चूंकि शांति-व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र के सम्मुख संवैधनिक प्रशासनिक मजबूरियां हैं। फिर भी राह तो निकालनी है। मौजूदा हालात में बंगाल को दो राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विभक्त करना जरूरी लगता है। उत्तरी बंगाल के पांच जनपदों दार्जिलिंग, कलिमपोंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को अलग करते हुए नया राज्य बनाया जाए। इन जनपदों की कुल आबादी लगभग 1.5 करोड़ तक होगी। गोरखालैंड का आंदोलन भी इन्हीं क्षेत्रों में चलता रहा है। उससे प्रभावित हुए बिना राष्ट्रहित में इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। यह निर्णय बंगाल ही नहीं संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाजपा के दो सांसदों ने भी इस आशय की मांग की है। इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल बंगाल को बचाने का है। बंगाल के उत्तरी एवं दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद का जनसांख्यिकीय अनुपात एनआरसी के अभाव में वर्षों से लगातार बिगड़ता गया है। इन जिलों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाकर केंद्र के नियंत्रण में लिया जाना आवश्यक है। शेष मूलतः दक्षिणी बंगाल के 11 जनपद पूर्ववत बने रहें तो कोई समस्या नहीं है। यह परिवर्तन बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश से लगातार सांप्रदायिक होते जा रहे इस क्षेत्र के चरित्र को एक बड़ी सीमा तक नियंत्रण में ले आएगा। इसके साथ ही यदि एनआरसी-सीएए की भी युद्धस्तर पर अनुपालन घोषणा हो जाए तो शीघ्र ही अराजकता की स्थिति समाप्तप्राय होने लगेगी।

एक सुझाव और है। केंद्र सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय प्रशासन के लिए भारत की उस प्राचीन इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पुनर्जीवित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी सेवा के मेजर कीथिंग ने तवांग पर भारतीय प्रशासन कायम किया था। तब यह सेवा मात्र नेफा (अरुणाचल प्रदेश) और असम तक सीमित थी। अब इसका विस्तार समस्त सीमांत क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता है। बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के सीमा क्षेत्रों का प्रशासन केंद्र के अधीन होने से सीमा से जुड़ी तमाम अव्यवस्थाएं, शस्त्र एवं ड्रग तस्करी, आतंकियों का प्रवेश, मानव तस्करी, पशु तस्करी, जनसांख्यिकी बदलने के प्रयास आदि बड़ी समस्याएं नियंत्रण में आनी प्रारंभ हो जाएगी। यह ध्यान रहे कि राज्यों की मशीनरी तो इस अवैध तंत्र और उसकी नियंत्रक राजनीति से भयभीत रहती है या फिर उसमें हिस्सेदार बन जाती है। इस प्रशासनिक परिवर्तन का बंगाल, असम और पंजाब जैसे राज्यों की बिगड़ रही आंतरिक शांति-व्यवस्था को सुधारने पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रशासनिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ममता बनर्जी इस परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलनकारी रुख अख्तियार करेंगी ही। सांप्रदायिक तत्वों का खेल बिगड़ने से वे दंगे-फसाद का माहौल बनाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम सकारात्मक ही होगा। पूर्वोत्तर और बंगाल को विवादरहित रखना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को भीषण भूराजनीतिक मजबूरियों में फंसा दिया था। आज समय बदला है। असंभव से निर्णय लिए जा रहे हैं। अफसोस होगा यदि समय पर निर्णय नहीं लिया जा सके। देश निर्णय की प्रतीक्षा में है।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

ड्रोन हमले ने बजाई खतरे की नई घंटी



दुष्यंत सिंह

हमारे पास इसकी भी क्षमता होनी चाहिए कि यदि हम ड्रोन मंडराता देख लें तो फिर उसे मार गिराएं

गत 26-27 जून की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो धमाके सुनाई दिए। इन धमाकों से आसपास रहने वाले जम्मू शहर के लोग सहमे तो होंगे, पर यहां के लोगों ने बहुत आतंकी हमले झेले हैं और इसलिए वे शायद ही अचंभित हुए हों। जम्मू का एयरपोर्ट वायु और थल सेना की छावनियों के बीच स्थित है। इस कारण भारतीय थल सेना के सुरक्षाकर्मी भी इसके चारों तरफ तैनात रहते हैं। इसी कारण जम्मू हवाईअड्डे में जमीनी घुसपैठ कर हमला करना बहुत मुश्किल है। शायद यही कारण था कि एयरफोर्स बेस को हवाई मार्ग से ड्रोन द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह हमला एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ, जिसमें एक इमारत की छत को हानि पहुंची और वायु सेना के एक वारंट अफसर एवं एक वायु सैनिक को मामूली चोट लगी। इस हमले का निशाना शायद टेक्निकल एरिया में खड़े सेना के हेलीकाप्टर थे। ड्रोन से हमला बहुत ही सस्ता और सुरक्षित तरीका है। इसमें हमला करने वालों के लिए जोखिम न के बराबर होता है। अगर यह हमला सफल हो जाता तो हमारा अत्यधिक नुकसान होता, साथ ही देश की साख को भी धक्का लगता। यह हमला शायद छोटे ड्रोन से किया गया। इस तरह के ड्रोन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं और उनका रडार द्वारा पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस हमले का अंजाम और भी भयानक हो सकता था, अगर ड्रोन उच्च क्षमता के विस्फोटकों से लैस होते। मेरा अनुमान है कि अगली बार विस्फोटक की मात्रा और उसका प्रकार अलग होगा। अभी तो इस हमले में केवल दो ही ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अगली बार शायद ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं।

यह देखा गया है कि कई बार ड्रोन अपने विस्फोटक के साथ ही लक्ष्य से टकरा जाते हैं। इसे हम कामीकाजे ड्रोन हमला भी कहते हैं। दूसरे महायुद्ध में जापानी पायलट्स अपने हवाईजहाज को पानी के बड़े-बड़े जहाजों में जानबूझकर क्रैश करा देते थे, ताकि वे हर हाल में नष्ट हो जाएं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद जिस तरह शहर में लगातार ड्रोन मंडराते दिख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगली बार पाकिस्तानी सीमा से लगे हवाईअड्डे जैसे श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट और अमृतसर निशाने पर हो सकते हैं। ड्रोन से आतंकी अपने साजो-सामान को बहुत आसानी से भेज सकते हैं। यह हमारे लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अतीत में ड्रोन के जरिये हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की गई है। हमें तभी सतर्क हो जाना चाहिए था।



जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी। फाइल

दुनिया में काफी दिनों से ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये हमले स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, दोनों ही कर रहे हैं, पर भारत में किसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला पहली बार हुआ है। अमेरिका, रूस, इजरायल, चीन और तुर्की ड्रोन के इस्तेमाल और उसकी तकनीक में बहुत माहिर हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान और सीरिया में न जाने कितने आतंकियों को ड्रोन हमले के जरिये मारा है। इसी तरह तुर्की ने सीरिया के साथ-साथ अजरबैजान एवं आर्मेनिया की लड़ाई में इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए सर्विलांस, इंटेलीजेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारा इंटेलीजेंस तंत्र अभी उतना सक्षम नहीं, जितना होना चाहिए। हमें लो लेवल रडार और आधुनिक नाइट विजन यंत्रों की भी सख्त जरुरत है, खास तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील ठिकानों पर। हमारे ऐसे ठिकानों पर अक्सर डिफेंस सर्विस कोर के व्यक्तियों की तैनाती होती है। ये जवान बहुत ही कर्तव्यपरायण होते हैं, पर उनकी उम्र ज्यादा होती है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर वायु सेना को एक बेहतर फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि इस तरह के हमलों की काट की जा सके।

इसके अलावा हमारे पास इसकी भी क्षमता होनी चाहिए कि यदि हम ड्रोन को देख लें तो फिर उन्हें मार गिराएं। ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए हम जैमर्स सरीखे इलेक्ट्रानिक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में एक आधुनिक जैमिंग सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा है, जो छोटे ड्रोन हमले को नाकाम कर सकता है। इसी तरह ब्रिटेन के ब्राइटस्टार सर्विलांस सिस्टम ने पिछले साल सितंबर में एक नया रडार ए 800 3डी नाम से लांच किया है। यह छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसे बॉर्डर मैनेजमेंट और मिलिट्री सिस्टम में आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं। अमेरिका भी एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे छोटे ड्रोन को नाकाम किया जा सकता है। इसी तरह जब ड्रोन एकदम नजदीक आ जाए, तब एक अन्य ड्रोन द्वारा ही उसे नष्ट करने के लिए इजरायल और अमेरिका ने मिलकर एक तकनीक विकसित की है। स्काईलार्ड नामक इस तकनीक में ड्रोन में एक जाल होता है, जो दुश्मन के ड्रोन को उसमें फंसाकर नाकाम कर देता है।

चूंकि इस तरह की उन्नत तकनीक को खरीदने या विकसित करने में समय लगेगा इसलिए हमें मशीनगन के जरिये ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता विकसित करनी होगी। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, पर अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो यह तरीका असरदार हो सकता है। जब तक ड्रोन नष्ट करने की तकनीक हासिल नहीं की जाती तब तक हमें पारंपरिक हवाई सुरक्षा के तरीकों को ही अमल में लाना होगा। ड्रोन हमलों की तुलना हम एक हवाई गुरिल्ला युद्ध से कर सकते हैं। इनकी काट भी एक गुरिल्ला युद्ध की तरह ही करनी होगी। यदि सीमा से लेकर संवेदनशील ठिकानों तक की हवाई और जमीनी सर्विलांस के साथ खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा सके तो हमें ड्रोन हमलों से निपटने में काफी सफलता मिल सकती है।

(लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट जनरल हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संस्कृति और जीवन

जीवन को परिष्कृत कर उसे वास्तविक रूप-सौंदर्य प्रदान करने वाली मान्यताओं, स्थापनाओं और मूल्यों का समूह है संस्कृति। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव कल्याण में सहायक समस्त ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक महनीय कार्य संस्कृति कहलाते हैं। ये कार्य मानव सभ्यता को मानवता के शिखर पर पहुंचाते हैं। इन कार्यों से मानव सभ्यता की उम्र निर्धारित होती है। संस्कृति किसी देश का आत्मा है, जिसके बिना वह निर्जीव है। संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है जहां उसके प्राकृत राग-द्वेषों का परिमार्जन होता है।

किसी देश की संस्कृति वहां के पूर्वजों की त्याग-तपस्या और उनकी उर्वर बौद्धिक शक्ति का परिणाम होती है। उनके दीर्घ अनुभव उसे संजीवनी प्रदान करते हैं। हमारे देश की संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है। इसके निर्माण में यहां के तप साधक ऋषि-मुनियों का योगदान रहा है। यह तपोभूमि भारत अध्यात्म की भूमि है। इसीलिए यहां की संस्कृति भी आध्यात्मिक है, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और ममता की प्रधानता है। यदि इसके मूल में 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के भाव हैं तो सर्व धर्म समभाव इसका प्राण। सत्य-अहिंसा इसके हथियार हैं तो त्याग और सहिष्णुता इसके पाथेय।

इस दुनिया में लोग तीन प्रकार से जीवन जीते हैं। कुछ अपनी प्रकृति में, कुछ विकृति में और कुछ अपनी संस्कृति में। जैसे-खुद का खाना प्रकृति है तो दूसरों का छीनकर खाना विकृति, परंतु दूसरों को खिलाकर खाना हमारे देश की संस्कृति है। स्वार्थ के लिए जीना प्रकृति है तो दूसरों को कष्ट देकर जीना विकृति, परंतु परोपकार के लिए जीना हमारे देश की संस्कृति है। देश के संसाधनों का भोग करना मानव की प्रकृति है तो देश के संसाधनों का भोग करके भी देश के विरुद्ध आचरण करना विकृति, परंतु देश के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखना हमारे देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को हमें अक्षुण्ण रखना होगा।

डॉ. सत्य प्रकाश मिश्र

उड़न तश्तरियों की गुत्थी

प्रदीप

> यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि क्या सितारों के आगे जहां और भी हैं

हमारी पृथ्वी पर जीवन के विविध रूप विद्यमान हैं। इंसानी कल्पना से दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की मौजूदगी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोग भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में पृथ्वी से कई गुना विकसित बुद्धिमान सभ्यताओं की मौजूदगी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी ग्रह पर जीवन अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, जहां अभी विकास की प्रक्रिया चल रही होगी। वर्तमान विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी से इतर किसी अन्य ग्रह या खगोलीय पिंड पर जीवन न पनपने का कोई कारण नहीं है।

शायद यही कारण है कि आए दिन पूरे विश्व में यूएफओ (एक तरह का स्पेसशिप) या उड़न तश्तरी के दिखाई देने के दावों के समाचार सामने आते रहते हैं। हॉलीवुड फिल्मों में भी एलियन एक प्रमुख कथानक के रूप में मिल ही जाते हैं। इन फिल्मों में उन्हें ऐसे खलनायकों के रूप में पेश किया जाता है, जिनका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करना या इंसानों को अपने गुलाम के रूप में इस्तेमाल करना है। फिल्मों से अलग कई लोग भी यह मानते हैं कि एलियंस उड़न तश्तरियों से पृथ्वी पर आते रहते हैं। वे आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु को यूएफओ कह देते हैं, लेकिन आज तक इस बात के पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं कि यूएफओ के जरिये सच में एलियंस धरती पर आते हैं या नहीं। सामान्यतः कई विज्ञानी भी यूएफओ के दिखाई देने के दावों पर यकीन नहीं करते। वे तारों के बीच की विशाल दूरी के मद्देनजर इसकी संभावना को खारिज कर देते हैं। वैसे भी ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ खास प्राकृतिक घटनाओं मसलन-उल्का पिंडों के टूटने, तड़ित युक्त तूफान, असाधारण वातावरण या बादल बनने वगैरह के कारण यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं होती हैं। कुछ मानव निर्मित कृत्रिम वस्तुएं भी यूएफओ का भ्रम पैदा करती हैं। जैसे-रडार प्रतिध्वनि, व्यावसायिक और सैन्य विमान, मौसम और अन्य शोधों के लिए प्रयुक्त होने वाले गुब्बारे आदि। इसके बावजूद उड़न तश्तरियों के देखे जाने के दावों में कोई भी कमी नहीं आई है। सारी दुनिया में उड़न तश्तरियों और एलियंस की मौजूदगी पर बहस को आगे बढ़ाने और विज्ञानियों द्वारा इस विषय पर शोध कार्य को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 2001 से प्रति वर्ष दो जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है।

हालांकि भले ही यूएफओ के अस्तित्व को दुनिया में आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इनके दिखाई देने की घटनाएं 1947 से ही मीडिया में लगातार आती रही हैं। बहरहाल यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि क्या सितारों के आगे जहां और भी हैं, जहां से एलियंस यूएफओ रूपी स्पेसशिप से पृथ्वी पर आते हैं? अब काफी लंबा समय बीत गया है। यूएफओ को लेकर एक मत बनाया जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चीन को सबक सिखाने का समय

'चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनता भारत' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में हर्ष वी पंत ने उचित ही लिखा है कि जब वैश्विक शक्तियां चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट हो रही हैं, तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है। इसमें दो मत नहीं कि चीन को कोई देश चुनौती दे सकता है तो वह भारत ही है। चूंकि पश्चिमी देशों के अपने स्वार्थ हैं। चीन के साथ उनके कारोबारी हित गहरे जुड़े हुए हैं। उनकी साझा सीमाएं भी नहीं हैं, लिहाजा वे चाहकर भी चीन के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाएंगे। इसके विपरीत भारत चीन के साथ लंबी सीमा साझा करता है। यह गाहे-बगाहे उसकी विस्तारवादी नीति की आक्रामकता से दो चार होता रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक इन दिनों वह हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार अपनी मजबूत इच्छाशक्ति, रणनीति और कूटनीति के दम पर चीन को कई मोर्चों पर कड़ा जवाब देने में सफल रही है। आंतरिक स्तर पर कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए चीन का डटकर सामना करने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। विश्व जगत को भी इस बदलते भारत का अहसास हो रहा है। जो देश चीन की बदमाशियों से परेशान होकर लंबे समय से उसको सबक सिखाना चाह रहे थे, अब भारत के तेवर को देखते हुए वे भी आगे आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि चीन को जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

मिथिलेश झा, पटना

मेलबाक्स

जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती

आज पूरे विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। धरती लगातार गर्म हो रही है। समुद्र का ताप बढ़ता जा रहा है। मानसून के चक्र में बदलाव हो रहा है। दिल्ली में मई के महीने में अत्यधिक बारिश हुई तो जून में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अब मानसून आने में देरी हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि हम जलवायु परिवर्तन के गहरे संकट से गुजर रहे हैं। हर वर्ष गर्मी का रिकार्ड टूट रहा है। कनाडा में भीषण गर्मी के चलते 130 लोगों की मौत हो चुकी है। यह एक चेतावनी है और चिंताजनक स्थिति भी। कहीं बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं तो कहीं बारिश न होने की वजह से लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। इसके पीछे हमारा पर्यावरण पर ध्यान न देना एक महत्वपूर्ण कारण है। हम पर्यावरण का इतना अधिक दोहन कर चुके हैं कि अब उसको वापस उस स्थिति में लाना मुश्किल भरा काम है, लेकिन इसे रोक जरूर सकते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए। हमें अपनी मुहिम तेज करनी होगी, वरना आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

आशीष, नई दिल्ली

बेहतर कूटनीति का परिणाम

संपादकीय पेज पर प्रकाशित आलेख 'चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनता भारत' में हर्ष वी पंत ने भारत को पहले की अपेक्षा चीन के विरुद्ध ज्यादा आक्रामक होना कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहतर माना है। मौजूदा सरकार कोविड 19 जैसी महामारी का सामना करते हुए चीनी रणनीति का भी सामना कर रही है। देखा जाए तो इस बीच भारत पूरी दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरा है। आज पश्चिमी देशों में कई महाशक्तियां होते हुए भी अमेरिका, रूस, फ्रांस सरीखे राष्ट्र भारत के साथ आर्थिक, तकनीकी और सामरिक समझौता करते रहते हैं। चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को रोकने में विभिन्न देश भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। बहरहाल आज चीन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी अमेरिका हो या जापान या फिर अन्य पश्चिमी राष्ट्र सभी का झुकाव भारत की ओर है। अब अमेरिका सरीखे राष्ट्र यह जान और मान गए हैं कि हर मोर्चे पर चीन की हेकड़ी कम करने के लिए भारत जैसे मजबूत और दृढ़संकल्पी राष्ट्र का साथ होना जरूरी है। यह सब मौजूदा सरकार की बेहतर कूटनीति और सफल विदेश नीति का ही परिणाम है।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

15.7 लाख रुपये का प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर लाभ देता है एक वृक्ष अपने जीवनकाल के 50 वर्षों के दौरान। इसके अलावा, वृक्षों का मानव के जीवन में अमूल्य योगदान है।



अभिषेक
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

आजकल

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण से महामारी की रोकथाम

कोरोना महामारी के घातक असर को कैसे कम किया जाए, इसके लिए निरंतर शोध जारी है। इसी क्रम में भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय, पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आइआइटी भुवनेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 16 शहरों में प्रदूषण और कोरोना संक्रमण की घातकता के संदर्भ में किए गए अध्ययन में पर्यावरण और कोविड के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है, जिसमें अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का जोखिम अधिक होना बताया गया है


वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कोरोना महामारी का असर अधिक घातक साबित हो रहा है। फाइल

कोविड महामारी की पहली लहर का लगभग सफलतापूर्वक सामना कर लेने से सरकार और जनमानस दोनों में आई आत्मसंतुष्टि ने इसकी दूसरी दूसरी लहर को अधिक भयावह बना दिया। शायद यही कारण है कि समय रहते तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी हरेक स्तर पर जारी है। इस तैयारी में कोविड के प्रसार और घातकता पर नियंत्रण के लिए कमर कसी जा रही है।

इस बीच वायु गुणवत्ता आयोग ने भी सतर्कता दिखाते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश स्वयं में ही एक अच्छी खबर है, किंतु आयोग के इन प्रयासों से कोविड के रोकथाम में अवश्य मदद मिल सकती है। ऐसे में हमें यह भी समझना चाहिए कि इस महामारी को रोकने में वायु प्रदूषण नियंत्रण का क्या योगदान हो सकता है।

इस संबंध में हमें यह समझना होगा कि किसी भी शोध की शुरुआत एक अनुमान से होती है जो या तो अनुभव या पुराने शोधों पर आधारित होता है। अनुमान को वैज्ञानिक परिकल्पना में बदलने की पहली शर्त यह है कि उसमें कारण, कारक और प्रभाव तीनों की स्पष्टता होनी चाहिए। इस स्पष्टता के निश्चित हो जाने के बाद उस परिकल्पना को कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। इन सभी परीक्षाओं में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कारण और प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। इसके कई चरण होते हैं जिससे यह निश्चित किया जा सके कि प्रभाव उसी कारक की वजह से है। बीमारियां शरीर के अंगों को क्यों प्रभावित करती हैं, इसको समझने के लिए संभावित कारकों का पृथक्करण कर अलग अलग मापन और परीक्षण संभव नहीं होता है, जिस कारण ऐसे शोधों की जटिलता और बढ़ जाती है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, लिहाजा इसके संदर्भ में बहुत सारे आंकड़े अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी इसके आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं। इस महामारी के मरीजों के चिकित्सीय इतिहास से जुड़े आंकड़े और कोविड वायरस शरीर में कैसे घुसता है और सक्रिय होता है, इसको समझने के लिए कई प्रकार के शोध अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

मगर इन सीमाओं का अर्थ यह नहीं है कि हम कोविड और वायु प्रदूषण को लेकर कोई वैज्ञानिक अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। संक्रमण और घातकता से जुड़े व्यक्तिवार आंकड़े भले ही नहीं हों, लेकिन यह संभव है कि कोविड के संक्रमण और घातकता के जो क्षेत्रीय स्तर पर शहरों के समग्र आंकड़े हमारे सामने हैं, उनको उस क्षेत्र के प्रदूषण के आंकड़ों से जोड़ कर देखा जाए। इस वैश्विक महामारी के आरंभ में ही इन्हीं समग्र आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण विज्ञानियों ने वायु प्रदूषण के कोविड के साथ संबंधों को समझते हुए अपने प्रारंभिक शोधों के आधार पर यह बताया कि वायुमंडल में कणिका तत्वों की मात्रा कोविड की घातकता को बढ़ा सकती है। इसी सिलसिले में प्रदूषण और कोविड के संबंधों को समझने के लिए यूरोपीय देशों में दो शोध हुए। नीदरलैंड में शहरों के वायु प्रदूषण और कोविड महामारी के बीच के संबंधों की पड़ताल की गई। वहीं एक अन्य शोध में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उत्तरी इटली में कोविड के ज्यादा घातक साबित होने में वायुमंडलीय प्रदूषण को सह-कारक माना जा सकता है? शोध को इसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए यूरोप के शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्रदूषण और कोविड से होने वाली मौतों पर वैश्विक स्तर पर शोध किया। इस टीम ने पूरी दुनिया में कोविड से होने वाली 15 प्रतिशत मौतों में प्रदूषण को सह-कारक माना था। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो ज्यादा प्रदूषित पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में कोविड से होने वाली वैसी मौतें जिनमें प्रदूषण सह-कारक था, उसका हिस्सा क्रमशः 15, 27 तथा 19 प्रतिशत माना गया। इस टीम ने भारत में भी कोविड के कारण होने वाली 17 प्रतिशत मौतों में प्रदूषण को सह-कारक माना। भारत में भी डॉक्टरों ने दिल्ली के 13 प्रतिशत संक्रमण के मामलों को वायु प्रदूषण से जोड़कर देखा था।

विज्ञानियों का मानना है कि लंबे समय तक पीएम 2.5 कणों के संपर्क के रहने से वायु प्रदूषण से संबंधित जोखिम मानव शरीर में पैदा होने लगता है। इस कारण से इंसान के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। यह भी माना जा रहा है कि कोविड-19 के वायरस मानव शरीर में एक खास एंजाइम के रिसेप्टर के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट है कि कोविड महामारी और प्रदूषण के संबंधों के पूरे तंत्र को समझने में विज्ञानियों को अभी काफी समय लगेगा, लेकिन इस संदर्भ में कुछ बातें समझी जा सकती हैं। मसलन हृदय की बीमारियों और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों के लिए कोविड वायरस ज्यादा घातक है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेना इन बीमारियों के जोखिम को पैदा करता है। अगर वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है तो अल्प समय में भी सांस संबंधी ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में प्रदूषित वातावरण से बाहर निकलने के कुछ समय बाद अपने आप या सामान्य इलाज से दूर हो जाती हैं। मगर उस अंतराल में कोविड संक्रमण हो जाए तो वह सामान्य परिस्थिति के संक्रमण से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यानी यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण कोविड के जोखिम को बढ़ा रहा है। यह वायरस इंसान की सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ाकर बीमारी की घातकता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अभी तक के तमाम वैज्ञानिक शोधों के आधार पर ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि अगर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और वायु प्रदूषण एक साथ मिल जाते हैं तो वह स्थिति काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

कृत्रिम आक्सीजन बनाम प्राकृतिक प्राणवायु

प्रमोद भार्गव

देशभर में बीते दिनों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौर में मेडिकल आक्सीजन के लिए हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई थी। मेडिकल आक्सीजन की मांग में अचानक कई गुना बढ़ोतरी होने के कारण अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हुई। हालांकि धीरे-धीरे इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सका, लेकिन मेडिकल आक्सीजन के अभाव में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाद में मेडिकल आक्सीजन का उत्पादन तेजी से बढ़ाया गया। फिलहाल मेडिकल आक्सीजन तैयार करने के जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, वे सभी आग लगने पर कुआं खोदने जैसे हैं। वैसे इस मामले में अच्छी बात यह है कि अब देश में मेडिकल आक्सीजन की कमी नहीं है। रोजाना आठ हजार टन आक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यह जो आपदा आई थी, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नतीजन आक्सीजन की आवाजाही के लिए जितने टैंकरों की जरूरत थी, उसके दस फीसद भी उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, ज्यादातर ऑक्सीजन संयंत्र हरियाणा, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि संकट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सबसे ज्यादा था। इसलिए आक्सीजन ढुलाई की चुनौती से निपटना मुश्किल हुआ।

यह माना गया कि कोरोना वायरस से पीड़ित रोगी को आक्सीजन की वास्तविक जरूरत के हिसाब से आक्सीजन दी जाती तो 10 से 25 प्रतिशत आक्सीजन बच सकती थी। लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में साधारण सफाईकर्मी रोगियों को आक्सीजन देने का काम कर रहे थे, यदि यही काम तकनीशियन करें तो आक्सीजन बच सकती है। कई अस्पतालों में पाइप लाइन से आक्सीजन लीकेज होकर भी व्यर्थ जा रही थी। साफ है, आक्सीजन की कमी को स्थानीय स्तर पर सुधारा जा सकता है। हमें इसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा। इस कमी का स्थाई हल करना है तो प्राणवायु उपलब्ध कराने वाले पेड़ों को अभियान चलाकर लगाया जाए।

वन संरक्षण को लेकर चलाए गए तमाम उपायों के बावजूद भारत में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 25 वर्षों में भारत में वन तेज रफ्तार से कम हुए हैं। वैश्विक वन संशोधन आकलन 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 से 2015 तक दुनिया में जंगल का दायरा तीन फीसद तक सिमट गया है।

वृक्षों का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वृक्ष जीव-जगत के लिए जीवनदायी तत्वों का सृजन करते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू-क्षरण न हों, यह पेड़ों की अधिकता से ही संभव है। वर्षा चक्र की नियमित निरंतरता पेड़ों पर ही निर्भर है। पेड़ मनुष्य जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, इसका वैज्ञानिक आकलन भारतीय अनुसंधान परिषद ने किया है। इस आकलन के अनुसार, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पर्यावरण के लिहाज से एक हेक्टेयर क्षेत्र के वन से 1.41 लाख रुपये का लाभ होता है। इसके साथ ही 50 साल में एक वृक्ष 15.7 लाख रुपये की लागत का लाभ देता है।

पेड़ों के महत्व का तुलनात्मक आकलन शीतलता पहुंचाने वाले विद्युत उपकरणों के साथ भी किया जा रहा है। एक स्वस्थ वृक्ष 10 कमरों में लगे वातानुकूलित संयंत्रों के बराबर ठंडक प्रदान करता है। घरों के आसपास पेड़ लगे हों तो वातानुकूलन की जरूरत 30 प्रतिशत घट जाती है। इससे 30 प्रतिशत तक बिजली की बचत होती है। एक एकड़ क्षेत्र में लगे वन छह टन कार्बन डाइआक्साइड सोखते हैं, इसके उलट चार टन आक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो 18 व्यक्तियों की वार्षिक जरूरत के बराबर होती है। आधुनिक यंत्रों के बढ़ते उपयोग से जुड़ जाने के कारण हम प्रकृति से निरंतर दूरी बनाते जा रहे हैं। संबंधित वैश्विक रिपोर्ट में पेड़ों के नष्ट होते जाने की जो भयावहता सामने आई है, उसके जारी रहने से पेड़ तो नष्ट होंगे ही, मनुष्य भी नष्ट होने से नहीं बचेगा? गोया, ऐसे जैविक हमलों से मानव को बचाए रखने के लिए आक्सीजन निर्माण के कृत्रिम उपायों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि स्थाई रूप से प्राणवायु देने वाले पेड़ घर-घर और गली-गली लगाए जाएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

एक गांव ऐसा भी

डा. सुरेश कुमार मिश्रा

हमारा गांव बहुत बड़ा है। दस हजार की आबादी है। सड़क, बिजली, पानी सबकुछ है गांव में। मंदिर-मस्जिद और पुस्तकालय भी है। हालांकि लोगों को मंदिर, मस्जिद और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए पुस्तकालय पर ताला पड़ा रहता है। अस्पताल है, किंतु वहां जाने वालों को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। सच कहें तो अस्पताल खुद भी हीन स्थिति में है। डाक्साब शहर से कभी आते नहीं, इसलिए गांव के सारे मरीज शहर जाते हैं। कहने को तो गांव में सह-शिक्षा वाला सरकारी स्कूल भी है, लेकिन वहां विद्यार्थी नहीं दिखाई देते। वहां सरपंच की भैंस और मास्साब की तनख्वाह, दोनों बंधी-बंधाई है। भैंस दूध देती है, मास्साब शिक्षा व्यवस्था को दूह लेते हैं।

गांव में एक बस अड्डा भी है। एक इसलिए कि एक ही बस आती है। चूंकि यहां सभी लोगों के पास अपने-अपने वाहन हैं, सो इस बस सेवा का लाभ वे ही ले पाते हैं, जो वाहन-सुख से वंचित हैं। इसलिए अड्डे पर ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं देती। अड्डे पर चाय की टपरी थी ही, वहां बैठने के लिए आलीशान चबूतरे और गोपनीय बातें करने के लिए मधुशाला और धूमपान केंद्र खोल दिए गए। मधुशाला और धूमपान केंद्र के चलते लोगों को पैसा देकर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुद अपनी जमापूंजी लुटाने यहां आ जाते। ऐसी बिना बुलाई भीड़ को देखकर किस अवसरवादी की जबान न लपलपाएगी! ऐसे ही एक दिन कृतार्थियों के मुखिया ने अपने दर्शन दिए। वहां आने वाले लोगों के लिए मधुपान और धूमपान की सुविधा मुफ्त कर दी। मुफ्त मिले तो जहर पीने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं। इस अवसर को भुनाने के लिए कृतार्थी के मुखिया ने अपनी मीठी-मीठी बातों से लोगों को फांसना शुरू किया। लोग मछली की तरह कांटे में फंसते चले गए। बहुत जल्द कृतार्थियों के मुखिया बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। चुनाव हुआ और भारी मतों से गांव के मुखिया बन बैठे। अब वे भोजन कम खाते हैं और जमीन ज्यादा। कहते हैं, ऐसा करने से ही उनका पाचन तंत्र ठीक बना रहता है। गांव के लोग उनकी तारीफ के पुल बांधते और कहते कि यह है बड़ा आदमी। बड़ी मछलियों द्वारा गांव में छोटी मछलियों को खत्म करने का खेल बदस्तूर जारी है।

ट्वीट-ट्वीट

प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अमरिंदर सिंह को कुछ वैसे ही लुभाते हुए नजर आएंगे जैसा उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ किया था। वहीं कांग्रेस सिद्धू और उनकी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं के चलते खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है।
स्वाति चतुर्वेदी@bainjal

कोवैक्सीन को इस साल के 'इंडियन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर' का खिताब दिया जाना चाहिए। उसके बमुश्किल ही कोई साइड इफेक्ट देखे गए। शायद ही उससे कोई मामला बिगड़ा हो। वहीं अब अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था ने भी कह दिया है कि वह अल्फा और डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। गब्बर@GabbbarSingh



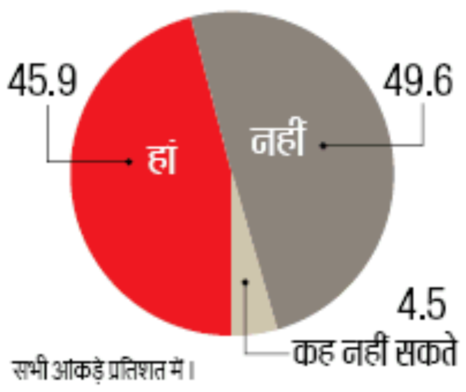
पिछले हफ्ते टीकाकरण का जो आंकड़ा 55 लाख रोजाना के दायरे में आ गया था वह मंगलवार और बुधवार को घटकर 30 लाख पर सिमट गया। यह दर्शाता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का स्टॉक चिंता का सबब है। चूंकि भंडारण और वितरण दोनों की जिम्मेदारी केंद्र के जिम्मे है तो टीकाकरण अभियान के सुस्त पड़ने की जवाबदेही भी उसी की होनी चाहिए।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को आम भेजकर मैंगो डिप्लोमेसी कर रही हैं। इसमें तृणमूल और भाजपा दोनों दलों के समर्थकों के लिए बड़ा सबक है। वह यह कि एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत को मत बढ़ाइए, क्योंकि नेता जानते हैं कि यह महज राजनीति है।
स्मिता प्रकाश@smitaprakash

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एक के बाद एक एफआइआर दर्ज होने से ट्विटर पर कुछ असर पड़ेगा?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या महंगाई बेलगाम होती दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दूध-सिलिंडर के हुए ऊंचे फिर से दाम,
सीजन है अब खाइए मलिहाबादी आम।
मलिहाबादी आम मालदा चौसा लंगड़ा,
करिए सुबहोशाम इसी को खाकर भंगड़ा।
चाह रही सरकार भूलिए आप बवंडर,
कहां कर रहे याद आप भी दूध-सिलिंडर।
- ओमप्रकाश तिवारी



प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

अनलाक के साथ बढ़ेगा राजनीतिक तापमान

कोविड महामारी की दूसरी लहर से उबर कर झारखंड अब लगभग पूरी तरह अनलाक हो गया है। राज्य का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मोर्चों पर एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। पाबंदियों के चलते मुख्य विपक्षी दल भाजपा जहां सड़क पर नहीं उतर पा रही थी, वहीं अब सरकार को घेरने के लिए मंथन करने व आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। उधर, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा विधायक दल के नेता बाबू लाल मरांडी को चौतरफा घेरने में जुटा है। रघुवर दास को लेकर प्रदेश पार्टी संगठन भी कुछ दुविधा में दिख रहा है, जिसका सत्ता पक्ष भरपूर फायदा उठा रहा है।

कोरोना की पाबंदियों के चलते अभी तक राजनीतिक दलों की गतिविधियां सीमित थीं। कार्यक्रमों से लेकर बैठकों तक का आयोजन आनलाइन चल रहा है। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक भी इन्हीं पाबंदियों के बीच हो रही है। बैठक में प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करने वाली टीम इस पर मंथन कर रही है कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार की घेराबंदी करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा बड़ा आंदोलन छेड़ने की रणनीति बना रही है।

दरअसल पिछले कुछ महीनों से भाजपा के खिलाफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। तीन विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की शिकस्त ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन का हौसला बढ़ा दिया है। भाजपा अब उपचुनावों की हार से उबर कर आगे बढ़ना चाहती है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर खूब माथापच्ची हुई। पार्टी के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपने नेताओं का बचाव करना भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ कुछ मामलों में राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिये जांच की कार्रवाई शुरू की है। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इसे लेकर असहज दिखता है। यही वजह है कि रघुवर दास के बचाव में पार्टी के बड़े नेता सामने नहीं आए। सत्तारूढ़ गठबंधन इसे भाजपा के अंदरूनी बिखराव के तौर पर प्रचारित कर रहा है।



रांची स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में (बाएं से) अन्नपूर्णा देवी, सुभाष सरकार, दिलीप सैकिया, दीपक प्रकाश, रघुवर दास, सीटी रवि, बाबूलाल मरांडी व धर्मपाल सिंह। जागरण आर्काइव

भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल सरयू राय भी खड़ी कर रहे हैं। कभी भाजपाई रहे पूर्व मंत्री सरयू राय ने पिछले चुनाव के वक्त टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर चर्चा में आए। इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मांग की है कि रघुवर दास के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार एक आयोग बनाकर उनके पूरे कार्यकाल की जांच करा ले। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा। रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ आरोपों से पार्टी को परेशानी का सामना करने और जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा।

सत्तारूढ़ गठबंधन के रवैये को राजनीतिज्ञ रघुवर दास की कार्यशैली का प्रत्युत्तर भी मानते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष के तत्कालीन नेता हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से जमीन लेने के आरोप लगाए थे और विशेष जांच दल का गठन किया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए इसकी प्रबल संभावना है कि यह प्रकरण आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा।

अपनी-अपनी राजनीति : झारखंड में आदिवासियों की मिनी असेंबली कही जाने वाली झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की नई समिति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। इसके मूल में काउंसिल के नए नियम हैं, जिसके तहत यह प्रविधान किया गया है कि टीएसी के पदाधिकारियों और सदस्यों के मनोनयन में राजभवन की कोई भूमिका नहीं होगी। इससे पहले हेमंत सरकार ने दो बार टीएसी के सदस्यों की सिफारिश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन तकनीकी अड़चन बताकर इसे वापस कर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के मार्फत टीएसी के गठन के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने नई कमेटी गठित कर दी। इसमें भाजपा के तीन विधायकों को भी सदस्य बनाया गया है। नवगठित टीएसी की पहली बैठक में भाजपा विधायक शामिल नहीं हुए। भाजपा ने इसका विरोध किया है। आरोप लगाया गया है कि टीएसी का गठन असंवैधानिक है। इसमें राजभवन को विश्वास में लेना चाहिए।

मंथन



डॉ. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

'बीमारू' की बदलती तस्वीर

'बीमारू' राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश के पास यह क्षमता है कि एकीकृत प्रयासों और उपलब्ध संसाधनों के बूते विकास की प्रक्रिया में वह अपने समकक्ष राज्यों से काफी आगे बढ़ सकता है



बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत विकास की राह पर अग्रसर 'बीमारू' प्रदेश। फाइल

हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए स्थायी विकास लक्ष्यों (एसीडीजी) के संदर्भ में भारत के 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां समस्त भारत के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कुल अंक 2019 में 60 से बढ़कर 2020 में 66 तक पहुंच गए हैं, वहीं सभी राज्यों में यह वृद्धि कम या ज्यादा देखने को मिली है। एसडीजी के संदर्भ में शीर्ष पर 75 अंकों के साथ केरल है, जबकि सबसे नीचे 52 अंकों के साथ बिहार है। बिहार इन दो वर्षों में 48 से 52 अंकों तक ही पहुंचा, जबकि असम 49 से बढ़कर 57 अंकों तक पहुंचा। नीचे के पायदान के अन्य राज्यों में झारखंड 50 अंकों से 56 अंक, मध्य प्रदेश 52 अंकों से 62 अंक, राजस्थान 50 अंकों से 60 अंक तक पहुंचे। बंगाल भी 56 अंकों से बढ़कर 62 अंकों तक ही पहुंचा। उत्तर पूर्व राज्यों में मेघालय 52 अंकों से 62 अंकों तक पहुंचा, जबकि अरुणाचल प्रदेश 51 अंकों से 60 अंकों तक पहुंचा। वहीं नगालैंड 51 अंकों से 61 अंकों तक और मणिपुर 59 अंकों से 64 अंकों तक पहुंचा।

हालांकि इस बीच कुछ राज्य आकांक्षी से निष्पादक की श्रेणी में आ गए और कुछ अन्य पिछड़े राज्यों का भी कार्य निष्पादन ठीक रहा है, लेकिन अभी भी उनका स्तर बेहतर राज्यों से काफी नीचे है। अभी भी सात राज्य 60 या उससे कम अंक ही प्राप्त कर पाए हैं। छह राज्यों के अंक 60 से अधिक लेकिन 65 से कम हैं। 65 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को फ्रंट रनर (यानी अगड़े माना गया है)। अभी भी 13 राज्य ऐसे हैं, जिन्हें अगड़े की श्रेणी में आना बाकी है। प्रश्न यह है कि हमारे सभी राज्य अगड़े की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं।

देखा जाए तो हमारा देश लंबे समय से क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के फार्मूले के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग उनके मानव विकास के स्तर के आधार पर की जाती है। एसडीजी में कई कारकों को शामिल किया गया है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं थे। मानव विकास सूचकांक में प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य के स्तर और शिक्षा के स्तर को उनके संकेतकों के आधार पर शामिल किया गया था।

वर्तमान में एसडीजी में 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छ जल और सफाई, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और ग्रोथ, समानता, शांति और न्याय हेतु सबल संस्थाएं, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग एवं उत्पादन इत्यादि शामिल हैं। इन लक्ष्यों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए 117 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है।

हमारे देश के पिछड़े राज्यों में अधिक जनसंख्या वाले राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा आदि शामिल थे। कई बार इन राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) के नामों को जोड़कर 'बीमारू' राज्य भी कहा जाता रहा है। यदि इन 'बीमारू' राज्यों के पिछले तीन दशकों का आकलन करें तो वर्ष 1990-91 से 2004-05 के बीच बिहार की ग्रोथ रेट माइनस एक प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 1.78 प्रतिशत, असम की 3.18 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 2.79 प्रतिशत ही रही। लेकिन राजस्थान की ग्रोथ 5.11 प्रतिशत और ओडिशा की 5.52 प्रतिशत रही। अगड़े राज्यों की ग्रोथ इस दौरान 6.03 प्रतिशत, जबकि पिछड़े राज्यों की मात्र 2.7 प्रतिशत ही रही। लेकिन 2004-05 से 2019-20 के दौरान पिछड़े राज्यों की ग्रोथ सम्मानजनक रही। बिहार में जीडीपी ग्रोथ 8.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7.9, उत्तर प्रदेश में 6.5, राजस्थान में 6.9, ओडिशा में 5.9 और झारखंड में 6.7 प्रतिशत की दर से दर्ज की गई। यह भी सच है कि चूंकि इन राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए तेज आर्थिक संवृद्धि के बाद भी प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से ये राज्य अभी भी बहुत पीछे हैं, जिस कारण वहां के लोगों में गरीबी, भूखमरी अधिक है।

एसडीजी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दो ही वर्षों में 42 अंकों से बढ़कर 60 तक पहुंचा। ऐसा इसलिए है कि यहां विद्युतीकरण शत प्रतिशत और एलपीजी कनेक्शन लगभग सभी परिवार को दिया जा चुका है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश के अंक 25 से बढ़कर 60 हो गए हैं। स्वच्छ जल एवं सफाई व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश के अंक दो वर्षों में 55 से 85 पहुंच गए हैं। शांति, न्याय और सबल संस्थाओं के संदर्भ में भी इस राज्य के अंक 61 से बढ़कर 79 तक पहुंच गए हैं। देखा जाए तो चाहे 17 कारकों में से उत्तर प्रदेश का कार्यनिष्पादन सिर्फ पांच कारकों में ही उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ है, लेकिन इन्हीं कारकों के कारण इस राज्य को संयुक्त अंकों में 11 अंकों की बढ़त हासिल हुई है। यानी अन्य कारकों में भी यदि बेहतरी होती है तो उत्तर प्रदेश अगड़े राज्यों में आ सकता है। गौरतलब है कि जैसे-जैसे प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है, सरकार का राजस्व भी बढ़ता है, जिसके चलते शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में बेहतरी संभव है।

आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, उत्तर प्रदेश स्थायी विकास के ऊंचे मापदंड प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे।

4000 रुपये जुर्माना पांच युवकों पर लगाया गया है चोरीछिपे हिमाचल के आनी स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा में जाने पर। पुलिस ने यह कार्रवाई उपायुक्त कुल्लू के श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक के आदेश का उल्लंघन करने पर की है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

जिम्मेदारी का भाव होना जरूरी

कोरोना संक्रमण के बीच बदली परिस्थितियों में पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें वनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में हर साल विभिन्न प्रजातियों के डेढ़ से दो करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सरकारी आकलन के मुताबिक यहां के जंगल प्रतिवर्ष 98 हजार करोड़ से अधिक की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके बड़ा सवाल फिजा में है कि क्या हम वनों एवं पौधारोपण के महत्व को गंभीरता से ले रहे हैं। यदि थोड़ी भी सजगता और गंभीरता दिखाई जाती तो पिछले 20 वर्षों में राज्य में वनावरण कहीं आगे निकल चुका होता, लेकिन यह आज भी 46 फीसद के आसपास ठहरा हुआ है।

साफ है कि नीति और नीयत में कहीं न कहीं कोई खामी है। यदि रोपे गए पौधों की प्रभावी मानीटरिंग और जिम्मेदारी के साथ देखभाल की जाती तो शायद यह प्रश्न भी नहीं उठता। कहने का आशय यह कि पौधारोपण को लेकर अब अधिक सजग होने की जरूरत है। वैसे भी कहा गया है कि एक पेड़ सौ पुत्रों के समान होता है। रोपित पौधों की देखभाल ठीक वैसे ही की जानी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। इस जिम्मेदारी का भाव न केवल वन समेत अन्य सरकारी विभागों, बल्कि जनसामान्य में भी जाग्रत होना आवश्यक है। अब जबकि, वन महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है तो यह बात जरूरी हो जाती है कि हमें पौधे लगाकर उनकी तरफ मुंह फेर लेने की परिपाटी को त्यागना होगा। फिर चाहे वह वन क्षेत्र हों, शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थल, वहां पौधारोपण को बेहद गंभीरता से लेना होगा। बात समझने की है कि धरती को हरा-भरा रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण और रोपित पौधों का संरक्षण आवश्यक है।

पौधारोपण को लेकर अधिक गंभीरता से कार्य करने की दरकार है। पौधों की देखभाल के मामले में सरकारी विभागों के साथ ही जनसामान्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी

सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न सिर्फ पौधे लगाने होंगे, बल्कि अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। सरकारी विभागों को भी सिर्फ पौधारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेने की परिपाटी का त्याग करना होगा। रोपे गए पौधे जीवित रहें, इसकी निरंतर मानीटरिंग जरूरी है। अब तो इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा सकती है। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।

कुल मिलाकर सरकारी विभागों और जनसामान्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण व वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से लेना होगा। तभी सही मायने में किसी भी मुहिम को सार्थक माना जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश

सतर्कता में ही बचाव

किसी भी आपदा से निपटने के पूर्व में किए गए प्रबंध काफी अहम होते हैं। यह सही है कि आपदा को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा से होने वाली क्षति को अवश्य कम किया जा सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर ने काफी नुकसान किया है। कई लोगों की जान चली गई और अब भी कई लोग इससे जूझ रहे हैं। विशेषज्ञ तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में इससे निपटने के तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। अस्पतालों में पहले ही व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। राज्य के सबसे बड़े शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में बच्चों के साथ उनकी माताओं के रहने की भी व्यवस्था हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल मरीजों से भर रहे थे, जबकि आक्सीजन की भी मांग बढ़ गई थी। यह सही है कि राज्य में आक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ा था। प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। टीकाकरण करने में हिमाचल अव्वल है, लेकिन अभी तक 18 साल से कम आयु वर्ग का



संक्रमण की पूर्णतया समाप्ति तक संबंधित नियमों का पालन अनिवार्यरूप से होना चाहिए। फाइल

कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हुआ है, लेकिन लोगों को नियमों का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए

टीकाकरण नहीं हुआ है। इसी कारण सरकार ने हर तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना वायरस की दोनों लहर के दौरान चिकित्सकों, नर्सों के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों में बेहतर सेवाएं दी हैं। इस दौरान कई समाजसेवी संगठन भी आगे आए हैं। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन काफी कमजोर हो गई है और जल्द ही इसके पूरी तरह थमने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्व प्रबंध कर लिए हैं, इनकी समय-समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए। अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राज्य के लोगों को भी हर तरह की सतर्कता बरतनी होगी। बेशक सरकार ने दूसरी लहर के दौरान लगाई गई बंदिशें हटा ली हैं, लेकिन लोगों को जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। मास्क और शारीरिक दूरी के पालन को अपनी आदत ही बना लिया जाना चाहिए। सतर्कता से ही महामारी को मात दी जा सकेगी।

हरियाणा

अराजकता पर अंकुश

विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, लेकिन हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बन गई है, उस पर अंकुश लगाना आवश्यक है और हरियाणा सरकार ने इसके लिए संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू कर दिया है। यद्यपि इस कानून की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना अब जारी हुई है। वैसे तो इस तरह का कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा में हिंसक आंदोलनों के दौरान हर बार करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी जाती है।

आंदोलनों के दौरान जो लोग बसों, ट्रेनों, बस स्टेशनों, सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों को क्षति पहुंचाते हैं, वह आम जनता की कमाई से बना होता है। जिन निजी संपत्तियों को निशाना बनाया जाता है, वे भी किसी परिवार का सहारा होती हैं, आसरा होती हैं। भले ही आंदोलनकारियों के नेता बाद में यह कहकर पल्ला झाड़ लें कि लूटपाट और हिंसा करने



किसी भी प्रकार की हिंसा का अधिकार नहीं देता लोकतंत्र। फाइल

वाले अराजक तत्व थे, आंदोलनकारी नहीं, लेकिन इसपर विश्वास करना मुश्किल होता है। कारण यह कि आंदोलनकारियों के नेता ऐसे लोगों को निर्दोष होने का राग अलापने लगते हैं। रही बात आंदोलनकारियों की मांगो की, तो हो सकता है कि उनकी मांगें उचित हों, लेकिन यह उनके और सरकार के बीच की बात है, उसके लिए वे दूसरों का क्यों नुकसान करते हैं। वे

संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संपत्ति क्षति वसूली कानून आवश्यक था

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आंदोलन करें। लोकतंत्र उन्हें किसी भी तरह की हिंसा का अधिकार नहीं देता। एक बात और सरकार को यह भी सोचना होगा कि केवल संपत्ति की वसूली का कानून बनाने से केवल काम नहीं चलेगा। उसे कठोरता से लागू भी करना होगा, जब तक आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली नहीं होगी, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक वे बार-बार ऐसा करते रहेंगे।

इसलिए आवश्यक है अराजक तत्वों से कठोरता वसूली की जाए, भले ही इसके लिए उनकी संपत्ति नीलाम करनी पड़ी, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लग सकेगा। यह शाश्वत सत्य है कि भय के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं।

बंगाल

कैंसर अस्पताल की आवश्यकता

बंगाल में हर साल कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंतु सूबे में अत्याधुनिक संसाधानों से लैस बेहतर उपचार वाले कैंसर अस्पतालों की संख्या काफी कम है। ऐसे में लोग बेहतर इलाज के लिए मुंबई से लेकर चेन्नई, बेंगलुरु से लेकर देश के दूसरे शहरों में जाने को मजबूर होते हैं। मुंबई के विख्यात टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में उपचार के लिए देशभर से लोग पहुंचते हैं और वहां भी मरीजों का काफी दबाव है। यही वजह है कि मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की शाखाएं कई राज्यों में खोली गई हैं और भी खुलेंगी, ताकि मुंबई पर रोगियों के दबाव को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, असम और पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश तक में शाखाएं खुल चुकी हैं। यही नहीं टाटा की ओर से कोलकाता के राजारहाट न्यूटाउन में भी वर्षों पहले कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। हालांकि इस अस्पताल का मुंबई टाटा मेमोरियल से कोई संबंध नहीं है। यही वजह है कि मुंबई की तुलना में उपचार थोड़ा महंगा है। अब बंगाल के लोगों को यहीं कैंसर का कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टाटा मेमोरियल के साथ मिलकर प्रदेश में दो कैंसर अस्पताल बनाने की योजना बना रही हैं। ममता का कहना है कि राज्य के लगभग 25 फीसद कैंसर रोगी इलाज के लिए मुंबई जाते हैं। लोगों के मुंबई न जाना पड़े, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही यहां दो नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। टाटा मेमोरियल के साथ मिलकर राज्य सरकार इन अस्पतालों की स्थापना करेगी। इनमें से एक अस्पताल महानगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल (एसएसकेएम) में बनेगा तो दूसरा अस्पताल सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल मेडिकल कालेज अस्पताल में बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन दोनों अस्पतालों के बन जाने से यहां के लोगों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बंगाल के लगभग 25 फीसद कैंसर रोगी इलाज के लिए मुंबई जाते हैं। इन लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही यहां दो नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे

मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की मदद से संचालित होता है। इस वजह से यहां काफी कम खर्च में लोगों को कैंसर का बेहतर इलाज मिल जाता है। यही वजह है कि अधिक लोग मुंबई पहुंचते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार का यह फैसला सराहनीय है और यदि ये अस्पताल बन जाएंगे तो लोगों को काफी सहूलियत और सुविधा होगी। कैंसर काफी खतरनाक बीमारी है। इससे पार पाने के लिए इसकी समय पर पहचान और फिर उचित इलाज की जरूरत होती है। अगर अस्पताल नजदीक होगा तो लोगों को ये दोनों सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। इससे यह बीमारी जानलेवा भी साबित नहीं होगी।

अब महारानी लक्ष्मीबाई होगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम

जागरण संवाददाता, झांसी

- जिलाधिकारी ने नाम परिवर्तन को लेकर शासन को भेजा प्रस्ताव
- सिर्फ रेलवे स्टेशन के नाम में ही किया जाएगा परिवर्तन, जिले के नाम में नहीं होगा फेरबदल

उप्र सरकार की मंजूरी मिली तो झांसी रेलवे स्टेशन को विश्वभर में झांसी को पहचान दिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मिलेगा। सांसद अनुराग शर्मा की सिफारिश पर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हालांकि नाम परिवर्तन सिर्फ रेलवे स्टेशन का होगा, जबकि जिले को झांसी के नाम से ही पहचाना जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही योगी सरकार केंद्र के पास इस निर्णय को भेज कर औपचारिकता पूरी कर लेगी।

योगी आदित्यनाथ सरकार पहले ही तीन प्रमुख स्थान, इलाहाबाद से प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर चुकी है। वहीं, अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। झांसी स्टेशन का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाएगा। जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही आगे की कार्यवाही के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश की थी। सांसद ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव करीब दो साल पहले रेलवे की जोनल मीटिंग के दौरान भी रखा था। उन्होंने यह प्रस्ताव बुंदेलखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रेलवे के समक्ष इसे बड़े जोर-शोर से रखा था। अब जिलाधिकारी द्वारा इस प्रस्ताव को आगे की कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है।



नाम बदलने का प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। फाइल/इंटरनेट मीडिया

झांसी रेलवे स्टेशन को लेकर क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने जो प्रस्ताव पूर्व में रखा था, उसे शासन और मंडल रेल प्रबन्धक झांसी को भेजा गया है। इसमें झांसी रेलवे स्टेशन का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की संस्तुति की गई है। जनपद का नाम बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\- आन्द्रा वामसी, ज़िलाधिकारी

रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है। स्टेशन का नाम परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

\- डा.शिवम शर्मा, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेल (प्रयागराज)

राजौरी में सेना ने बनाई 'रहमत की दीवार'

राज्य ब्यूरो, जम्मू : नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ सटे जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सेना ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने शिविर की बाहरी दीवार को रहमत की दीवार में बदल दिया है। दीवार पर लगी कीलों पर जहां जरूरतमंदों के लिए कपड़े और जूते लटक रहे हैं, तो वहीं स्टील की दो आलमारियों में चौबीस घंटे खाद्य सामग्री उपलब्ध रहती है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि रहमत की दीवार सेना की एस आफ स्पेड्स डिवीजन ने तैयार की है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए सेना को सराहा है। उन्होंने कहा कि रहमत की दीवार पर जो सामान है, वह पुराना नहीं है। यह सामान सिर्फ सैन्याधिकारी, सैन्यकर्मी या अन्य सुरक्षाबलों के जवान ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग भी उपलब्ध कराते हैं। राजौरी पुलिस और रोटरी क्लब राजौरी भी इसमें हमारी मदद कर रही है।

रहमत की दीवार पर सेना ने अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी भाषा में दानियों से सहयोग के लिए कई संदेश भी लिखे हैं। एक संदेश में लिखा है कि जो वस्तु आपके उपयोग की नहीं है, वह दूसरों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आएं हमारा सहयोग करें और वह सामान दान करें जो जरूरतमंदों के काम आए।

छह माह में 18 लाख 88 हजार श्रद्धालुओं ने लगाई मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी

राकेश शर्मा, कटड़ा

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है। जून के प्रथम पखवाड़े में प्रतिदिन दो से तीन हजार श्रद्धालु ही वैष्णो देवी के भवन पहुंच रहे थे, लेकिन अब छह से आठ हजार श्रद्धालु रोजाना मां के दर्शन के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। तीन महीने के बाद एक बार फिर मां वैष्णो देवी का भवन व आधा शिविर कटड़ा श्रद्धालुओं से गुलजार होना शुरू हो गया है। इस वर्ष अब तक 18,88,188 श्रद्धालु वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। गुरुवार दोपहर 1:00 बजे तक 2,500 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इस साल मार्च में सबसे अधिक 5,25,198 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि अप्रैल में 3,21,735 ने दर्शन किए।

हेलीकाप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा हो या फिर मां वैष्णो देवी भवन पर रहने के साथ सुबह-शाम दिव्य आरती में शामिल होना, सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को आसानी से मिल रही हैं।

मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बरसात के लिए ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

\- रमेश कुमार, सीईओ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड

यात्रा के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी

कटड़ा आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। अगर श्रद्धालु दो दिन पुरानी रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन पालीमरेस चेन रिएक्शन (आरपीटीसीआर) निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है तो उसे यात्रा करने की इजाजत है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते श्री मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

गुजरात में जगन्नाथ रथयात्रा को मिल सकती है मंजूरी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथयात्रा को कोरोना महामारी के बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार व पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक के बाद दोपहर तक अखाड़ों, भजन मंडली व झांकियों के बिना रथयात्रा को मंजूरी मिलने की संभावना है। रथयात्रा के दौरान जनता कर्फ्यू रहेगा ताकि दर्शनार्थियों को रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रथयात्रा से पहले मंगला आरती में शामिल होंगे। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रथों के आगे झाड़ू लगाकर रथयात्रा रवाना करेंगे।

गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा की पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जनता कर्फ्यू के साथ सीमित रथों को मंजूरी देने पर सहमति बनी है। रथों को खींचने के लिए 150 ऐसे खलासियों को चुना जाएगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महाराज ने बताया कि मंदिर में रथयात्रा की तैयारियां की जा रही हैं।

हिमाचल में एक टिकट पर कई ट्रेन में सफर

जागरण संवाददाता, शिमला

- शिमला-कालका ट्रैक पर शुरू हुई 'हाप आन, हाप आफ' सुविधा
- जानकारी के अभाव में पहले दिन नहीं मिला टिकट का एक भी खरीदार

हिमाचल प्रदेश में शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर पर्यटकों की सुविधा के लिए 'हाप आन, हाप आफ' टिकट की सुविधा गुरुवार से शुरू हुई है। इस सुविधा के तहत यात्री दिन में एक बार टिकट लेता है तो वह किसी भी ट्रेन में सफर कर सकता है। योजना का पहला दिन होने के कारण लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए एक भी टिकट नहीं बिका। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग शिमला से कालका जाते या आते समय रास्ते में पिकनिक मनाना चाहते हैं, उनके लिए यह टिकट लाभदायक हो सकती है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह उपयोगी हो सकती है।

यदि कोई यात्री कालका से शिमला के लिए सुबह रेलगाड़ी से रवाना होता है तो वह सोलन में उतरकर काम निपटा सकता है। घूम-फिर सकता है। इसके बाद जो भी ट्रेन शिमला की ओर आती है, उसमें उसी टिकट से यात्रा कर सकता है। ये टिकट एक से तीन दिन के लिए मिलनी शुरू हो गई है। अधिकारियों की मानें तो आने वाले समय में इस टिकट की मांग बढ़ सकती है। शिमला रेलवे स्टेशन अधीक्षक जोगेंद्र ने बताया कि पहले दिन 'हाप आन, हाप आफ' टिकट किसी ने नहीं खरीदा है। उन्होंनें उम्मीद जताई की जल्द ही इस योजना का आकर्षण बढ़ेगा।

यह होगा किराया

कितना किराया	बड़े	बच्चे
एक दिन	500	250
दो दिन	800	400
तीन दिन	1000	500

नोट : किराया रुपये में

यह है टिकट का फायदा

इस टिकट को लेने के बाद दिनभर शिमला-कालका के बीच चलने वाली रेलगाड़ी में सफर किया जा सकता है। दोबारा टिकट लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टेशन पर उतरकर घूमने के बाद दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं।

यह है सामान्य किराया

रेलगाड़ी में शिमला से कालका का सामान्य किराया 70 रुपये है। फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का किराया 400 रुपये है। विस्टाडोम ट्रेन का किराया शिमला से कालका तक 800 रुपये है। शिमला-कालका ट्रैक पर छह रेलगाड़ियां चलती हैं। कोरोना काल में पांच रेलगाड़ियां दोबारा शुरू हुई हैं और अभी एक और शुरू होनी है।

25 फीसद सस्ता होगा गरीब रथ का सफर

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- रेलवे बोर्ड ने गरीब रथ में किराये की पूर्व की व्यवस्था बहाल की

भीषण गर्मी में एसी क्लास की गरीब रथ एक्सप्रेस का सफर यात्रियों को दोहरी राहत देगा। ठंडी हवा के बीच यात्रियों का किराया भी अन्य ट्रेनों की अपेक्षा 25 प्रतिशत कम होगा। रेलवे बोर्ड ने गरीब रथ स्पेशल के किराये में कोई बदलाव नहीं किया है। पूर्व किराये की फीडिंग के साथ गरीब रथ स्पेशल की बुकिंग शुरू हो गई है।

पिछले साल 23 मार्च को कोरोना के कारण संपूर्ण लाकडाउन में ट्रेनें बंद की गई थीं। रेलवे ने नियमित ट्रेनों को बंद कर एक मई से श्रमिक स्पेशल और 13 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। इन ट्रेनों में तत्काल का आरक्षण लागू किया गया। इसके बाद रेलवे ने क्लोन स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू कीं। क्लोन स्पेशल का किराया तो सामान्य रहा, लेकिन वरिष्ठ नागरिक सहित सभी तरह के किराये की रियायत को समाप्त कर दिया। फेस्टिवल स्पेशल में अब भी तत्काल का किराया ही रेलवे ले रहा है। नियमित ट्रेनों को बंद करने के बाद रेलवे ने गरीब रथ का संचालन गुरुवार से शुरू किया। इसके किराये को लेकर बोर्ड में मंथन किया गया। आखिर में तय किया गया कि गरीब रथ का किराया पूर्व की तरह कम होगा। गरीब रथ एसी थर्ड श्रेणी बोगियों वाली ट्रेन है, जिसमें साइड लोअर और अपर बर्थ के बीच एक मिडिल बर्थ भी होती है। पुष्पक जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों की एसी थर्ड कनवेंशनल बोगी में जहां 64 सीट होती हैं, वहीं गरीब रथ में 72 होती है। इस कारण गरीब रथ का किराया कम होता है।

इतना पड़ेगा किराये में अंतर

ट्रेन 05303 गोरखपुर-एर्नाकुलम फेस्टिवल स्पेशल का एसी थर्ड का लखनऊ से भोपाल का किराया 1180 रुपये है, जबकि ट्रेन 02533 पुष्पक स्पेशल का किराया 965 रुपये है। ट्रेन 05307 भोपाल गरीब रथ स्पेशल का लखनऊ से भोपाल का किराया 705 रुपये तय किया है। इसी तरह लखनऊ से रायपुर का गरीब रथ का किराया 820 रुपये है। इस ट्रेन में बेडरोल नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य चार्ज के रूप में 25 रुपये यात्रियों को देना होगा।

'मुझे मंगलसूत्र की बेड़ियों में न जकड़ो, मैं पढ़ना चाहती हूं'

प्रकाश वत्स, पूर्णिया: पापा, मुझे मंगलसूत्र की बेड़ियों में न जकड़ो, मैं पढ़ना चाहती हूं। मैं कुछ बनना चाहती हूं...। प्लीज मेरे अरमानों की चिता मत जलाइए...। बस यही रट थी, उस 14 वर्षीय किशोरी की। पिता आर्थिक लाचारी के खूंटे से बंधे थे। बिहार सरकार अब बिटिया को पढ़ाई में मदद करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बच्ची को पढ़ाई में हर सरकारी योजना का समुचित लाभ मिले और किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक पहल की जाएगी।

पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव की 14 वर्षीय किशोरी ने खुद अपने हाथों ही गले में पड़ा मंगलसूत्र उतार फेंका। माता-पिता सहित स्वजन बिटिया से ससुराल जाने की मनुहार करते रहे, लेकिन किशोरी ने किसी की नहीं सुनी। किशोरी की जिद को समाज के कई लोगों का समर्थन मिला और आखिरकार किशोरी की जीत हुई।

इस कहानी की शुरुआत पूर्णिया-कटिहार मार्ग पर कटिहार जिले की सीमा पर अवस्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिवानगंज गांव से हुई। पांच दिन पूर्व इसी गांव के गिरीश मंडल ने अपनी कक्षा नौ में पढ़ने वाली बिटिया की शादी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद एक 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी थी। जबरन शादी होने के बाद भी किशोरी सुसराल न जाने की जिद पर कायम रही। बाद में समाज और चाइल्ड लाइन व पुलिस की तत्परता से अधेड़ दूल्हे व दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

अब मिस्ड काल पर मिलेगा देव भाषा संस्कृत का ज्ञान

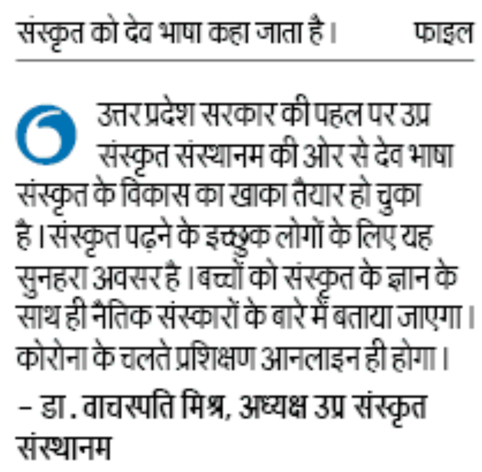
जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ

- उत्तर प्रदेश में शुरू होगा प्रशिक्षण, फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत में बोलेंगे बच्चे

यदि आप देव भाषा संस्कृत को बोलना या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप घर बैठे 9522340003 नंबर पर मिस्ड काल कर निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए पंजीयन करा सकते हैं। शुक्रवार से पंजीयन शुरू हो जाएगा। देव भाषा संस्कृत के प्रति लगाव पैदा करने और सीखने के इच्छुक लोगों को मौका देने के लिए उप्र संस्कृत संस्थानम की ओर से यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस प्रशिक्षण में डाक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, विद्यार्थी या नौकरी पेशा कोई भी हिस्सा ले सकता है।

15 दिन का होगा संस्कृत का परिचय कोर्स : उप्र संस्कृत संस्थानम की ओर जारी किए गए नंबर पर मिस्ड काल करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी पर क्लिक करते ही गूगल फार्म आएगा। फार्म में व्यवसाय व पढ़ाई सहित अन्य जानकारियां भरनी होंगी। व्यवसाय के अनुरूप ही ग्रुपवार पढ़ाई होगी। पहले 15 दिन तक संस्कृत में बोलने का परिचय कोर्स होगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा।

अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत बोलेंगे नौनिहाल : पढ़ाई के साथ ही बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार की जानकारी हो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। उप्र संस्कृत संस्थानम की ओर से जिले स्तर पर संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी के बीच अब हर ग्राम पंचायतों में बच्चों को संस्कार देने के लिए निःशुल्क पाठशालाएं खोली जाएंगी। बच्चे अब फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत में भी बोलेंगे।



संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। फाइल

उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर उप्र संस्कृत संस्थानम की ओर से देव भाषा संस्कृत के विकास का खाका तैयार हो चुका है। संस्कृत पढ़ने के इच्छुक लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बच्चों को संस्कृत के ज्ञान के साथ ही नैतिक संस्कारों के बारे में बताया जाएगा। कोरोना के चलते प्रशिक्षण आनलाइन ही होगा।

\- डा. वाचस्पति मिश्र, अध्यक्ष उप्र संस्कृत संस्थानम

8 जेल अधिकारियों को इटली में कैदियों की पिछले साल अप्रैल में की गई पिटाई के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 23 को निलंबित कर दिए गए हैं। जेल में कोरोना फैलने की खबर के बाद कैदियों ने मास्क आदि की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था।

दुनिया में तेजी से फैल रहा डेल्टा वैरिएंट

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : दुनिया में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। यह तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि यह वैरिएंट 96 देशों तक पहुंच चुका है। साथ ही आगाह किया कि आने वाले महीनों में कोरोना का यह बेहद संक्रामक स्वरूप विश्वभर में हावी हो जाएगा। यह वैरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था।

डब्ल्यूएचओ के साप्ताहिक डाटा के अनुसार, मंगलवार तक दुनिया के 96 देशों में डेल्टा वैरिएंट के मामले पाए गए। यह संभव है कि वास्तविक आंकड़ा अधिक हो सकता है। क्योंकि वायरस के इस स्वरूप की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमताएं सीमित हैं। कई देशों ने बताया है कि उनके यहां डेल्टा के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। अस्पतालों में इस वैरिएंट के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की इस स्वास्थ्य एजेंसी ने चेताया है कि आने वाले महीनों में डेल्टा वैरिएंट के सबसे हावी होने का अंदेशा है। पिछले हफ्ते डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेबरेसस ने कहा था कि अब तक कोरोना के जितने वैरिएंट की पहचान हुई है, उनमें से डेल्टा सबसे संक्रामक है। यह वैरिएंट उन लोगों में तेजी से फैल रहा है, जिनको कोरोना टीका नहीं लगा है। उन्होंने कहा, 'कुछ देशों ने पाबंदियों में ढील दी है, जिसके कारण विश्व में संक्रमण बढ़ रहा है।' ताजा डाटा के मुताबिक, अल्फा वैरिएंट के मामले 172 देशों में मिले हैं। बीटा के 120 और गामा के 72 देशों में मामले पाए गए हैं।

यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी : समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। कहा कि यूरोप में नए मामलों में 10 हफ्ते से जारी गिरावट का दौर खत्म होने वाला है। अगर लोग अनुशासित नहीं रहे तो एक और लहर को टाला नहीं जा सकता है।



कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे को देखते हुए वैश्विक स्तर पर वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। गुरुवार को रूस की राजधानी मास्को में बूस्टर डोज लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग। एपी

सितंबर तक 10 फीसद आबादी को वैक्सीन लगाने की अपील

लंदन, प्रेट्र : डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने गुरुवार को प्रत्येक देश से सितंबर तक अपनी 10 फीसद आबादी को वैक्सीन लगाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया, 'जब तक हम हर जगह महामारी खत्म कर नहीं कर देंगे, तब तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे।' उन्होंने यह चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई देश टीकाकरण में काफी आगे निकल गए हैं, जबकि कुछ देशों के पास अपने स्वास्थ्यकर्मियों, बुजुर्गों और अन्य खतरे वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों में एक फीसद लोगों को भी टीका नहीं लग पाया है, जबकि कुछ देशों में 60 फीसद का टीकाकरण हो चुका है।

कोरोना उत्पत्ति की जांच के लिए चीन पर बढ़ रहा दबाव

- वायरस के कथित लैब लीक का मामला पकड़ रहा है जोर
- वायरस उत्पत्ति के प्रारंभिक डाटा हटाए जाने के लग रहे हैं आरोप

बीजिंग, एएनआइ : चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरा होने पर बेशक समारोह किया जा रहा है, लेकिन महामारी के बीच कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच को लेकर वह फिर घिरता जा रहा है। दुनियाभर के देशों का जांच को पूरा करने को लेकर चीन पर दिनों-दिन दबाव बढ़ रहा है।

कोरोना वायरस के कथित लैब लीक का मामला अब जोर पकड़ रहा है। यह मामला पूरी दुनिया में बहस का विषय बन गया है और चीन की विश्वभर में आलोचना हो रही है। विश्व के तमाम विज्ञानी यह मांग उठा चुके हैं कि वायरस उत्पत्ति की पूरी जांच किया जाना जरूरी है।

एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की जांच के दौरान चीन ने कोरोना वायरस उत्पत्ति के प्रारंभिक डाटा को हटा दिया था।

बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी की शुरूआत में कोरोना वायरस टेस्ट के अंतरराष्ट्रीय डाटा बेस को इंटरनेट से भी हटा दिया गया है।

वाल स्ट्रीट जनरल ने जांच में पाया कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने पर जांच को महीनों तक लंबित करने के लिए वीटो का भी इस्तेमाल किया। इस समय को उसने प्रारंभिक डाटा को हटाने में लगाया। यही कारण है कि डब्ल्यूएचओ की लैब से वायरस लीक होने की जांच ठीक से नहीं हो सकी।

अमेरिका से भारतीय प्रवासियों ने भेजे चिकित्सकीय उपकरण

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका से वैश्विक महामारी कोविड-19 से भारत में मुकाबले के लिए अहम चिकित्सकीय उपकरणों समेत वेंटिलेटर, पल्स आक्सीमीटर आदि भारत तक जहाज से भेजे गए हैं।

अमेरिकी राज्य न्यूजर्सी, न्यूयार्क और कनेक्टिकट में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की ओर से न्यूजर्सी के केसबी से मुंबई और दिल्ली भेजे गए हैं। जहाज के जरिये 300 वेंटिलेटर, तीन हजार वेंटिलेटर सर्किट, फिल्टर, फ्लो सेंसर, 100 पोर्टेबल वेंटिलेटर और 310,176 पल्स आक्सीमीटर भेजे गए हैं। न्यूयार्क में भारत के डिप्टी कांसुल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा ने तीनों अमेरिकी राज्यों के प्रवासी भारतीयों के संघ की सराहना करते हुए कहा कि वह लोग जहाज से चिकित्सकीय सामग्री भेजने की बेहद अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं।

न्यूज गैलरी

कतर और भारत के बीच एयर बब्बल समझौता 31 तक बढ़ा

दोहा : कतर और भारत के बीच एयर बब्बल समझौता 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कतर में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की गई घोषणा में कहा गया है कि इस समझौते के तहत उड़ानों को बहाल कर दिया गया है। दूतावास ने ट्वीट किया, 'भारत और कतर के बीच एयर बब्बल समझौता जुलाई 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के तहत उड़ानें बहाल हो गई हैं। दोनों तरफ के नागरिक उड्डयन अधिकारियों और एयरलाइंस को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने में अपना सहयोग जारी रखने के लिए धन्यवाद।' समझौता 30 जून को समाप्त हो गया था। भारत ने कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी और एयर बब्बल समझौते के तहत विभिन्न देशों के बीच विमानों का संचालन शुरू किया। इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निर्धारित अंतराष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। महानिदेशालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कामर्शियल यात्री विमानों पर 30 जून को समाप्त हो गया प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेगा। (एएनआइ)

पाक ने भारत से लगी सीमा पर चीनी टैंक वीटी-4 तैनात किए

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सेना ने भारत से लगी सीमा पर चीन के बने वीटी-4 युद्धक टैंकों की पहली खेप को तैनात कर दिया है। चीन के सरकारी हथियार निर्माता नोरिंको ने पिछले साल अप्रैल में ही पाकिस्तान को वीटी-4 टैंकों की आपूर्ति शुरू कर दी थी। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान तीसरा ऐसा देश है, जिसने चीन से इन टैंकों की खरीद की है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पिछले साल ही वीटी-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दी है। चीन में बने वीटी-4 टैंक को थर्ड जेनेरेशन टैंक माना जाता है। दरअसल चीन, पाकिस्तान के 350 टैंकों को बेहतर करने के लिए वीटी-4 टैंक की टेक्नोलाजी बेच रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन महमूद ने कहा कि बुधवार को हथियारबंद डिविजन के तहत वीटी-4 टैंकों की पहली खेंप चीन ने पाकिस्तान को सौंप दी है। (प्रेट्र)

दो महीने बाद नेपाल की घरेलू उड़ानें शुरू

काठमांडू : नेपाल में दो महीने के अंतराल के बाद 50 फीसद यात्रियों के ही बैठने की क्षमता के साथ घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इसके चलते ही गुरुवार से काठमांडू स्थित घरेलू हवाई अड्डे की इमारत में चहल-पहल बढ़ गई है। ध्यान रहे कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के बेतहाशा बढ़ने के बाद नेपाल सरकार ने विगत तीन मई से नियमित घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी थी। अब नए आदेश के तहत संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक जुलाई से नेपाल भर में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि नियमित रूप से चलने वाली 64 घरेलू उड़ानों को फिर से बहाल कर दिया गया है। (एएनआइ)

ईरान में कट्टरपंथी मौलवी न्यायपालिका प्रमुख नियुक्त

दुबई : ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने एक कट्टरपंथी मौलवी गुलामहुसैन मोहसेनी एजेही को देश का नया न्यायपालिका प्रमुख नियुक्त किया है। वह राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रैसी की जगह लेंगे। 64 वर्षीय एजेही देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का शीर्ष असैनिक पद संभालेंगे। ईरान में सभी सरकारी मामलों में अंतिम स्वीकृति देने वाले आयतुल्ला अली खामनेई ने गुरुवार को एजेही की नियुक्ति की घोषणा की। सुप्रीम लीडर ने उनसे न्याय का पक्ष लेने और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का अनुरोध किया। उन्होंने एजेही के अनुभव, स्वच्छ रिकार्ड और वैधानिक रूप से सक्षम होने की सराहना की है। एजेही एक ऐसी न्यायपालिका का प्रभार संभालेंगे जिसकी अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूह व्यापक रूप से आलोचना करते रहे हैं। (एपी)

चिनफिंग ने दी दुनिया को धमकी, विरोधियों का कुचल देंगे सिर

आक्रामक तेवर ▸ कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरा होने पर चीनी राष्ट्रपति का संबोधन

कहा– ताइवान को हासिल करना हमारा ऐतिहासिक मिशन

बीजिंग, प्रेट्र : चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पार्टी के सौ साल पूरे होने के मौके पर पूरी दुनिया को धमकाया है। उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम विरोधियों को नेस्तनाबूद कर कर देंगे, उनका सिर कुचल दिया जाएगा।

थ्येनआनमन चौक से भाषण में शी चिनफिंग ने अपने इरादों को भी साफ कर दिया। चीन के सैन्य और राजनीतिक एजेंडे में ताइवान और वे सभी द्वीप हैं, जिन पर वह अपना कब्जा करना चाहता है।

चिनफिंग ने कहा कि ताइवान को मुख्यभूमि से जोड़ना हमारा ऐतिहासिक मिशन है। हमें ताइवान के स्वतंत्रता के प्रयास को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चीन का एकीकरण करना ही हमारा मुख्य मकसद है।

चिनफिंग अपनी ताकत को लेकर भी बड़बोलेपन से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कोई भी देश हमें धमकाने, उत्पीड़ित करने या अधीन करने की कोशिश न करे। ऐसे देशों को चीन की मजबूत सेना और यहां की एक अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी की एक फौलादी दीवार से सामना करना होगा।

विरोधी देश भाषण न दें : चीन ने उइगर मुस्लिमों के 'नरसंहार' मामले पर अमेरिका के लगातार आक्रामक होने और हांगकांग में चीनी कानूनों का विरोध करने पर कहा कि हम उपयोगी सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन भाषण नहीं सुनेंगे।

दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक सेना बनाने का सपना : चिनफिंग ने कहा कि हमें अपनी सेना को सबसे अत्याधुनिक बनाना है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हों।

रायटर के अनुसार चिनफिंग ने कहा कि चीन के लोग पुरानी दुनिया को खत्म करना जानते हैं तो नई दुनिया बनाने का भी उनमें दम है।

थ्येनआनमन चौक से एक घंटे का संबोधन : थ्येनआनमन चौक पर एक घंटे के संबोधन के दौरान स्कूली बच्चों सहित 70 हजार से ज्यादा लोग उपस्थित थे। एक जुलाई 1921 को माओत्से तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) की स्थापना की थी। यह आयोजन सौ साल पूरा होने पर किया गया था। गुरुवार के कार्यक्रम की शुरुआत फाइटर जेट विमानों के प्रदर्शन से हुई।

हांगकांग में कड़ी सुरक्षा, विक्टोरिया पार्क हुआ बंद : चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरे होने पर हांगकांग में तनाव की स्थिति बनी रही। आंदोलनकारियों के भय से यहां पूरे हांगकांग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूर्व में आंदोलन का स्थल रहे विक्टोरिया पार्क को सील कर दिया गया था।



बीजिंग में गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरे होने पर आयोजित समारोह के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग। साथ में हैं प्रधानमंत्री ली क्वांग(एकदम बाएं)। रायटर

ईरान अब संरा के निरीक्षकों को नहीं जाने दे रहा नातांज

▸ नातांज है मुख्य परमाणु शोधन संयंत्र, अप्रैल में हो चुका है वहां पर हमला



नतांज स्थित परमाणु संयंत्र की फाइल फोटो।

पेरिस, रायटर : ईरान ने अपने मुख्य यूरेनियम शोधन केंद्र नातांज में संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों के जाने पर रोक लगा दी है। कहा है कि यह कदम उसने संयंत्र की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया था। नातांज शोधन केंद्र में अप्रैल में विस्फोट हुआ था और वहां की बिजली गुल हो गई थी। ईरान ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। अपने परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के कैमरों से निगरानी ईरान पहले ही रोक चुका है। इस सबके चलते उसके और पश्चिमी देशों के संबंध बिगड़ने तय माने जा रहे हैं।

2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद से ईरान अपनी क्षमताएं बढ़ाने में लगा है। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वह यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ा रहा है और उसे परमाणु हथियार बनाने लायक शोधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अभी परमाणु हथियार बनाने से दूर है। इसी वजह से यूरोपीय देश-ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के साथ जुड़े हुए हैं और जो बाइडन के नेतृत्व वाला अमेरिका भी परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने की राह पर है। लेकिन ईरान अब शर्तें खड़ी करके समय ले रहा है। ताजा शर्त पहले अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने और उसके बाद परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वार्ता करने की है। इसके चलते अप्रैल से विएना में ईरान और छह शक्तिशाली देशों के बीच चल रही वार्ता में गतिरोध पैदा होने के आसार हैं।

ताजा घटनाक्रम में ईरान ने जिस तरह से आइएईए के निरीक्षण दल को नातांज जाने से रोका है, उससे उसके और पश्चिमी देशों के बीच खटास पैदा हो सकती है। ईरान ने 2019 में आइएईए की एक निरीक्षक को हवाई अड्डे पर रोक दिया था और उसके यात्रा दस्तावेज भी जब्त कर लिए थे। ईरान को उसके नातांज जाने पर आपत्ति थी। ईरान ने परमाणु समझौते से परे हटकर यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ाए जाने की घोषणा की है। जाहिर है कि उसकी घोषणा का क्रियान्वयन नातांज में हो रहा है। इसलिए वह वहां पर आइएईए का निरीक्षण या निगरानी नहीं चाहता है। वह बातचीत और शर्तों पर चर्चा में समय गुजारना चाहता है। उसका यह रुख बरकरार रहा तो कुछ हफ्तों में उसके पश्चिमी देशों से संबंध बिगड़ सकते हैं।

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए वर्क वीजा पाने की खुली नई राह

▸ पढ़ाई के बाद इस वीजा के आधार पर नौकरी पाने के लिए यहां रुक सकेंगे

लंदन, एएनआइ : ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय समेत विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीजा पाने के लिए नई राह खुल गई है। गृह विभाग ने गुरुवार को इन छात्रों के लिए औपचारिक तौर पर नया पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा शुरू किया। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत और अन्य देशों के छात्र इस वीजा के आधार पर नौकरी पाने के लिए इस देश में रुक सकेंगे।

ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने गत वर्ष इस वीजा कार्यक्रम का एलान किया था। अब इसे लागू किया गया है। इस नए वर्क वीजा से भारतीय छात्रों को ज्यादा लाभ होने की संभावना है। क्योंकि वे काम के अनुभव की संभावना के आधार पर डिग्री कोर्सों का चयन करते हैं। यह नया वर्क वीजा कार्यक्रम ग्रेजुएट छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जो मान्यता प्राप्त ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करते हैं। वे इस वीजा के आधार पर ब्रिटेन में दो साल रहकर नौकरी की तलाश कर सकेंगे। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ने एक बयान में कहा, 'ब्रिटिश सरकार के अंक आधारित इमीग्रेशन सिस्टम के तहत भारत और दुनियाभर के प्रतिभावान छात्रों के लिए ब्रिटेन में अब कारोबार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे क्षेत्रों में सर्वोच्च स्तर पर अपने करियर की शुरुआत करने का अवसर है।' उन्होंने बताया, 'इससे उन छात्रों को मदद मिलेगी, जो ब्रिटेन में रहने और काम करने के इच्छुक हैं।'

56 हजार भारतीयों को मिला वीजा

ब्रिटेन में गत वर्ष 56 हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों को स्टूडेंट वीजा जारी किया गया। यह आंकड़ा इससे पहले वाले साल के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा था। जबकि ब्रिटेन ने गत वर्ष कुल जितने स्टूडेंट वीजा जारी किए, उनमें से करीब एक तिहाई भारतीयों के हिस्से में आए।

खालिदा को विदेश जाने के लिए अपराधों की माफी मांगनी होगी : कानून मंत्री

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि खालिदा जिया अगर अपने इलाज के लिए विदेश जाना चाहती हैं तो उन्हें अपने अपराधों को कुबूल करना होगा और राष्ट्रपति से उसके लिए माफी मांगनी होगी। उन्होंने ऐसा विपक्षी दल के नेता के उन्हें राजनीतिक कारणों से देश के बाहर इलाज कराने से रोके जाने का आरोप लगाने के बाद कहा है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने पिछले हफ्ते सरकार से मांग की थी कि पार्टी अध्यक्ष खालिदा जिया (76 वर्ष) को इलाज के लिए तत्काल विदेश जाने की इजाजत दी जाए।

डेली स्टार बांग्लादेश अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अनीसुल हक ने बांग्लादेश की संसद में कहा कि खालिदा जिया को अगर इलाज के लिए विदेश जाना है तो उन्हें अपने सारे अपराध स्वीकार करने होंगे और राष्ट्रपति शेख हसीना से माफी मांगनी होगी। पिछले हफ्ते बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा था कि लिवर और अन्य तकलीफों के इलाज के लिए उन्हें विदेश ले जाने की जरूरत है।

जानलेवा लू से कनाडा में हाहाकार, ब्रिटिश कोलंबिया में मरे 486 लोग

- अमेरिका भी रहा झुलस, सिएटल में 48 डिग्री पहुंचा तापमान
- अमेरिका में भी 121 से ज्यादा लोगों की मौत

वैंकूवर, रायटर : कनाडा और अमेरिका में लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 486 लोगों की मौत हो गई है। अन्य शहरों में भी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में पारा तेजी से ऊपर आ रहा है। यहां 121 से ज्यादा लोग गर्मी से मारे गए।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में इस बार गर्मी से लोगों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। यहां गर्मी के सभी रिकार्ड टूट रहे हैं। यहां के लिटन शहर में पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अब तक सैकड़ों लोगों के मरने के बाद भी लगातार गर्मी से मरने वालों के बारे में जानकारी मिल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बढ़ती गर्मी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक स्थिति है।

वाशिंगटन राज्य में गर्मी से हालत खराब होने के कारण लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। यहां के सिएटल में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ओरेगन के गवर्नर केटे ब्राउन ने जंगलों में आग को लेकर आपात स्थिति का एलान किया है। पोर्टलैंड के अग्निशमन विभाग ने चार जुलाई को स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। एपी के अनुसार ओरेगन में 63 लोगों की मौत हो गई। पोर्टलैंड में भी गर्मी से 45 लोगों ने जान गंवा दी। वाशिंगटन में बीस लोगों के गर्मी से मरने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। यह संख्या बढ़ सकती है। पोर्टलैंड में 2017 से 2019 में गर्मी से मरने वालों की संख्या सिर्फ 12 थी। सिएटल में भी गर्मी से 13 लोगों की मौत हो गई।

वहीं, न्यूयार्क के मेयर बिल डी ब्लेसिओ ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि लोग अपने घरों से न निकलें। अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। न्यूयार्क शहर के सामाजिक सेवा विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस ने गर्मी से बचने के लिए गाइड लाइन जारी की है।

परमाणु सौदे के प्रमाणीकरण में सहयोग करे ईरान : भारत

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम के आधार पर जांच-पड़ताल आदि की गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) से सहयोग जारी रखने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ईरान के परमाणु मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में 2231 प्रस्ताव (2015) पर कहा कि ज्वाइंट कांप्रिहेंसिव प्लान आफ एक्शन (जेसीपीओए) और 2231 प्रस्ताव का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। साथ ही इस प्लान को लागू करने पर भी सहमत है।

आमतौर पर ईरान परमाणु संधि (जेसीपीओए) के तौर पर पहचाने जाने वाले समझौते को वियना में 14 जुलाई, 2015 में ईरान और यूरोपीय संघ समेत पी5प्लस देशों (चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी) के बीच हुआ था। मई 2018 में अमेरिका के इस समझौते से हाथ खींचने के बाद इस सौदे के भविष्य पर सवाल उठ खड़े हुए थे।

अब्दुल्ला ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में अफगानिस्तान का अस्तित्व खतरे में

- विदेशी सेनाओं की वापसी से रिक्तता की स्थिति
- हवाई हमले में 53 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मौजूदा परिस्थितियों को देखकर कहा है कि देश की एकता और अस्तित्व दोनों ही खतरे में है।

अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने यह गंभीर बात राष्ट्रपति पैलेस में शीर्ष नेताओं की एक बैठक में कही। इस बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी व अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में चारों तरफ गंभीर खतरे हैं, ऐसी स्थिति में हमें शांति चाहिए। विदेशी सेनाओं की वापसी से रिक्तता की स्थिति बन रही है।

उन्होंने कहा कि तालिबान अब वार्ता धीमी और युद्ध की गति तेज किए हुए है। हालांकि दोनों के ही प्रतिनिधि दोहा में हैं, फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है। तालिबान वार्ता के नाम पर समय नष्ट कर रहे हैं।

इधर अफगान सेना के हवाई हमलों में 33 आतंकवादियों की मौत हो गई। ये हवाई हमले बाल्ख प्रांत के कालदर और शोर टप्पेह में हुए। इन हमलों में 21 तालिबानी घायल हुए हैं। सभी तालिबानी आतंकी एक स्थान पर एकत्रित थे। अफगान सेना ने घुरियान में तालिबान के एक हमले को नाकाम कर दिया। इस संघर्ष में बीस आतंकी मारे गए।

इटली की सेना ने हेरात सैन्य अड्डा और एयरपोर्ट सौंपे

नाटो सेना में शामिल इटली की सेना ने भी पूरी तरह से वापसी कर दी है। इटली की सेना के जिम्मे पिछले बीस साल से हेरात का सैन्य अड्डा और एयरपोर्ट थे। ये उसने अफगानिस्तान की सेना को सौंप दिए।

पाक किसी भी युद्ध में अमेरिका का सहयोगी नहीं बनेगा : इमरान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के संदर्भ में कहा कि वह अब अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध में सहयोगी नहीं बनेगा। अफगानिस्तान के मामले में पाक को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ शांति में साझेदार बनेंगे, लड़ाई में नहीं। आइएएनएस के अनुसार इमरान ने नेशनल असेंबली में कहा कि वह अफगान सरकार के नेतृत्व में शांति वार्ता का पूरा सम्मान करेगा।

पाक में इमरान सरकार ने लोगों का जीवन नरक बनाया : बिलावल

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार ने नया पाकिस्तान के नाम पर लोगों का जीवन नरक बना दिया है।

पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार नेशनल असेंबली में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री इमरान के बजट भाषण के बाद बिलावल ने कहा कि पीएम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे गरीबों के बजाय अमीरों को फायदा हुआ है। बिलावल ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री के भाषण को सुनना नहीं चाहती। उन्होंने इमरान खान से पिछले तीन वर्षों के कामकाज का हिसाब मांगते हुए कहा कि गरीबी और बेरोजगारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

टैक्स चोरी में फंसी ट्रंप की कंपनी, सीएफओ ने किया सरेंडर

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▸ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी की चल रही थी जांच, मैनहटन की अदालत में चलेगा मुकदमा

न्यूयार्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारिवारिक व्यवसाय और उनका ट्रंप आर्गनाइजेशन टैक्स चोरी की जांच में फंस गए हैं। मैनहटन की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी ट्रंप आर्गनाइजेशन और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) एलन वीसेलबर्ग को आरोपित किया है। वीसेलबर्ग ने डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के आफिस में गुरुवार को सरेंडर कर दिया। उन्हें मैनहटन की अदालत में पेश किया जाएगा। सरेंडर के समय उनके वकील साथ में थे। डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने दो साल तक जांच करने के बाद पहला आपराधिक मामला दर्ज किया है।

अब इस मामले में नए तथ्य सामने आ सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत बढ़ाने वाले हो सकते हैं। गुरुवार को हुए इस घटनाक्रम की ट्रंप को भी उम्मीद नहीं थी। इससे उनकी कंपनी पर आर्थिक रूप से भी असर पड़ सकता है। उनकी कंपनी के साझेदारों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

ट्रंप आर्गनाइजेशन और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग के खिलाफ विशेषतौर पर क्या आरोप लगाए गए हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ज्ञात हो कि मैनहटन डिस्ट्रिक्ट अटार्नी साइरस वेंस पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के पूरे कारोबार की टैक्स चोरी के संबंध में न्यूयार्क की अटार्नी जनरल लेटिटिआ जेम्स के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं।

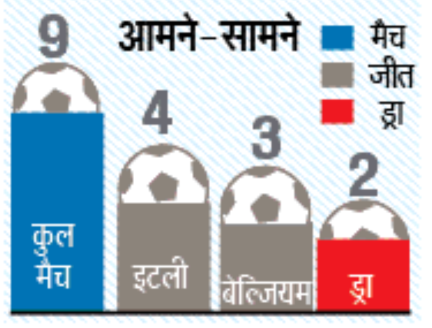
रायटर के अनुसार ट्रंप आर्गनाइजेशन ने एक बयान में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अटार्नी साइरस वेंस मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रंप परिवार के कारोबार को पिछले 48 साल से देख रहे हैं। यह न्याय नहीं राजनीति है।

मजबूत इटली के सामने होगा चोटिल बेल्जियम

दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला ब्रून और हैजार्ड का खेलना मुश्किल

म्यूनिख, एपी : अपने पहले यूरो कप खिताब की तलाश में जुटी बेल्जियम की टीम शुक्रवार देर रात को इटली के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसके लिए यह मैच आसान नहीं रहने वाला है। इटली की टीम 1968 के बाद इस खिताब को जीतने के लिए बेताब है और इस सत्र में उसने दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। वहीं, बेल्जियम की टीम इटली को रोकने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन, यह काफी मुश्किल होने वाला है।

बेल्जियम की टीम के दो अहम खिलाड़ी प्री-क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल के खिलाफ चोटिल हो गए थे और उनका इस मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। उनके नहीं होने से बेल्जियम का अटैक कमजोर हो गया है। बेल्जियम की टीम इस मैच में मिडफील्डर केविन डि ब्रून और नियमित कप्तान स्ट्राइकर ईडन हैजार्ड के बिना उतर सकती है। उन पर अंतिम फैसला मैच के शुरू होने से पहले लिया जाएगा। दोनों ही खिलाड़ी पिछले मैच में चोटिल हो गए थे। कोच रोबर्ट मार्टिनेज की टीम बेल्जियम का प्रदर्शन वैसे तो इस सत्र में और टूर्नामेंट में अच्छा रहा है। लेकिन, पुर्तगाल के खिलाफ सिर्फ एक गोल होने से मार्टिनेज के अटैकिंग रणनीति पर सवाल उठने लगे थे कि उनकी खराब रणनीति के कारण ही टीम अधिक गोल नहीं कर पाई। अब ब्रून और ईडन नहीं खेलते हैं तो उनका अटैक और भी कमजोर पड़ जाएगा और गोल करने का अधिक दबाव रोमेलु लुकाकू पर आ जाएगा। विपक्षी टीमें लुकाकू को गोल करने से रोकती हैं। बेल्जियम के खिलाड़ियों को इटली के डिफेंस को भेदना आसान नहीं होगा। इटली की लीग सीरी-ए में इंटर मिलान के लिए खेलने वाले लुकाकू ने बेल्जियम को यहां तक टीम की चार जीत में तीन गोल दागे हैं। वहीं, इटली को अपने डिफेंडर और कप्तान जार्जियो चिएलिनी की भी कमी खल सकती है जो चोट से परेशान हैं लेकिन उनके खिलाड़ी फार्म में हैं। काइरो इमोबाइल और मैनुअल लोकेटली ने टीम को यहां तक पहुंचाने में अपना-अपना योगदान दिया है और इटली के प्रशसंकों को कोच राबर्टो मानसिनी की टीम से अच्छे प्रदर्शन की आस रहेगी।



आज के मैच

स्विट्जरलैंड vs स्पेन
रात 9:30 बजे | स्थान : सेंट पीटर्सबर्ग

बेल्जियम vs इटली
रात 00:30 बजे | स्थान : म्यूनिख

सोनी नेटवर्क



अभ्यास के दौरान दौड़ लगाते बेल्जियम टीम के खिलाड़ी • एएफपी

> सिर्फ एक पल मैच हमारे पक्ष और खिलाफ कर सकता है। हमें पहले मिनट से लेकर सीटी बजने तक मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है।
> **योरी टीलमांस,** मिडफील्डर, बेल्जियम

> 31 मैचों से नहीं हारने के बाद इटली को शिकस्त देना हमारे लिए कड़ी चुनौती है।
> **थार्गन हैजार्ड,** मिडफील्डर, बेल्जियम

> हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि केविन डि ब्रून मैच में खेलेगा। वह ऐसा खिलाड़ी है जो मैच में अंतर पैदा कर सकता है।
> **जार्जिंहो,** मिडफील्डर, इटली

7 पिछले मैचों में थार्गन हैजार्ड ने बेल्जियम के लिए चार गोल दागे हैं जबकि दो गोल उन्होंने करने में मदद की है

2 गोल और एक में मदद काइरो इमोबाइल इटली के लिए यूरो के इस सत्र में किए हैं

3 पिछले क्वार्टर फाइनल में इटली का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट में निकला है जिसमें उसे एक जीत और दो हार मिली हैं

31 पिछले मैचों से इटली की टीम को शिकस्त नहीं मिली है

13 पिछले मैचों से बेल्जियम की टीम भी नहीं हारी है

उलटफेर से बचना चाहेगी स्पेनिश टीम

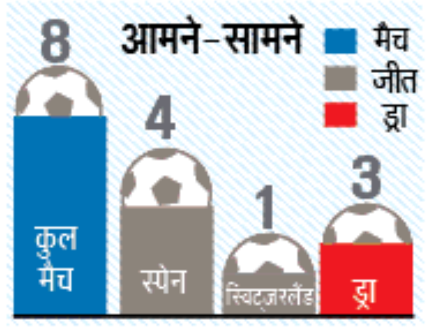
पहले क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगी भिड़ंत

सेंट पीटर्सबर्ग, एपी : विश्व चैंपियन फ्रांस को प्री-क्वार्टर फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में हराने वाली स्विट्जरलैंड शुक्रवार को यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन को भी आसानी से जीतने नहीं देगी। दोनों टीमें यूरो कप में पहली बार आमने-सामने हो रही हैं। स्विट्जरलैंड उलटफेर के लिए जानी जाती है। इस टीम ने फ्रांस के खिलाफ जीत हासिल करके सभी को दिखा भी दिया था।

स्विट्जरलैंड स्पेन को इससे पहले एक बार हरा भी चुकी है। 2010 विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने स्पेन को 1-0 से हराकर चौंका दिया था। फ्रांस के खिलाफ स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और निर्धारित समय में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया था और फिर अतिरिक्त समय में अगर स्विट्जरलैंड गोल नहीं कर पाया तो उसने सितारों से सजी फ्रांस को भी अपने डिफेंस को भेदने नहीं दिया। फिर पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की थी। यह टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल खेल रही है। वहीं, स्पेन को स्विट्जरलैंड को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों में अच्छा करना होगा। एक गलती उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। स्पेन को सेंट्रल मिडफील्डर 18 वर्षीय पेड्री से अच्छे प्रदर्शन की आस रहेगी जो टीम के लिए गोल करने के मौके बनाते हैं। वह अपने करियर का पहला कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने क्रोएशिया को अतिरिक्त समय में हराया था।



सेंट पीटर्सबर्ग में अभ्यास करते स्विट्जरलैंड टीम के खिलाड़ी • एपी



12 पिछले मैचों में स्पेनिश टीम को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। इस दौरान स्पेन ने छह मुकाबले जीते और इतने ही ड्रा खेले हैं

1 मैच यूरो कप के इस सत्र में ग्रुप स्तर में स्विट्जरलैंड जीत पाई थी। इसके अलावा स्विस टीम ने एक मैच ड्रा खेला तो एक में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा

3 पिछले मैचों में स्विट्जरलैंड और स्पेन ने शुरुआती 30 मिनट के अंदर अपनी-अपनी तरफ से गोल दागे हैं

चिली के खिलाफ नेमार की टीम में वापसी

रियो डि जेनेरियो, एपी : गत विजेता ब्राजील और चिली के स्टार खिलाड़ियों ने शुक्रवार को कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल मैच के लिए अपनी-अपनी टीमों में वापसी की है। पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलने वाले नेमार ब्राजील की टीम में वापस आ गए हैं जबकि पिंडली की चोट से ठीक होने के बाद एलेक्सिस सांचेज ने चिली की टीम में वापसी की है।

पिछले ग्रुप मैच में इक्वाडोर के खिलाफ 1-1 से ड्रा मैच में ब्राजील के नेमार, डिफेंडर थियागो सिल्वा और स्ट्राइकर गेब्रियल जीसस को आराम दिया गया था जबकि केसेमिरो उस मैच में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर खेले थे। ब्राजील ने अभी तक टूर्नामेंट में चार में से तीन में जीत दर्ज की है और वह खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है। वहीं, चिली ग्रुप स्तर में सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर पाया था और वह बोलविया के खिलाफ थी। सांचेज ग्रुप स्तर के मैचों में चिली के लिए नहीं खेल पाए थे और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था। चिली के कोच मार्टिन लासर्ते ने गुरुवार को टीम के अभ्यास सत्र के बाद 32 वर्षीय सांचेज को टीम में शामिल करने का फैसला किया। दिन का अन्य क्वार्टर फाइनल मैच पेरू और पराग्वे के बीच जिओनिया में होगा।

आज के मैच

पेरू vs पराग्वे
2:30 बजे | स्थान : जिओनिया

ब्राजील vs चिली
5:30 बजे | रियो डि जेनेरियो

सोनी नेटवर्क



नेमार • फाइल फोटो, एएफपी

आस्कर-विजय से मरे ने जीवित रखा सपना

लंदन, एपी : विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर दूसरे दौर के मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे पहला सेट जीतने के बाद दो सेट से पिछड़ गए थे। वहां मौजूद घरेलू दर्शक सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे वह था फाइट मरे फाइट... इसके बाद मरे ने जोरदार वापसी की व जर्मनी के खिलाड़ी आस्कर ओटे के खिलाफ जीत हासिल की। जिसे सब आस्कर-विजय भी कह रहे हैं। मरे ने दो सेट से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 से मैच जीतकर तीसरी बार विंबलडन खिताब अपने नाम करने का सपना बरकरार रखा। इस जीत के बाद मरे ने अपनी टी-शर्ट उतारकर एक प्रशंसक को तोहफे के रूप में भेंट की। पहले दौर में भी चार सेट तक के मुकाबले में अंतिम दो सेट लगातार जीतकर मरे कभी हार नहीं मानने का नमूना पेश कर चुके थे। इसके बाद दूसरे दौर में भी उन्होंने इसी अंदाज में खेला। पहला सेट आसानी से 6-3 से जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि मरे इस मैच को सीधे तीन सेटों में जीत लेंगे लेकिन, 151वें नंबर के खिलाड़ी आस्कर ने शानदार वापसी की और मरे को लगातार दो सेट 6-3, 6-3 से हराकर उनके ही घर में खेले जाने वाले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में बैकफुट पर ढकेल दिया। अंतिम सेट के समय रोशनी कम होने के कारण कोर्ट की छत बंद कर दी गई और दूधिया रोशनी में मैच खेला जाने लगा। दर्शकों ने फाइट मरे (मरे लड़ो) चिल्ला चिल्लाकर अपने लोकल हीरो के अंदर जोश भरना शुरू किया, जिससे प्रेरित होकर मरे ने एक बार फिर आगे आकर खेलना शुरू किया। इस मैच को जीतने के बाद वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसे की उनके चेहते अभिनेता या अभिनेत्री के आस्कर जीतने पर दर्शकों के अंदर जोश व उत्साह देखने को मिलता है।

स्वितोलिना हुई उलटफेर का शिकार : महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना उलटफेर का शिकार हो गईं जिन्हें दूसरे दौर में पोलैंड की मागडा लिनेटे ने 6-3, 6-4 से हराया। एश्ले बार्टी ने 6-4, 6-3 से एना ब्लिंकोवा को हराया।

सानिया-बेथानी की जोड़ी दूसरे दौर में : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा व अमेरिका की जोड़ीदार बेथानी माटेक सैंड्स ने डेसिरे व एलेक्सा की जोड़ी 7-5, 6-3 से हराया।

जीत से चमके रोजर फेडरर, तीसरे दौर में

लंदन, रायटर : पहले दौर में संघर्ष करने के बाद सुनहरी खिली धूप के नीचे दूसरे दौर के मैच में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर शानदार लय में दिखाई दिए। जिसके चलते उन्होंने जर्मनी के रिचर्ड गास्केट को सीधे सेटों में 7-6, 6-1, 6-4 से एकतरफा अंदाज में हराया। पहले सेट को भले ही गास्केट टाई ब्रेकर तक ले जाने में सफल रहे लेकिन उसमें भी हार मिली। इसके बाद फेडरर ने गास्केट को वापसी का मौका ही नहीं दिया और मैच में जीत हासिल कर सुनहरी धूप में चमकते नजर आए।

मरे ने जर्मनी के आस्कर ओटे को पांच सेटों तक चले कड़े मुकाबले में पराजित किया



मैच जीतने के बाद खुश एंडी मरे • एएफपी

खेल डायरी

भारतीय महिला टीम ने गंवाई सीरीज

टांटन, प्रेट्र : कप्तान मिताली राज की अर्धशतकीय पारी केट क्रास की शानदार गेंदबाजी और सोफी डंकली के जुझारू अर्धशतक के सामने फीकी पड़ गई जिससे इंग्लैंड ने बुधवार को यहां दूसरे महिला वनडे डे-नाइट मैच में भारत को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। मिताली ने रन आउट होने से पहले सात चौकों की मदद से 59 रन बनाए लेकिन, बाकी भारतीय बल्लेबाज मध्यम गति की गेंदबाज क्रास (5/34) और बायें हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (3/33) के सामने नहीं टिक पाई और पूरी टीम 50 ओवर में 221 रन पर आउट हो गई। शेफाली वर्मा ने 55 गेंदों पर 44 रन का योगदान दिया। आसान लक्ष्य के सामने इंग्लैंड भी शुरू में लड़खड़ा गया और 28.5 ओवर के बाद उसका स्कोर पांच विकेट पर 133 रन था। डंकली (नाबाद 73) और कैथरीन ब्रंट (नाबाद 33) ने यहीं से छठे विकेट के लिए 92 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड ने 47.3 ओवर में पांच विकेट पर 225 रन बनाए।

टूर डि फ्रांस ने केस लिया वापस

नई दिल्ली, जेएनएन : फ्रांस की लोकप्रिय साइकिल रेस टूर डि फ्रांस की बोर्ड इकाई ने शनिवार को उस महिला प्रशंसक को चेतावनी देते हुए अपना केस वापस ले लिया जिसकी वजह से 26 जून को हुई रेस में एक बड़ा हादसा हुआ था।

दरअसल यह महिला प्रशंसक ट्रैक पर साइन बोर्ड लेकर खड़ी थी। उसने पीछे आते रेसरों को देखा ही नहीं। इससे एक रेसर उनके बोर्ड से टकराया और करीब 20 राइडर्स अपना संतुलन खो बैठे। इसके बाद महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर टूर डि फ्रांस ने केस भी कर दिया था।

इस केस को वापस लेते हुए टूर डि फ्रांस के निदेशक क्रिश्चियन ने कहा, 'हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। इस कहानी ने ज्यादा ही तूल पकड़ लिया था। आपको राइडर्स का सम्मान करना चाहिए।'

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम का क्वारंटाइन खत्म



श्रीलंका के कोलंबो के एक होटल में गुरुवार को क्वारटाइन पूरा करने के बाद एक साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी • बीसीसीआइ

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन : सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की अगुआई में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम का गुरुवार को तीन का अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया। सभी खिलाड़ी एक साथ स्वीमिंग पूल में मस्ती करते हुए दिखाई दिए। बीसीसीआइ ने गुरुवार को एक फोटो ट्वीट की जिसमें सभी खिलाड़ी स्वीमिंग पूल में हैं।

इस दौरे पर दोनों टीमों को तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है और सभी मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। अब भारतीय खिलाड़ी आपस में टीमें बनाकर अभ्यास मैच खेलेंगे। पहला वनडे वनडे 13 जुलाई को जबकि सीरीज का दूसरा मैच 6 जुलाई को खेला जाएगा। वनडे सीरीज का अंतिम मैच 18 जुलाई को होगा। टी-20 सीरीज की शुरुआत 21 जुलाई से होगी। इस सीरीज का दूसरा मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा जबकि सीरीज और दौरे का आखिरी मैच 25 जुलाई को होगा।

भारत के खिलाफ मजबूत टीम के साथ उतरेंगे : रूट

लंदन, प्रेट्र : इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने कहा है कि रोटेशन नीति को छोड़ने का समय आ गया है जिससे कि भारत के खिलाफ और फिर एशेज में सबसे मजबूत संभावित टीम उतारी जा सके और वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) खिताबी मुकाबले को टेलीविजन पर देखने के बजाय इसके लिए चुनौती पेश कर सकें। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की रोटेशन नीति उस समय विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गई थी जब इस साल की शुरुआत में वे अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ भारत दौरे पर नहीं गए थे और सीरीज 1-3 से गंवाने के कारण डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। डब्ल्यूटीसी के नए चक्र की शुरुआत भारत और इंग्लैंड के बीच चार अगस्त से शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ होगी। रूट ने कहा, 'आराम और रोटेशन की नीति को पीछे छोड़ना होगा। अगर सभी फिट हुए तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम उतारेंगे। यह काफी रोमांचक होगा और मैं इसे लेकर उत्सुक हूं।' बेयरस्टो और वुड भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट में नहीं खेले थे लेकिन, चौथे टेस्ट में उतरे थे। टीम की पहली पसंद के विकेटकीपर जोस बटलर सीरीज के पहले मुकाबले के बाद स्वदेश लौट गए थे।

शुभमन की चोट को ठीक होने में लग सकता है कम से कम दो महीने का समय

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को शिन (घुटने के नीचे पैर का अगला हिस्सा) की गंभीर चोट लगी है जिसके कारण वह कम से कम दो महीने तक क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। बीसीसीआइ के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह तय है कि गिल इंग्लैंड के खिलाफ नाटिंघम में चार अगस्त से शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सूत्र ने कहा, 'शुभमन को शिन स्ट्रेस फ्रेक्चर है, जिसके कारण वह कम से कम दो हफ्ते तक बाहर रहेंगे। इसके कारण वह अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रिहैब पूरा करने के बाद सितंबर में होने वाले अंतिम दो टेस्ट में फिट होने के लिए भी अधिक समय नहीं है।' समझा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल में साउथैंप्टन में संपन्न विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान यह चोट बढ़ गई। भारत ने यह मुकाबला आठ विकेट से गंवाया था।

गेंदबाजों को जल्दी थकते हुए देखना दुखद : कपिल देव

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि आज के जमाने के गेंदबाजों को चार ओवर तक गेंदबाजी करने के बाद थकते हुए देखना दुखद है। कपिल ने कहा, 'आज का क्रिकेट बेसिक है, आपको या तो बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी। हमारे समय में आपको सब करना होता था। क्रिकेट अब बदल गया है। कई बार मुझे यह देखकर दुख होता है कि खिलाड़ी महज चार ओवर तक गेंदबाजी करने के बाद थक जाते हैं। मैंने सुना है कि इन्हें तीन या चार ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं करने दिया जाता है।'

उन्होंने कहा, 'हमारे समय में हम लोग यह नहीं कह पाते थे कि यह सही है और यह गलत है। अगर आखिरी बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करने आता था तो हमें कम से कम 10 ओवर फेंकने पड़ते थे। आज के दौर में इनके लिए यह चार ओवर काफी होते हैं जिससे हमारे जमाने के खिलाड़ियों को काफी अजीब लगता है।' आलराउंडर हार्दिक पांड्या फिटनेस के कारण गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और वह सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं।

गए थे वजन कम करने लेकिन बन गए भाला फेंक चैंपियन

पदक के दावेदार
TOKYO 2020
21 दिन शेष

अनिल भारद्वाज • गुरुग्राम

13 साल के जिस लड़के को शरीर का वजन कम करने के लिए जिम भेजा गया था वही, एक दिन दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की कतार में शामिल हो जाएगा यह न उस लड़के ने सोचा था और न ही उसके परिवार ने। हालात यह थे कि उसके परिवार में किसी को यह पता ही नहीं था कि भाला फेंक भी कोई खेल है।

हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की। जिन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 67 साल बाद भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था। नीरज के चाचा भीम कहते हैं कि वह किसान परिवार से है लेकिन, जब नीरज ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता तो उनके जानने वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ओलंपिक पदक भी दिलाएगा। आज वही खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पदक के बेहद करीब माना जा रहा है। इन दिनों नीरज अपनी तैयारी को पुख्ता बनाने के लिए विदेश में पसीना बहा रहे हैं। नीरज के चाचा बताते हैं कि आयु की तुलना में नीरज का शरीर बहुत भारी था। इसी कारण उन्हें जिम में भेजा गया जिससे कि उनका शरीर फिट हो सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जिम बंद हो गए। तो वह स्टेडियम में वाक करने लगा। यहीं पर उनकी मुलाकात एथलीट जयवीर और मोनू से हुई तो उन्होंने नीरज को एथलीट बनाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने नीरज का एथलीट संबंधी अलग-अलग स्पर्धा में ट्रायल लिया। इसी समय नीरज को भाला थमाया गया। यहां पर नीरज ने बिना प्रशिक्षण के जब पहली बार लंबी दूरी तक भला फेंका जिसे वहां पर खड़े अन्य लोग भी देखकर हैरान हो गए। यहीं से तय हुआ कि नीरज अब भाला फेंक स्पर्धा में खेलेगा। जब पहली बार 2012 में नीरज राज्य स्तरीय जूनियर चैंपियनशिप खेलने गए, तो उन्होंने वहां पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने एथलीट दिग्गजों को चौका दिया। प्रदेश में स्वर्ण पदक जीतने वाले बालक को जब इसी वर्ष जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भेजा गया तो स्वर्ण पदक झटक लाया।

चाचा भीम कहते हैं कि उनके इस प्रदर्शन से परिवार हैरान था, क्योंकि जिस तरह से नीरज का वजन था उससे कोई नहीं कहता था वह एक दिन ऐसे पदक जीतेगा। परिवार ने नीरज को अच्छा प्रशिक्षण दिलाने के लिए उन्हें 8000 रुपये का भाला खरीदकर दिया। भाला महंगे थे लेकिन, परिवार किसान होने के कारण वह अपने बच्चे पर अधिक खर्च नहीं कर पा रहे थे लेकिन, परिवार का हर सदस्य चाहता था कि वह आगे खेले। वर्ष 2016 में जब नीरज को जूनियर विश्व चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना था। उनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन, पदक की आशा नहीं थी क्योंकि यूरोप देशों के खिलाड़ियों का दबदबा कायम था लेकिन, भारत के उभरते स्टार ने सबको चौका दिया और उन्होंने 86.48 मीटर दूरी पर भाला फेंकने के साथ नया विश्व रिकार्ड बनाया। वह रिकार्ड भारत के नाम आज भी है। यहीं से नीरज के खेल जीवन का बदलाव आया और उसके बाद वह आगे बढ़ता गया।

अभी हाल में पटियाला में खेली गई ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता में उन्होंने अपना पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ते हुए 88.7 मीटर भाला फेंक कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नीरज का यही प्रदर्शन उन्हें पदक की दौड़ में शामिल करता है। रियो ओलंपिक में 90.3 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले जर्मन एथलीट थामस रोहलर टोक्यो में नहीं खेलेंगे। नीरज का कहना है कि थामस के हटने या नहीं हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पांच साल के अंतराल के बाद दुनिया के नए खिलाड़ी आ रहे हैं जो कड़ा मुकाबला करेंगे। अच्छा प्रदर्शन करने पर ही पदक हाथ में आएगा। यह सब उस दिन पर निर्भर करेगा जिस दिन मुकाबले होंगे, शायद मैं राष्ट्रीय रिकार्ड को वहां पर तोड़ दूं।

नीरज की उपलब्धियां

वर्ष	चैंपियनशिप	दूरी	पदक
2016	जू. विश्व चैंपियनशिप	86.48 मीटर	स्वर्ण
2017	सी. एशियन चैंपियनशिप	85.23 मीटर	स्वर्ण
2018	कामनवेल्थ गेम	86.47 मीटर	स्वर्ण
2018	एशियाई खेल	88.06 मीटर	स्वर्ण



नीरज चोपड़ा • फाइल फोटो, रायटर

नीरज का रिकार्ड
88.07 मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में फेंका था

विश्व रिकार्ड
104.80 मीटर दूर भाला फेंककर जर्मनी के उवे होन ने विश्व रिकार्ड बनाया था। उवे वर्तमान में भारतीय भाला फेंक टीम के कोच भी हैं

इनसे मिलेगी चुनौती
97.76 मीटर दूर जर्मनी के जोहानेस वेटर ने विश्व कांटिनेंटल टूर-2020 में भाला फेंका था।

ओलंपिक के लिए
90 मीटर से अधिक की दूरी पर आ सकता है ओलंपिक में पदक

जोकोविक, फेडरर व ओसाका के नाम ओलंपिक प्रवेश सूची में

टोक्यो ओलंपिक डायरी

विंबलडन, एपी : सर्बिया के नोवाक जोकोविक, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और जापान की नाओमी ओसाका के साथ आस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी टोक्यो ओलंपिक की प्रवेश सूची में शामिल हैं, जिसकी घोषणा गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) ने की। आइटीएफ ने कहा, 'प्रवेश सूची में अब भी बदलाव हो सकता है।'

फेडरर ने पिछले सप्ताहांत कहा था कि वह 11 जुलाई को विंबलडन के खत्म होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि वह जापान जाना चाहेंगे या नही।

जोकोविक ने स्पष्ट कर दिया है कि वह गोल्डन स्लैम पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसे 1988 में स्टेफी ग्राफ ही पूरा कर पाई थी जब उन्होंने एक ही साल में चारों ग्रैंडस्लैम जीतने के अलावा ओलंपिक में सिंगल्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता था।

जोकोविक इस साल फरवरी में आस्ट्रेलिया ओपन और पिछले महीने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। जबकि विंबलडन में उनका विजयी अभियान जारी है और यूएस ओपन का होना अभी बाकी है। ओलंपिक के साथ ओसाका की प्रतियोगिताओं में वापसी होगी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा ब्रेक लेने के लिए वह फ्रेंच ओपन के पहले दौर के बाद हट गई थी। दो बार के गत चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे भी सूची में शामिल हैं जिन्हें विशेष छूट दी गई क्योंकि जिन खिलाड़ियों की रैंकिंग सीधे प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं है उनमें उन्होंने सबसे अधिक ओलंपिक और ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं।

दर्शकों के प्रवेश पर असमंजस बरकरार : ओलंपिक शुरू होने में मात्र तीन सप्ताह का समय रह गया है और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 2 जुलाई, 2021

हसीन दिलरुबा तापसी

मुलाकात



तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'हसीन दिलरुबा' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कुछ समय पहले ही तापसी रूस में छुट्टियां बिताकर स्वदेश लौटी हैं। इस फिल्म, उनकी छुट्टियों और इंटरनेट मीडिया पर बेबाक बयानों को लेकर उनसे बातचीत के अंशः

आप रूस में छुट्टियां बिताकर लौटी हैं। उस ट्रिप पर आपने खूब साड़ियां पहनीं, जिसने लोगों का ध्यान खींचा...
मुझे साड़ियां पहनना पसंद है। काटन और मलमल की बहुत सी साड़ियां मेरे पास हैं। मुझे साड़ी को थोड़ा ट्विस्ट करके पहनना अच्छा लगता है, जैसे टी-शर्ट के साथ या क्राप टाप और स्नीकर्स के साथ जो लुक आता है, वह मुझे पसंद है। मैंने विदेश में साड़ियां पहनीं, इसलिए लोगों का ध्यान गया होगा। 'हसीन दिलरुबा' में मैंने साड़ियां पहनी हैं। साड़ी आकर्षक परिधान है।

'हसीन दिलरुबा' आपकी पहली फिल्म है, जो ओटीटी पर रिलीज हुई है। बाक्स आफिस का प्रेशर नहीं होगा?
हां, मेरे लिए डिजिटल प्लेटफार्म का यह पहला अनुभव है। बाक्स आफिस की चिंता होती है, पर वो इस बार नहीं है। रिलैक्स्ड हूं।

आप इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं। फिल्म जब दूसरी अभिनेत्रियों के पास से होकर आपके पास आती है, तब उसे लेकर क्या सोच होती है?
जिनकी यह फिल्म है, उनको शायद मैं इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं लगी, लेकिन खुद में मैं माइंड ब्लोइंग हूं। अक्सर इस तरह के किरदार में मुझे लेने के लिए मेकर्स सोचते नहीं हैं। थोड़ा सा सेंशुअस किरदार था। मेरे लिए वही चीज मजेदार रही कि मुझे अपना वह साइड देखने को मिल रहा था, जो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कर सकती हूं।

फिल्म में सुशील लड़की की बात की गई है। आपके लिए सुशील लड़की की परिभाषा क्या है?
मैं खुद को बहुत सुशील समझती हूं, भले ही दूसरों को ऐसा न लगे। आपके लिए जो अच्छा है, वह किसी दूसरे को बुरा लग सकता है। सुशील शब्द को लेकर भी वैसा ही है। फिल्म में जो मेरा रानी का किरदार है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन दूसरे कामों में वह परफेक्ट है। वह खुद को सुशील समझती है।

फिल्म में प्यार में पागलपन दिखाया गया है। असल जिंदगी में इसपर क्या कहेंगी?
प्यार में पागलपन की बातें हमने खबरों में पढ़ी हैं। देखा जाए तो जीवन में करने को बहुत कुछ है। सिर्फ प्यार प्राथमिकता नहीं रह जाता है। प्यार में मैं इतना पागल नहीं हो सकती हूं कि किसी और के लिए खुद को नुकसान पहुंचाऊं।

इंटरनेट मीडिया पर बेबाकी से बात कहने के साथ ही मर्यादा को बनाए रखना कितना जरूरी मानती हैं?
मैं दिल्ली की हूं। बातों को खुलकर कहने में पीछे नहीं रहती, लेकिन परवरिश मायने रखती है। हम जो होते हैं, उसमें पढ़ाई-लिखाई, घर वालों की शिक्षा का योगदान होता है। मुझे यह बात सिखाई गई है कि किस परिस्थिति में कैसे बर्ताव करना है। दूसरी अहम बात है कि फैंस स्टार को आदर्श की तरह देखते हैं। उनकी उम्मीदों का मान रखना आपपर निर्भर करता है।

प्रियंका सिंह

चर्चा में

साल 1984 में रिलीज राज एन सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाक्सर' में मिथुन चक्रवर्ती ने बाक्सर की भूमिका निभाई थी, जो जेल जाने के बाद बाक्सिंग सीखता है। छह बार की विश्व चैंपियन और ओलंपियन बाक्सर मैरी काम के सफर को उमंग कुमार ने बखूबी पर्दे पर उतारा। उन्होंने फिल्म में महिला खिलाड़ी के साथ होने वाले भेदभाव को संजीदगी से पेश किया। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों का प्यार मिला। मैरी काम के किरदार के लिए प्रियंका चोपड़ा ने जीतोड़ मेहनत की थी। प्रियंका का कहना था कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने सीमाओं में रहने से इन्कार कर दिया। धान उगाने वाले किसान की बेटी होने के बावजूद बाक्सर बनने का ख्वाब देखा। इस फिल्म से दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम सभी पर बंदिशें लगी रहती हैं। वैसा ही हुआ भी। 'मैरी काम' को पापुलर फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया।

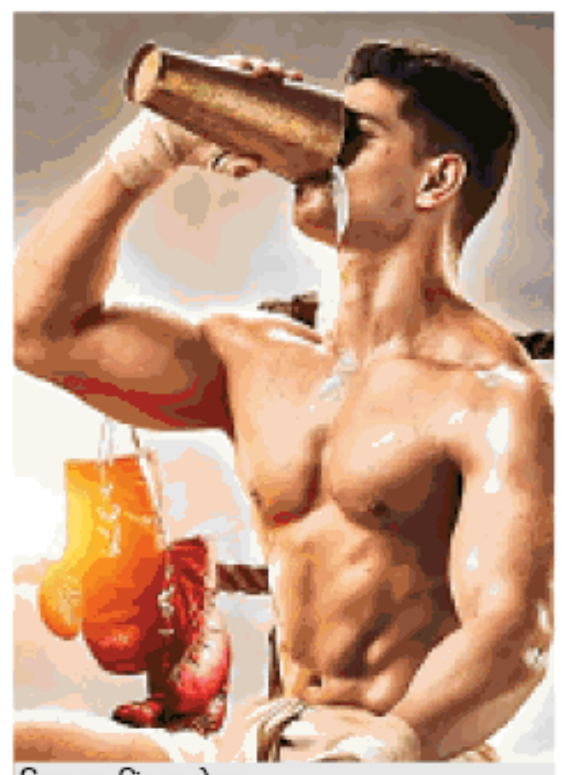
कहानियां हैं कई: आगामी दिनों में फादर आफ इंडियन बाक्सिंग कहे जाने वाले मुक्केबाज कैप्टन हवा सिंह की बायोपिक, राकेश ओमप्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म 'तूफान', फिल्म 'अपने' की सीक्वल 'अपने 2', साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अभिनीत फिल्म 'लाइगर', दो पार्ट में बनने वाली विकास बहल निर्देशित और टाइगर श्राफ अभिनीत फिल्म 'गणपत' बाक्सिंग पर आधारित होगी। शाहिद कपूर भारतीय मुक्केबाज डिंग्को सिंह की बायोपिक से अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वह फिल्म किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पाई। दो खिलाड़ियों के बीच रिंग में खेले जाने वाले इस खेल को बायोपिक व फिक्शन दोनों ही जानर में सेट करने की संभावनाएं होती हैं।

बतौर एक्टर बदल जाता है सोचने का तरीका: अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली फिक्शन फिल्म 'तूफान' में बाक्सर का रोल करने को लेकर फरहान अख्तर कहते हैं कि जब किसी खेल पर फिल्म बनती है, तब हीरो के जेहन में घूमने लगता है कि मेरी एंट्री कैसी होगी, प्रोमो कैसे एडिट होगा, लेकिन जब रिंग में उतरकर बाक्सिंग करनी पड़ती है तो ये बातें हवा हो जाती हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। यह शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें दिमाग लगाना है। अंतर यह है कि इसमें तेजी से अपने शरीर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। मेरा मानना है कि अगर किसी भी काम को करने की वजह सही हो तो अपने आप वह शक्ति भीतर आ जाती है। मैंने दिन में तीन-तीन घंटे ट्रेनिंग की, लेकिन उसकी थकान महसूस नहीं हुई।

इमोशन और जुनून दोनों: हमारे देश में क्रिकेट से प्रेम करने वाले दर्शकों के बीच बाक्सिंग पर फिल्म लाना किसी रिस्क से कम भी नहीं होता है। 'अपने' फिल्म में बाक्सिंग दिखा चुके निर्देशक अनिल शर्मा 'अपने 2' में करण देओल से बाक्सिंग कराएंगे। वह कहते हैं कि जब मैंने 'अपने' में बाक्सिंग को रखने का फैसला किया था, तब लोगों ने मुझे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'बाक्सर' का उदाहरण दिया था, जो खास सफल नहीं हुई थी, लेकिन मुझे यह खेल पसंद है। इस खेल में इमोशन और जुनून दोनों होते हैं। हिंदी फिल्में इन्हीं दो भावनाओं पर चलती हैं। लोगों ने हालीवुड की 'राकी' सीरीज, मुहम्मद अली पर बनी व विल स्मिथ अभिनीत फिल्म 'अली' देखी हैं। बाक्सिंग पर देश में भी फिल्में बननी चाहिए। 'अपने 2' में भी बाक्सिंग का खेल होगा। मैंने खुद फिर से बाक्सिंग सीखनी शुरू कर दी है। फिल्म 'अपने' के वक्त भी पंचिंग बैग लगाकर प्रैक्टिस किया करता था, खेल के नियम सीखे। बाक्सिंग की ट्रेनिंग खुद करने से फायदा यह होता है कि बाक्सर की मानसिकता आपके भीतर आ जाती है। बाक्सर के अंदर पावर और विनम्रता दोनों होती है। बाक्सिंग रिंग ही बाक्सर की दुनिया होती है। हमें भी कैमरा उसी के अंदर घुमाना होता है। उतनी सी जगह में इमोशन, फाइट तब सही से कैमरे पर कैप्चर हो पाएंगे, जब मुक्केबाजी करते वक्त आपस में भिड़ने का कोई उद्देश्य होगा। जब ये बातें स्पष्ट होंगी तो इस खेल को शूट करना भी आसान हो जाता है।


फिल्म लाइगर का पोस्टर


फिल्म तूफान में मुक्केबाज बने फरहान अख्तर


फिल्म हवा सिंह का पोस्टर

फिल्मों में बढ़ रहा मुक्केबाजी का पंच



क्रिकेट, फुटबाल, हाकी के अलावा बाक्सिंग का खेल भी बालीवुड का पसंदीदा विषय रहा है। 'सुल्तान', 'साला खड़ूस', 'मुक्काबाज', 'मैरी काम', 'ब्रदर्स' जैसी कई फिल्में बाक्सिंग के आसपास बुनी गई हैं। आगामी दिनों में फादर आफ इंडियन बाक्सिंग कहे जाने वाले मुक्केबाज कैप्टन हवा सिंह की बायोपिक, राकेश ओमप्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म 'तूफान', 'अपने 2', साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अभिनीत 'लाइगर', विकास बहल निर्देशित और टाइगर श्राफ अभिनीत 'गणपत' बाक्सिंग पर आधारित होगी। दो खिलाड़ियों के बीच सीमित दायरे में खेले जाने वाले इस खेल को पर्दे पर दर्शाने के लिए जरूरी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं स्मिता श्रीवास्तव और प्रियंका सिंह

खेल की ऊर्जा का एहसास कराना मुश्किल: पर्दे पर रिंग के अंदर बाक्सिंग करते हुए कलाकारों को देखकर कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पर्दे पर दिखाना आसान नहीं होता। 'भाग मिल्खा भाग' के बाद 'तूफान' खेल पर आधारित राकेश ओम प्रकाश मेहरा की दूसरी फिल्म है। राकेश कहते हैं कि बाक्सिंग क्लोज कांटैक्ट वाला खेल है। दो लोगों के बीच की फाइट को फेक नहीं दिखा सकते हैं। बाक्सिंग में लोग एक-दूसरे को मारते हैं। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, उसे वैसे ही शूट करना होता है। खेल वाली कहानियां प्रेरणा देती हैं, उस प्रेरणा को कैमरे के जरिए महसूस कराना निर्देशक के लिए सबसे मुश्किल काम होता है।

बाक्सर बनना चुनौती: पर्दे पर बाक्सर दिखने के लिए कलाकारों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। प्रख्यात मुक्केबाज कैप्टन हवा सिंह की बायोपिक में सूरज पंचोली होंगे। किरदार की तैयारी को लेकर सूरज कहते हैं कि बाक्सर की तरह फिट बाडी बनाने के लिए काफी समर्पण व परिश्रम चाहिए। डाइट, वर्कआउट रूटीन, सोने का पैटर्न सब बदल जाता है। मैंने लाकडाउन से पूर्व हवा सिंह के परिवार के साथ काफी वक्त बिताया था। हरियाणा में उनके घर पर रहा। वह आर्मी में थे। उनके साथियों से जाकर मिला, उनके स्वभाव के बारे में जाना।

बाक्सर के किरदार की तैयारी के बाबत 'मैरी काम' और 'तूफान' फिल्म के अभिनेता दर्शन कुमार कहते हैं कि बाक्सिंग को दूर से देखने और खुद करने में बहुत फर्क होता है। 'मैरी काम' में मैंने प्रियंका चोपड़ा को दूर से दिन में 16 घंटे मेहनत करते देखा था। जब मैंने खुद 'तूफान' में बाक्सिंग की, तब समझ में आया कि यह खेल कितना मुश्किल होता है। असली बाक्सर्स के साथ ट्रेनिंग की है। इस खेल को क्लोज शाट्स में फिल्माया जाता है। ऐसे में कलाकार का बाक्सर की तरह लगना बहुत जरूरी है। बाक्सर की जो बाडी लैंग्वेज 10-15 साल में बनती है, वह हमें कुछ माह में हासिल करनी पड़ती है।

विदेशी ट्रेनर्स और एक्शन डायरेक्टर का बोलबाला: मुक्केबाजी पर बनी फिल्मों में अक्सर ट्रेनिंग के लिए विदेशी ट्रेनर और एक्शन डायरेक्टर का सहारा लिया जाता है। इसकी वजह बताते हुए अनिल शर्मा कहते हैं कि हमारे यहां के एक्शन डायरेक्टर इस खेल की बारीकियों को लेकर अब भी परिपक्व नहीं हैं। विदेश में बचपन से ही बच्चों को बाक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया के एक्शन डायरेक्टर बाक्सिंग में माहिर होते हैं। हालांकि अब बाक्सिंग का खेल हमारे देश में भी लोकप्रिय हो रहा है, ऐसे में जल्द ही वक्त आएगा, जब विदेश से ट्रेनर्स नहीं लाने पड़ेंगे।

साल 2001 में मुक्केबाज मुहम्मद अली की बायोग्राफिकल फिल्म 'अली' में अभिनेता विल स्मिथ को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दे चुके अमेरिकी ट्रेनर डोरेल फास्टर ने फरहान को भी ट्रेनिंग दी है। वह कहते हैं कि किसी एक्टर को एक नवोदित खिलाड़ी की तरह सिखाना पर्दे पर मुक्केबाजी को वास्तविकता में दिखाने का सबसे सरल तरीका है। हालांकि अभिनेता की मानसिकता को एक खिलाड़ी की मानसिकता में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। रिंग में विरोधी के सामने स्थिर और सीधा नहीं खड़ा होना चाहिए, इससे विरोधी के लिए हमला करना आसान हो जाता है। रिंग में अपना स्थान बदलते रहने से विरोधी को भी हमला करने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है। प्रशिक्षण के बाद फरहान अख्तर अब पेशेवर बाक्सर की तरह रिंग में लड़ सकते हैं।

सीखनी पड़ी मुक्केबाजी



एक अच्छी फिल्म की तलाश में अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने 'मुक्काबाज' की स्क्रिप्ट अपनी बहन के साथ मिलकर लिखी थी। अनुराग कश्यप को जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तब वह निर्देशन के लिए राजी हुए, पर उनकी शर्त थी कि विनीत ही मुक्काबाज बनेंगे। विनीत कहते हैं कि फिल्म का बजट कम था। हम विदेश से ट्रेनर नहीं मंगा सकते थे। जितने पैसों में वह ट्रेनिंग देते, उतना तो फिल्म का बजट था, लिहाजा मैंने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। मैं पटियाला के कोचिंग सेंटर में पहुंचा। वहां सालभर ट्रेनिंग ली। हड्डी-पसली टूटी, लेकिन मैं डटा रहा।

यादों का झरोखा

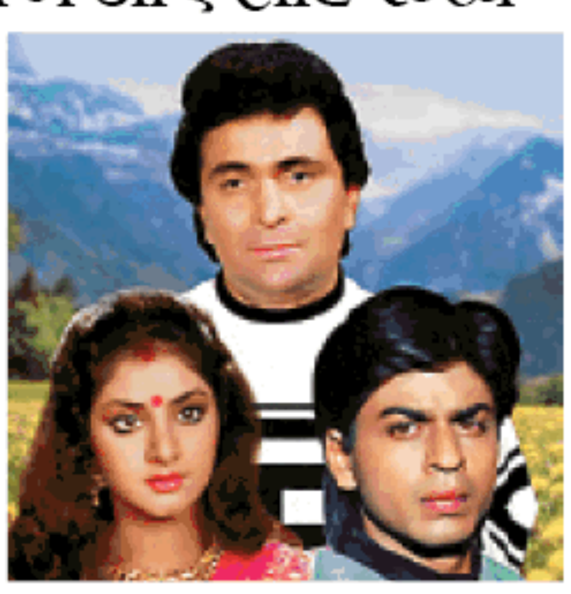
जिस फिल्म के लिए डेट नहीं थी उसी से सिनेमा में आए शाह रुख



साल 1992 में रिलीज फिल्म 'दीवाना' से शाह रुख खान ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। आज वह ऊंचाई हासिल कर चुके हैं। उनके अलावा स्वर्गीय ऋषि कपूर और दिव्या भारती ने फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया साझा कर रहे हैं फिल्म के निर्माता गुड्डू धनोआ...

प्रोड्यूसर शबनम कपूर के कहने पर मैंने उनके साथ दक्षिण भारत में जाकर निर्देशक एस ए चंद्रशेखर की करीब 10 फिल्में देखीं। उसमें से हमें तमिल फिल्म 'वसंत रागम' काफी पसंद आई। वापस लौटने के बाद शबनम ने फोन करके इस फिल्म को हिंदी में बनाने की योजना मुझे बताई। मैंने शबनम से कहा कि आप 'इंसाफ की देवी' और 'बेगम साहिबा' बना रही हैं, यह फिल्म मुझे बनाने दें। वह इसके लिए राजी हो गईं। फिर बतौर प्रोड्यूसर मैंने इसमें अपने दोस्त तथा शबनम के पति ललित कपूर और राजू कोठारी को साथ लिया। पहले हम इस फिल्म को ऋषि कपूर, दिव्या भारती और अरमान कोहली के साथ बनाने वाले थे। निर्देशन के लिए हमने एस ए चंद्रशेखर को चुना था। उन दिनों मैं अपने फुफेरे भाई धर्मेंद्र के बेटे बाबी देओल की लांच फिल्म 'बरसात' का प्रोडक्शन संभाल रहा था। उसी सिलसिले में मैं संगीतकार नदीम-श्रवण को धर्मेंद्र भाई के घर बैठकों के लिए ले जाता था। एक दिन रास्ते में मैंने नदीम-श्रवण से अपनी फिल्म के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी।

अरमान कोहली फिल्म 'इंसाफ की देवी' में भी काम कर रहे थे। उसी दौरान शबनम जी और अरमान के बीच कुछ अनबन हुई। शबनम के पति ललित मेरी फिल्म से जुड़े थे, इसलिए अरमान ने दोनों फिल्में छोड़ दीं। उसके बाद मैंने शेखर कपूर (फिल्मकार) से फिल्म के हीरो के बारे में बात की। उन्होंने शाह रुख खान के नाम का सुझाव दिया। शाह रुख उन दिनों दिल्ली में रहा करते थे। उन्हें फोन करके इस फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया। इसी बीच निर्देशक एस ए चंद्रशेखर ने भी इस फिल्म का निर्देशन करने में असमर्थता जता दी। मैंने और राज कंवर ने 'घायल' के सेट पर साथ काम किया था।



इस फिल्म के निर्देशन के लिए पूछने पर वह तुरंत राजी हो गए। बतौर निर्देशक उनकी भी यह पहली फिल्म थी।

जब हम शाह रुख से मिलने दिल्ली गए तो उन्होंने डेट्स न होने का हवाला देते हुए फिल्म करने से इन्कार कर दिया। उनका जवाब सुनकर हम चौंक गए? उस समय उनके पास 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'दिल आशना है', 'चमत्कार', 'कभी हां कभी ना' और राकेश रोशन की 'किंग अंकल' मिलाकर पांच फिल्में थीं। फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने कहानी सुनी। शाह रुख ने कहा कि मुझे फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसके लिए डेट्स मैं किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कैंसिल होने पर ही दे पाऊंगा। हम इस पर राजी हो गए। इस फिल्म के लिए उनकी स्वीकृति मिलने का दूसरा कारण ऋषि कपूर थे। शाह रुख उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं। हम फिल्म की तैयारियां कर रहे थे तभी शाह रुख ने बताया कि 'राजू बन गया जेंटलमैन' का शूट कैंसिल हो गया है। 20-25 दिनों का वक्त है, क्या शूटिंग शुरू कर सकते हैं। हमने फटाफट सारी योजना तैयार की और शूटिंग शुरू हो गई।

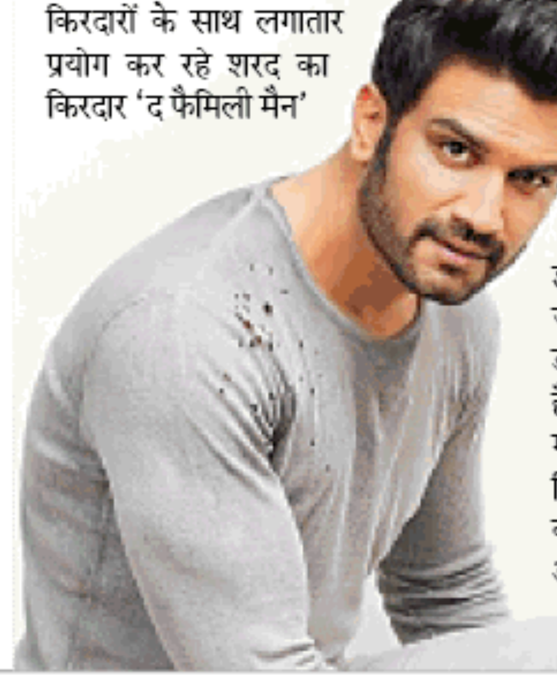
फिल्म का अंतिम शेड्यूल ऐसी दीवानगी...गाने की शूटिंग का था, जिसे शिमला में फिल्माया जाना था। इस गाने की शूटिंग से पहले ही फिल्म के अन्य गाने रिलीज हो चुके थे और सुपरहिट रहे। हम जब इस गाने की शूटिंग के लिए शिमला गए तो वहां की टैक्सियों में हमारी फिल्म के गाने खूब बज रहे थे। इस गाने की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती को 104 डिग्री बुखार था। फिर भी उन्होंने हमें नुकसान से बचाने के लिए शूटिंग की। संयोग देखिए, जिस फिल्म के लिए कभी शाह रुख के पास डेट्स नहीं थीं, उनकी वही फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई। उसके बाद मैंने भी कई हिट फिल्में बनाईं और निर्देशित कीं।

दीपेश पांडेय

मेरी बात

सबसे मुश्किल होते हैं साधारण किरदार

फिल्मों और डिजिटल प्लेटफार्म दोनों पर शरद केलकर लगातार प्रयोगात्मक किरदारों को तरजीह दे रहे हैं। वेब सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 2' में अरविंद के किरदार में उन्हें पसंद किया जा रहा है। उनकी आगामी फिल्मों में अजय देवगन अभिनीत 'भुज- द प्राइड आफ इंडिया' और 'देजा वू' शामिल हैं। अपने डेढ़ दशक के करियर और प्रोजेक्ट्स को लेकर बदलती पसंद पर उन्होंने साझा की दिल की बातें...



सादगी अच्छी लगी: किरदारों के साथ लगातार प्रयोग कर रहे शरद का किरदार 'द फैमिली मैन' वेब सीरीज में बहुत सादगीपूर्ण है। वह बताते हैं, 'शो में मेरे किरदार अरविंद की एक अलग कहानी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने इस शो का पहला सीजन किया था तो मेरे पास ज्यादातर निगेटिव किरदार आ रहे थे। मुझे लोगों को अपना एक नया रूप दिखाना था कि मैं साधारण और सादगी वाले किरदार भी निभा सकता हूं। इस शो में मुझे वो मौका मिला। इसके निर्देशक राज एंड डीके (राज निदिमोरू और कृष्णा डीके) जैसे बेहतरीन फिल्ममेकर्स के साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर मौका मिल रहा था तो मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। मेरा किरदार साधारण इंसान है, उसकी लार्जर दैन लाइफ वाली छवि नहीं है। मुझे इसकी सादगी बहुत अच्छी लगी। किरदार जितना साधारण होता है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है।'

डांस और गाने वाले किरदार: अब तक ज्यादातर गंभीर किरदारों में नजर आए शरद डांस और गाने वाले किरदार भी करना चाहते हैं। वह (मुस्कुराते हुए) कहते हैं, 'अगर मौका मिला तो मैं डांस और गाने वाले किरदार भी करना चाहूंगा। वह भी एक्टिंग का एक पहलू है, जिसे छुए बिना मजा नहीं आएगा। हालांकि, डांस के मामले में तो मैं बहुत ही बुरा हूं, लेकिन जरूरत पड़ी तो वह भी सीखूंगा।'

आने वाली फिल्में: फिल्म 'तान्हाजी- द अनसंग वारियर' में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले शरद आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, 'तान्हाजी के बाद मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक और मराठी फिल्म की है। इसके साथ 'भुज- द प्राइड आफ इंडिया' भी है, जो डिज्नी प्लस हाटस्टार पर रिलीज होगी। इसके अलावा हिंदी में एक अन्य फिल्म 'देजा वू' और एक तमिल फिल्म 'अयालान' कतार में हैं।'

चयन की कसौटी: हिंदी सिनेमा में डेढ़ दशक से ज्यादा समय के करियर के बाद प्रोजेक्ट्स को लेकर बदलती पसंद पर शरद कहते हैं, 'मेरे लिए तीन चीजें सबसे अहम होती हैं। पहली, कहानी कैसी है, दूसरी, कहानी में मेरे किरदार की क्या अहमियत है और तीसरी उस किरदार में मैं बतौर कलाकार क्या अलग कर सकता हूं? इन तीनों चीजों के सही बैठने पर ही मैं प्रोजेक्ट स्वीकार करता हूं। मेरी कोशिश हमेशा खुद को किरदार के मुताबिक ढालने की होती है। मेरे किरदार में आपको उसका ही व्यक्तित्व दिखेगा, भले ही शक्ल शरद केलकर की हो। अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोग उसे पसंद करेंगे।'

दीपेश पांडेय





वालमार्ट ने अमेरिका के रोजर्स में खोला पहला स्टोर

वर्ष 1962 में आज ही के दिन वालमार्ट ने अमेरिका के रोजर्स शहर में पहला स्टोर खोला था। वर्ष 2010 में कंपनी ने भारत में प्रवेश किया और 'बेस्ट प्राइस' के नाम से स्टोर खोला। वर्ष 2017 में ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की 77 फीसद हिस्सेदारी खरीदकर देश में एक बड़ा निवेश किया।





देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को किया गिरफ्तार

वर्ष 1940 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विरोध स्वरूप भूख हड़ताल करने पर उन्हें घर भेज दिया गया। इसके बाद वह कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और भतीजे की मदद से देश से बाहर निकल गए।

इंदिरा गांधी और भुट्टो ने किए थे शिमला समझौते पर दस्तखत

वर्ष 1972 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1971 में हुई लड़ाई के दौरान 90 हजार से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाए जाने के बाद पड़ोसी देश घुटनों के बल बैठाने पर मजबूर हुआ था। इसमें तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिये कश्मीर से जुड़े विवाद सुलझाएंगे। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र दखल नहीं दे सकता है। समझौते पर भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे।



इधर-उधर की

गलती से सूंघ लिया तेज नशे वाला खूबसूरत फूल

कनाडा, एजेंसी : हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी हो, जरूरी नहीं है। कनाडा की राफेला वेमैन अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक पीले रंग का खूबसूरत फूल दिखाई दिया। फूल के बारे में बिना कुछ जाने उन्होंने उसे सूंघा और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर भी डाल दिया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब उन्हें फूल की सच्चाई पता चली। इस फूल को एंजल्स ट्रंपेट कहा जाता है, जिसमें स्कोपोलामाइन रसायन होता है, जिसे दुनिया के सबसे डरावने नशे में शुमार किया जाता है। वेमैन ठीक हैं और फूल सूंघकर हुए पछतावे वाला उनका वीडियो वायरल हो रहा है।



तबीयत खराब होने पर पता चली सच्चाई। इंटरनेट मीडिया

एक माह तक कोरोना को पास नहीं फटकने देगा नैनो सैनिटाइजर

जागरण विशेष

आइआइटी हैदराबाद की टीम ने हाथों, मास्क और सतह के लिए तैयार किए स्वच्छता उत्पाद

हिमांशु अस्थाना • वाराणसी

म्यूटेट (परिवर्तित) होते कोरोना वायरस को देखते हुए विज्ञानी सैनिटाइजर को भी अपडेट कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर डा. ज्योत्सेंदु गिरि की अगुआई में नैनो टेक्नोलाजी पर आधारित किफायती, लेकिन लंबे समय तक प्रभावी सैनिटाइजर और अन्य स्वच्छता (हाइजीन) उत्पाद बनाए गए हैं। ड्यूरोकिया नामक ये उत्पाद कोरोना वायरस के साथ अन्य हानिकारक बैक्टीरिया से भी बचाव करने में सक्षम हैं। गत दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्पाद को लांच किया था और अब ये आनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।



ड्यूरोकिया एच- हैंड सैनिटाइजर



ड्यूरोकिया एस- सरफेस डिसइंफेक्टेंट



बीते दिनों नैनो टेक्नोलाजी पर आधारित सैनिटाइजर को लांच करते केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक • सौजन्य डा. रूबी

24 घंटे तक हाथ धोने की जरूरत नहीं : इन उत्पादों में सरफेस डिसइंफेक्टेंट (सतह विसंक्रमणकारी), हैंड सैनिटाइजर व मास्क डिसइंफेक्टेंट शामिल हैं। शोध टीम में शामिल बनारस की युवा विज्ञानी डा. रूबी सिंह ने बताया कि सरफेस डिसइंफेक्टेंट घर-अस्पताल व अन्य सार्वजनिक व निजी स्थलों में फर्श, दीवारों आदि पर छिड़काव के 60 सेकेंड के भीतर न सिर्फ कोरोना वायरस को खत्म कर देगा, बल्कि इन्हें करीब 35 दिन तक वायरस से सुरक्षित भी रखेगा। हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद 24 घंटे तक हाथों को धोने या दोबारा सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, मास्क डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के बाद मास्क को न धोने की जरूरत है और न बदलने की। मूल खोजकर्ता डा. ज्योत्सेंदु गिरि के अनुसार इनका परीक्षण लैब के अलावा आइआइटी-हैदराबाद के सभी छात्रावासों, मेस (भोजन कक्ष), हेल्थ सेंटर, अस्पताल व विभागों आदि में किया गया। शोध टीम ने पाया कि सरफेस डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव के बाद करीब 35 दिनों तक वहां की दीवारें और फर्श संक्रमण से मुक्त रहे। नैनो टेक्नोलाजी युक्त ये उत्पाद कोरोना के खतरनाक वैरिएंट से 99.99 फीसद तक सुरक्षा देते हैं और इनसे एलर्जी और त्वचा की बीमारियों का खतरा भी नहीं है। तकनीक को गत माह पेटेंट कराने के बाद एक कंपनी कियाबायोटेक के नाम से पंजीकृत कराकर उत्पाद को कम दाम पर बाजार में पेश किया गया। इसमें अब अन्य ई-कामर्स कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं।

नैनो फार्मूलेशन में विशेष किस्म के पालीमर : डा. रूबी ने बताया कि इथेनाल (एल्कोहल) आधारित सैनिटाइजर पर नैनो फार्मूलेशन की कोटिंग की गई है। एल्कोहल सतह पर मौजूद वायरस को फौरन खत्म कर देता है। नैनो फार्मूलेशन खास पालीमर से निर्मित है और इसमें स्पाइक (कील) होते हैं, जो इसे लंबे समय तक सतह से चिपकाए रखते हैं। नैनो फार्मूलेशन धनात्मक विद्युत आवेशित होते हैं, इसलिए वायरस (आमतौर पर ऋणात्मक विद्युत आवेशित) को अपनी ओर खींचते हैं। इसकी ऊबड़-खाबड़ सतह से टकराकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन खत्म हो जाते हैं और वह निष्प्रभावी हो जाते हैं।

बनारस में हुई इंटर तक पढ़ाई, आइआइटी से पीएचडी

डा. रूबी की इंटरमीडिएट तक पढ़ाई बनारस के यूपी कालेज से हुई। बीएससी और एमएससी लखनऊ के बाबू बनारसी दास कालेज से करने के बाद आइआइटी हैदराबाद के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग से पीएचडी की है। उनके पिता डा. अंबिका सिंह रसायनशास्त्र के लेक्चरर हैं।



रूबी सिंह • सौ. स्वयं

मोबाइल से बढ़ रहा बच्चों में मोटापे का खतरा

रहें सतर्क ▶ अमेरिका में हुए एक अध्ययन में सामने आई बात, ज्यादा स्क्रीन टाइम से एक साल में बढ़ जाता है मोटापे का जोखिम

वाशिंगटन, एएनआइ : बदलते सामाजिक परिवेश के साथ मनोरंजन के साधन भी बदल रहे हैं। कभी खेल के मैदान में जुटने वाले बच्चे आज मोबाइल फोन, टैबलेट, टीवी में ही जुटे दिखते हैं। माता-पिता भी कई बार अपनी व्यस्तताओं के चलते उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इसका फायदा उठाकर बच्चे इन गैजेट्स को अधिक समय देने लगते हैं। अब इसे लेकर एक चिंताजनक बात सामने आई है। अमेरिका में हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि नौ से 10 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम यदि ज्यादा हो जाए तो एक साल बाद उनके मोटापे के शिकार होने का जोखिम बढ़ जाता है। यह अध्ययन पीडियाट्रिक ओबीसिटी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

स्क्रीन टाइम का मतलब टीवी, मोबाइल, टैबलेट या किसी अन्य वर्चुअल माध्यम के लिए दिया जाने वाला समय है। यह जानना भी जरूरी है कि मोटापे से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन में पाया गया कि वर्चुअल माध्यम पर दिया जाने वाला प्रति अतिरिक्त घंटा एक साल बाद उच्चतर बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) से जुड़ा हुआ है। बीएमआइ का आकलन व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर किया जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि जिन बच्चों ने टीवी, यूट्यूब वीडियो देखने, वीडियो गेम्स खेलने, वीडियो चैटिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग में ज्यादा समय दिया, उनमें एक साल बाद वजन बढ़ने का ज्यादा जोखिम था। शुरुआत में अध्ययन में शामिल 33.7 फीसद बच्चों को ओवरवेट या मोटा (ओबीस) माना गया और सालभर बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35.5 फीसद हो गया। मोटापा बढ़ने का यह आंकड़ा किशोरवय या वयस्कता की शुरुआत में अनुमानित होता है। अध्ययनकर्ताओं ने नौ से 10 साल की उम्र वाले 11,066 बच्चों के बीएमआइ जेड-स्कोर का विश्लेषण किया। यह स्कोर बच्चों की उम्र व लिंग के हिसाब से समायोजित होता है। इन बच्चों से टीवी, इंटरनेट मीडिया जैसे छह विभिन्न स्क्रीन टाइम के तौर-तरीकों पर सवाल पूछे गए।

यह आया सामने : अध्ययन के मुख्य लेखक यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसोन नगाटा के मुताबिक, स्क्रीन टाइम अक्सर सुस्त या गतिहीन बना देता है और शारीरिक श्रम की गतिविधियां थम सी जाती है। बच्चों के सामने खाने-पीने की चीजों के ज्यादा विज्ञापन आते हैं और स्क्रीन के सामने ओवरइटिंग (जरूरत से ज्यादा खाना) करने लगते हैं। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक यूनिवर्सिटी आफ टोरंटो के सामाजिक कार्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर काइल टी. गैन्सन के अनुसार, शरीर की नकारात्मक छवि और ओवरइटिंग संभवतः इंटरनेट मीडिया के ज्यादा एक्सपोजर के कारण भी हो सकती है। गैन्सन का यह भी कहना है उनके अध्ययन से इस बात सामने आई कि स्क्रीन टाइम किस प्रकार से बच्चों या किशोरों पर प्रभाव डालने लगा है।

वर्तमान में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत : प्रोफेसर नगाटा के मुताबिक, यह अध्ययन कोविड-19 महामारी के पहले का है, लेकिन उसके निष्कर्ष महामारी के समय में बदली दैनिक गतिविधियों के कारण ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। चूंकि इस समय आनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ गया है और खेल-कूद तथा मेलजोल पर बंदिशें हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है।



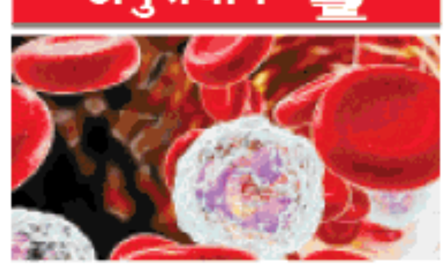
पीडियाट्रिक ओबीसिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है यह शोध। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

यह दिया सुझाव

प्रोफेसर नगाटा यह मानते हैं कि स्क्रीन टाइम शैक्षणिक गतिविधियों और वर्चुअल मेलजोल के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन अभिभावकों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना भी नहीं होना चाहिए कि उनमें गतिहीनता आ जाए या दैनिक रुटीन में आवश्यक शारीरिक श्रम का समावेश नहीं हो। इसके लिए अभिभावकों को बच्चों से बातें करनी चाहिए और स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल के लिए फैमिली मीडिया यूज प्लान भी बनाना चाहिए।

कोविड से ब्लड सेल्स में आ सकता है बदलाव

अनुसंधान



कोरोना ने कई समस्याएं पैदा की हैं। फाइल

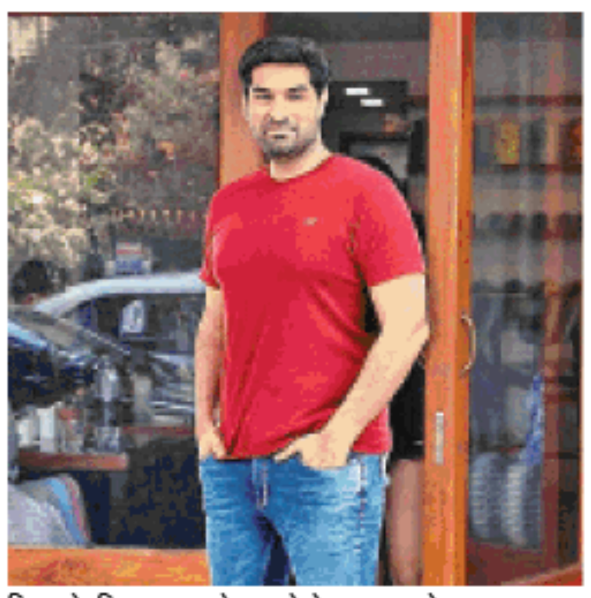
कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते सेहत के मोर्चे पर दूसरी कई गंभीर समस्याएं भी उभर रही हैं। अब एक नए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना संक्रमण ब्लड सेल्स में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। इस संक्रमण की वजह से रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स (कोशिकाओं) के आकार और कठोरता में उल्लेखनीय स्तर पर परिवर्तन की आशंका पाई गई है।

जर्मन शोधकर्ताओं के अनुसार, कुछ मामलों में इस बदलाव का असर कई माह तक रह सकता है। यह हो सकता है कि इसी कारण कुछ लोग संक्रमण से उबरने के बाद भी लंबे समय तक परेशान रहते हैं। कोरोना बीमारी के दौरान आमतौर पर रक्त संचार पर असर पड़ने के साथ ही आक्सीजन आपूर्ति भी सीमित हो जाती है। ये सब ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं की अहम भूमिका होती है। इन पहलुओं पर गौर करने के लिए जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ लाइट (एमपीएल) और फ्राइडरिक एलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स पर यह अध्ययन किया है। एमपीएल के प्रोफेसर जोचेन गक ने कहा, 'हमें संक्रमण के दौरान और इससे उबरने के बाद दोनों स्थितियों में कोशिकाओं में स्पष्ट और दीर्घकालीन बदलाव देखने को मिला है।' बायोफिजीकल पत्रिका में अध्ययन के नतीजों को प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष कोरोना से गंभीर रूप से बीमार पड़े 17 लोगों, संक्रमण से उबरे 14 पीड़ितों और 24 स्वस्थ लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला है। उन्होंने इन प्रतिभागियों से एकत्र 40 लाख से ज्यादा ब्लड सेल्स का परीक्षण किया। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

डेल्ही बेली में कुणाल का किरदार करने वाले थे आमिर खान

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनमें कई बार जो रोल कोई कलाकार करने वाला होता है, वह कुछ वजहों से नहीं कर पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ। उनकी प्रोडक्शन कंपनी तले बनी फिल्म डेल्ही बेली में पहले आमिर खान वह रोल करने वाले थे जो कुणाल रॉय कपूर ने निभाया है। इस फिल्म की रिलीज के 10 साल पूरे होने पर अभिनय देव ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि आमिर को किसी भी रोल के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। इस फिल्म में जो उनका आखिर में एक गाना है आई हेट यू लाइक आई लव यू, उसके लिए मैंने आमिर को एक साल तक मनाया था। फिल्म का पहला कट देखने के बाद आमिर हां कहा था। फिल्म में कुणाल ने जो किरदार निभाया है, वह पहले आमिर करने वाले थे। लेकिन दिक्कत यह हुई की वह उसी समय गजनी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ कुणाल का किरदार था, जिसके लिए मोटा होना था, वहीं दूसरी तरफ गजनी फिल्म के लिए उन्हें सिक्स पैक एब्स बनाने थे। दोनों फिल्में साथ में संभव नहीं थी। उन्होंने गजनी को चुना, क्योंकि उस पर काम शुरू हो चुका था। कुणाल को मैं मोटा करने के लिए रोज लंच के बाद 12 रसगुल्ले खिलाया करता था। उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बड़ी गालियां दी थीं कि तुमने कुणाल को मोटा क्यों कर दिया। मैं अपने सामने बिठाकर उन्हें रसगुल्ले खिलाता था। अब भी यकीन नहीं होता है कि इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं।



फिल्म के लिए कुणाल रोज खाते थे 12 रसगुल्ले।

जन्मदिन तक फिट होने का संकल्प लिया था

यूं तो नए साल पर कई लोग संकल्प लेते हैं कि फिट होना है, जिम जाना है। लेकिन अभिनेता पवन मल्होत्रा ने अपने जन्मदिन के लिए फिट होने का संकल्प लिया था। दो जुलाई को अपने जन्मदिन के मौके पर दैनिक जागरण से बात करते हुए जब वी मेट फिल्म के अभिनेता पवन कहते हैं कि मैं इस बार अपने जन्मदिन पर पंजाब में शूटिंग कर रहा हूं। जहां तक उम्र की बात है तो मैं उतने ही साल का खुद को मानता हूं, जितना अंदर से महसूस करता हूं। कोरोना काल के दौरान मैं काफी वक्त तक बाकी लोगों के तरह ही घर पर रहा हूं। घर बैठे बहुत पेट निकल आया था, जिसे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार यही सोचा था कि जन्मदिन आने से पहले मैं खुद को पहले की तरह फिट कर लूंगा। काफी हद तक इस फिटनेस को पा लिया है, जो चाहता था। मेरी तोंद कम हो गई है। लोग नए साल पर संकल्प लेते हैं, मैंने जन्मदिन के दिन को चुना था। मैं सिक्स पैक एब्स बनाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, लेकिन कलाकार की तोंद नहीं दिखनी चाहिए। फिलहाल पवन पंजाब में अपनी एक और वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे है। वह कहते हैं कि मेरी पिछली वेब सीरीज ग्रहण के ही निर्माता के साथ मैं दूसरी वेब सीरीज शूट कर रहा हूं। कहानी पंजाब में ही सेट की गई है। थ्रिलर शो है। मेरी फिल्में अनफेयर एंड लवली और लव हैकर्स बनकर तैयार है। अनफेयर एंड लवली नवंबर तक रिलीज होगी।



पंजाब में वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं पवन।

प्रोडक्शन वाले मेरे खाने का ख्याल रखते हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता : वरुण बडोला

कई टेलीविजन कलाकार हैं, जिन्होंने फिल्मों की बजाय टीवी पर ही ज्यादा काम किया है। कोशिश : एक आशा और मेरे डैड की दुल्हन जैसे धारावाहिकों में अभिनय कर चुके अभिनेता वरुण बडोला का मानना है कि माध्यम से कलाकार की प्रतिभा को आंका नहीं जा सकता है। एक लाइव चैट के दौरान वरुण ने कहा कि बड़े पर्दे पर न काम करने की बातें करियर के शुरुआती दौर में कुछ समय के लिए परेशान करती थी। मैं टीवी छोड़कर, फिल्में ढूंढने में लग सकता था, लेकिन मेरी परिस्थिति ने कभी मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं एक काम छोड़कर दूसरे की तलाश करूं। उस दौरान कई बड़े निर्देशकों ने मुझे कहा कि तुम फिल्मों में काम करने के लायक हो। लेकिन उन्हीं निर्देशकों ने मुझे फिल्मों में काम नहीं दिया। मेरे लिए काम करते रहना ज्यादा जरूरी रहा है। आज तक एक नजरिया बना हुआ है कि टीवी में एक्टिंग करने की जरुरत नहीं होती है। डायलॉग बोल दो काम हो जाता है। मुझे इस बात से बहुत नफरत है। मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। कुछ तो कारण होगा कि इतना लंबा काम किया है। यह सिर्फ लक से नहीं होता है। टीवी में कैसा भी काम होता हो, मेरा काम यह है कि मैं जिस माध्यम पर काम कर रहा हूं, उसे इज्जत मिले। आसान नहीं रोज के पांच सीन पढ़ कर उसे एक्ट करना। मैंने अपने काम के साथ समझौता कभी नहीं किया है। प्रोडक्शन वाले मेरे खाने-पीने का ख्याल रखते हैं या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी किसी सीन को निपटाता नहीं हूं।



20 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वरुण।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है सोनम की फिल्म ब्लाइंड



सोनम ने ब्लाइंड की शूटिंग स्कॉटलैंड में की है।

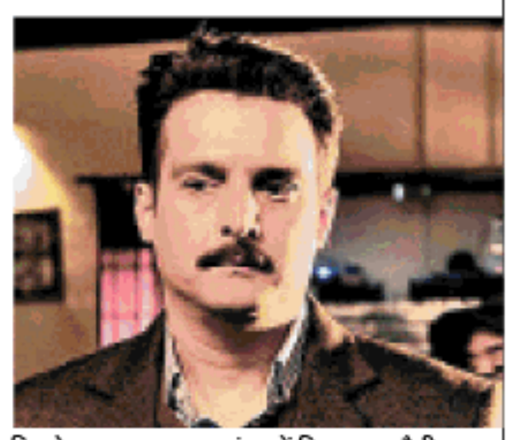
कोरोना की दूसरी लहर मंद होने पर भी थिएटर्स के पूरी क्षमता से खुलने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। थिएटर खुलने पर दर्शक कितनी संख्या में फिल्में देखने पहुंचेंगे, उसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में बॉलीवुड के गलियारों से खबरें आ रही हैं कि सोनम कपूर अभिनीत फिल्म ब्लाइंड सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ब्लाइंड फिल्म साल 2011 में इसी नाम से रिलीज हुई कोरियन फिल्म की हिंदी रीमेक है। स्कॉटलैंड में इस साल फरवरी में सोनम ने फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले सुजॉय इस फिल्म को थिएटर में ही लाने पर विचार कर रहे थे। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के चलते, अब इस फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक तीन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस बारे में बात चल रही है, जहां पर मेकर्स को अच्छी डील मिलेगी, उस प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वैसे सोनम इस फिल्म से पहले एके वर्सेस एके से अपना डिजिटल डेब्यू कर चुकी हैं। हालांकि इस फिल्म में वह मेहमान भूमिका में थीं। उनकी थिएटर में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म द जोया फैक्टर थी।

सभी फोटो इंस्टाग्राम

मजा तो किरदार की तैयारी में ही आता है

हिंदी सिनेमा में बीते करीब तीन दशक से सक्रिय अभिनेता जिमी शेरगिल जल्द फिल्म कॉलर बॉम्ब में पुलिस अधिकारी मनोज के किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म नौ जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। हिंदी के साथ-साथ पंजाबी सिनेमा में भी सक्रिय जिमी इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी प्रयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सभी कलाकारों को एक नया विकल्प दिया है। उनसे हुई बातचीत के अंश।

सात सवाल



पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हिमाचल व नैनीताल में हुई थी कॉलर बॉम्ब की शूटिंग • टीम जिमी

• कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आपके क्या अनुभव रहे?

-मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि दूसरी लहर शुरू होने से पहले ही पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हमने इस फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश और नैनीताल के कुछ हिस्सों में पूरी कर ली थी। हर तरह की सावधानी बरतते हुए बायो बबल के अंतर्गत शूटिंग की गई। बायो बबल में किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होती। सुरक्षा का ध्यान रखने से टीम संक्रमण से बची रही। दूसरी लहर के दौरान मैं अपने घर में ही रहा। पढ़ने का थोड़ा शौक है तो घर पर स्क्रिप्ट और कुछ किताबें पढ़कर पूरा समय बिताया।

• कॉलर बॉम्ब में आपके लिए क्या खास आकर्षण रहा?

-एक्टर के लिए कहानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। काफी वक्त हो गया था, मैंने ऐसी कोई थ्रिलर फिल्म नहीं की थी। इसके अलावा इस फिल्म में युवा निर्माताओं, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर और सह कलाकारों की टीम मुझे काफी दिलचस्प लगी। मुझे लगा कि इस टीम के साथ मुझे कुछ नया अनुभव मिलेगा। यह फिल्म मुझे पिछले साल लाकडाउन के दौरान ऑफर हुई थी, तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी ज्यादा वक्त मिला।

• ट्रेलर में स्कूल के सीन दिखाए गए हैं। शूटिंग करते हुए स्कूल की क्या यादें ताजा हुईं?

-यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। ऐसे में सेट का माहौल ज्यादातर गंभीर हुआ करता था। मैंने खुद भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है, इसलिए जब स्कूल अटेंडेंट ने मुझे पूरा स्कूल दिखाया, तो मेरे लिए वहां की परिस्थितियों को समझना आसान रहा। स्कूल में पहुंचकर आपको अपने बीते दिन याद आना स्वाभाविक है। मुझे हॉस्टल की जिंदगी, सुबह साढ़े चार बजे उठना, फिर मेस में खाने के लिए लाइन लगाना और प्लेग्राउंड जैसी कई चीजें फिर से याद आ गईं।

• करीब तीन दशक के करियर के बाद किसी फिल्म के लिए किरदारों की तैयारी को लेकर अब आपकी क्या प्रक्रिया होती है?

-सबसे ज्यादा मजा तो तैयारी में ही आता है, फिर चाहे वो कोई भी किरदार हो। तैयारी के दौरान आप लेखक, निर्देशक और पूरी टीम के साथ बैठते हैं। अपनी तैयारी से पहले उनकी सुनते हैं और उसके बाद उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। सेट पर एक साथ इतना कुछ हो रहा होता है कि आपको वहां तैयारी करने का वक्त नहीं मिलता। आपने जैसा होमवर्क किया होता है, उसी हिसाब से परफार्म करते हैं। शूटिंग के वक्त दिमाग में कई चीजें रखनी पड़ती हैं, जैसे अगर किसी थ्रिलर की शूटिंग कर रहे हैं, तो बीच में कुछ ऐसा न कर दें जिससे दर्शकों का मजा किरकिरा हो जाए।

• इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में आपने पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है। इसमें क्या कुछ अलग करने की कोशिश की है?

-इस फिल्म में मेरी सह कलाकार आशा नेगी का डायलॉग है कि हर फसाद की जड़ भूतकाल की किसी न किसी बात में होती है। यह डायलॉग मेरे किरदार के लिए भी प्रासंगिक है। इस फिल्म में मेरा किरदार पुलिस अधिकारी के साथ-साथ एक बेटे का पिता भी है। उसके बेटे का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में होता है, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में रोमांचक मोड़ आता है। इस किरदार की व्यक्तिगत जिंदगी ही इसे मेरे पिछले किरदारों से अलग करती है।

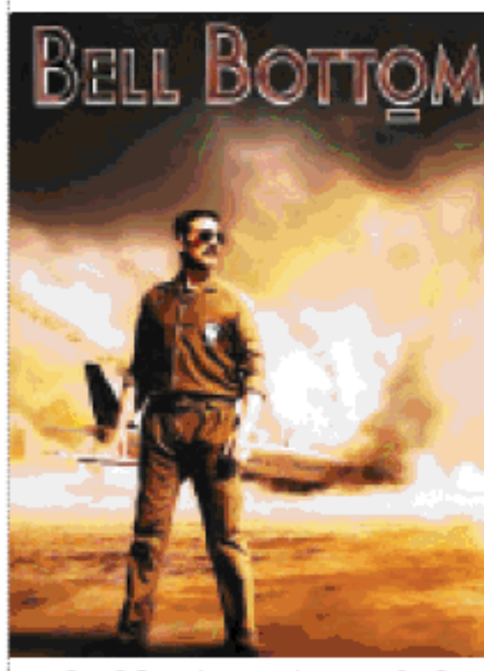
• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। इसे अपने लिए कैसे देखते हैं?

-एक विकल्प और मिल गया है, सिर्फ मुझे ही नहीं सभी कलाकारों को। अगर आपके पास एक साथ दो स्क्रिप्ट आती हैं, जिसमें एक सिनेमाघरों के लिए कॉमर्शियल फिल्म की है और दूसरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें आपको कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। तो इससे कलाकार को पारंपरिक किरदारों से अलग कुछ नया करने का विकल्प मिल जाता है।

• बतौर निर्माता आपने पंजाबी में कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं। क्या हिंदी में भी प्रोड्यूस करने की कोई योजना है?

-वक्त आने पर जरूर करूंगा। काफी सारी चीजों की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आ गई। सब कुछ रुक गया। परिस्थितियां सामान्य होने पर उन पर फिर से काम शुरू होगा। फिलहाल इस दौर में सभी का सकारात्मक रहना ज्यादा जरूरी है।

(दीपेश पांडेय)



रंजीत की फिल्म बेल बॉटम में जासूस की भूमिका निभा रहे हैं अक्षय • इंस्टाग्राम

रंजीत तिवारी संग एक और फिल्म करेंगे अक्षय

हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म बेल बॉटम 27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके अलावा आगामी दिनों में उनकी सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, अतरंगी रे, बच्चन पांडे, रक्षा बंधन और राम सेतु जैसी फिल्में भी रिलीज की कतार में हैं। अब खबर है कि अक्षय कुमार ने फिल्म बेल बॉटम के निर्देशक रंजीत तिवारी के निर्देशन में बनने वाली एक और फिल्म को स्वीकृति दे दी है। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रत्सासन की हिंदी रीमेक होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म के लिए रंजीत तिवारी और अक्षय के बीच हुई बातचीत पर अक्षय ने अपना निर्णय ले लिया है। उन्होंने इस फिल्म को अपनी स्वीकृति दे दी है। अगर परिस्थितियां सही रहीं तो अगस्त से ब्रिटेन में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू किए जाने की योजना है। फिल्म की अभिनेत्री के लिए रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो अक्षय और रकुल प्रीत की जोड़ी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखेगी। तमिल अभिनेता विष्णु विशाल अभिनीत फिल्म रत्सासन की कहानी अरुण कुमार नामक एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अभिनेता बनना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस में रहकर वह एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री (रहस्य) को हल करता है। अक्षय फिलहाल आनंद एल राय द्वारा निर्देशित फिल्म रक्षा बंधन की शूटिंग में व्यस्त हैं।